सूर्योदय 5:34 सूर्यास्त 7:22

आज का तापमान

शिमला	16.4 न्यू	21.8 अधि
धर्मशाला	16.2 न्यू	30.1 अधि

बाजार

सेंसेक्स	76,059
निफ्टी	23,767

सोना 1,42,000 चांदी 2,19,000

भारतेन्दु शिखर

हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू व उत्तराखंड में प्रसारित

आरएनआई नं. HPHIN/2000/02437 | शिमला | शनिवार, 25 जुलाई 2026 | 10 श्रावण, विक्रमी संवत 2083 | वर्ष 28, अंक 91, कुल पृष्ठ 12 | मूल्य : 5 रुपए | info@bhartendushikhar.com | 8894677702

पेपर लीक संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी

रिजिजू बोले- 27 जुलाई को संसद में रखा जाएगा पेपर लीक से जुड़ा बिल, 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान

एजेंसी, नई दिल्ली। पेपर लीक संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। शुक्रवार को संसद में पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक बिल में पेपर लीक के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मामले में 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है।

मोदी ने वीरवार आधी रात 12 बजे छात्रों के लिए वीडियो संदेश जारी किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान करने वाला कानून बनाएगी। पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर 2.56 मिनट का एक वीडियो मैसेज पोस्ट किया। कहा- पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों छात्रों, उनके माता-पिता के लिए पीड़ादायक है। इसलिए पेपर लीक से अब तक, पिछले ढाई महीनों में कई कदम उठाए हैं। गुनहगारों को पकड़ा है, वे जेल में हैं। वहीं, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है, 'सरकार सोमवार को छात्रों से जुड़ा बिल पेश करेगी। प्रधानमंत्री का कहना है कि इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए, अगर कांग्रेस छात्रों के मुद्दों को उठाने के लिए संसद की कार्यवाही में बाधा डालती है, तो वह जाल में फंस जाएगी।'

धर्मेंद्र प्रधान क्रिमिनल शिक्षा मंत्री, इस्तीफा दें : राहुल

राहुल गांधी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान एक अपराधी शिक्षा मंत्री हैं। उन्हें हटाया जाना चाहिए। वे हमारे शिक्षा तंत्र के ध्वस्त होने का प्रतीक हैं। उन्हें जाना ही होगा। उन्हीं की वजह से हजारों लोग बाहर हैं। राहुल ने पैलेट गन से घायल छात्रों से मुलाकात की। वे एक घायल छात्र को साथ में लेकर मीडिया के सामने आए। उन्होंने छात्र के हाथ में लगे घाव को दिखाया। राहुल ने कहा मैं यह बताना चाहता हूं कि यहां खड़ा मेरा भाई उस समय पैलेट गन से घायल हो गया था, जब वह तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध-प्रदर्शन कर रहा था। सरकार का कहना है कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया था। उसकी आंख को नुकसान पहुंचा है और उसकी देखने की क्षमता चली गई है।

राज्यसभा में वंदे मातरम से जुड़ा बिल पेश

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में 'राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026' पेश किया। यह विधेयक राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन से संबंधित है। प्रस्तावित संशोधन के तहत 'वंदे मातरम' के अपमान या उसके गायन में जानबूझकर बाधा डालने को दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया गया है।

सदन चलने दें, राहुल अपने सांसदों को समझाएं : रिजिजू

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन चलने दें, राहुल अपने सांसदों को समझाएं। उन्होंने कहा मैंने आज एक बार फिर केसी वेणुगोपाल से अनुरोध किया है, क्योंकि हम सभी इस बात पर सहमत हैं कि नीट पर चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने देश को भरोसा दिलाया है। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है और चर्चा की मांग की है।

एयरफोर्स की तैनाती स्थायी इलाज नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को नीट परीक्षा में पेपर लीक मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह पेपर लीक रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर बारीकी से नजर रखेगा। कोर्ट ने साफ कहा कि सालों से अस्थायी (तदर्थ) व्यवस्थाओं के सहारे काम करने से दिक्कतें पैदा हुई हैं। अब परीक्षा की पक्की और व्यवस्थित प्रक्रिया बनाई जाए। नीट री-टेस्ट के पेपर पहुंचाने में एयरफोर्स की मदद ली गई थी, लेकिन ऐसे कदम अस्थायी हैं। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच शुक्रवार को इस मामले से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि सरकार यह बताए कि परीक्षा में पारदर्शिता लाने, राधाकृष्णन समिति की सिफारिशें लागू करने और आईआईटी मॉडल अपनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

सीजेपी बोली- प्रधान के इस्तीफे पर समझौता नहीं : आज जवाब देगी सरकार

कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच शुक्रवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक हुई। इसमें सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और सीजेपी की तरफ से सौरभ दास, आशुतोष रांका शामिल हुए। बैठक के बाद सीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा, 'हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सरकार ने मुआवजा देने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने पर सहमति जताई है।' केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि दो घंटे की बातचीत में सीजेपी ने सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगें और परीक्षा प्रणाली में सुधार के 5 सुझाव रखे हैं। सरकार ने इस पर विचार करने के लिए कल तक का समय मांगा है।

एनआईए जांच की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई से इनकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पीआईएल पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें नीट पेपर लीक व उससे जुड़े मुद्दों के विरोध में 20 जुलाई को संसद तक सीजेपी के मार्च की एनआईए से जांच कराने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि किसी मामले की जांच एनआईए को सौंपना केंद्र सरकार का काम है, न की कोर्ट का।

दिल्ली पुलिस का दावा प्रदर्शन करने वालों में 216 के क्रिमिनल रिकॉर्ड

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वालों की पहचान कर रही है। 216 लोग ऐसे मिले हैं, जिनका पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है।

इनमें वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली व बाकी अन्य जिलों के हैं। सूत्रों के मुताबिक, वायरल सोशल मीडिया पोस्ट, सीसीटीवी फुटेज की एफसी, से जांच करने पर इन क्रिमिनल्स की पहचान हुई। जंतर-मंतर पर कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी। पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई थी। कई वीडियोज ऐसे भी आए थे, जिनमें फोर्सेस पर भी हमला हुआ। फोर्सेस पर गलत बल प्रयोग के आरोप भी लगे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस प्रदर्शन की फुटेज और फोटो जांच रहा है। इस बीच, रैपिड एक्शन फोर्स ने भी जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग और पेलेट गन चलाने के आरोपों की जांच शुरू कर दी है।

न्यूज शॉर्ट्स

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 676.24 अरब डॉलर पहुंचा

एजेंसी, मुंबई। विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार तीसरे हफ्ते इजाफा हुआ है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 17 जुलाई को समाप्त हफ्ते में 1.08 अरब डॉलर बढ़कर 676.24 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इससे पिछले हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार 96.4 करोड़ डॉलर बढ़कर 675.16 अरब डॉलर हो गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने शुक्रवार को जारी आंकड़ों में कहा कि 17 जुलाई को समाप्त हफ्ते के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार का प्रमुख घटक माने जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए) 4.55 अरब डॉलर बढ़कर 551.06 अरब डॉलर हो गई है। इस हफ्ते में स्वर्ण भंडार का मूल्य 3.48 अरब डॉलर घटकर 101.75 अरब डॉलर रह गया। वहीं, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 4.4 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.67 अरब डॉलर हो गया।

भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल पर हुई एफआईआर

एजेंसी, नई दिल्ली। भोजपुरी अभिनेत्री अंजना सिंह ने भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और उनकी टीम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अभिनेत्री ने खेसारी पर अपनी फेक तस्वीरें और

वीडियो ऑनलाइन प्रसारित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे लेकर एफआईआर दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि उनकी और उनकी 11 साल की बेटी की आपत्तिजनक एआई-जनरेटेड तस्वीरें और वीडियो ऑनलाइन फैलाए जा रहे हैं। एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए, अंजना सिंह ने भोजपुरी सिंगर-एक्टर खेसारी लाल यादव की टीम से जुड़े लोगों पर यह कंटेंट फैलाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। अंजना ने कहा, 'पिछले कुछ दिनों से मेरी और मेरी 11 साल की बेटी की आपत्तिजनक एआई-जनरेटेड तस्वीरें और वीडियो फैलाए जा रहे हैं।

विपक्ष राजनीति कर रहा, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई : मुख्यमंत्री सैनी

एजेंसी, चंडीगढ़। नीट-यूजी पेपर लीक मामले में विपक्ष के ऊपर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि युवाओं को बरगलाकर राजनीति रोटियां सेंकने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें विपक्ष सफल नहीं होगा। पूरा देख विपक्षी नेताओं को देख रहा है।

शुक्रवार को जिला भाजपा कार्यालय गुरुकमल में आयोजित पार्टी की बैठक में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में साफ तौर पर कहा है कि जो भी दोषी है, उसे सजा मिलेगी। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया है कि वह इस मुद्दे पर चर्चा में सहयोग करें। यह युवाओं से जुड़ा विषय है। मोदी सरकार

◆ **राजनीति नहीं, युवाओं के हित में सहयोग करे विपक्ष**

युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वह युवाओं के मुद्दे को लेकर गंभीर हैं और इस पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लंबे कार्यकाल में कई बार पेपर लीक हुए हैं लेकिन कभी भी इतने कम समय में परीक्षा नहीं हुई। मोदी सरकार ने कम से कम में दोबारा परीक्षा कराई।

जन शिकायतों के निस्तारण में देरी बर्दाश्त नहीं : सीएम धामी

जनसेवा की भावना से काम करें अधिकारी, हर शिकायत का हो समयबद्ध समाधान

एजेंसी, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनीं।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक जन शिकायत का संवेदनशीलता, पारदर्शिता व समयबद्धता के साथ समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनहित और सुशासन के सिद्धांत पर कार्य कर रही है तथा जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक शिकायत का गंभीरतापूर्वक परीक्षण कर नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई करने और

शिकायतकर्ता को समाधान की प्रगति से अवगत कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना सरकार का दायित्व है। सभी अधिकारी जनसेवा की भावना के साथ कार्य करें और जन शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी न होने दें। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आयुक्त गढ़वाल आनंद स्वरूप और आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप को प्राप्त जन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन मामलों का निस्तारण जिला या विभागीय स्तर पर संभव है, उन्हें तत्काल हल किया जाए, जबकि उच्च स्तर के मामलों को शीघ्र संबंधित विभागों को भेजा जाए।

अमेरिका ने भारत समेत 60 देशों पर 10-12.5 प्रतिशत तक लगाया आयात शुल्क

एजेंसी, वॉशिंगटन। अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले सामानों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने की घोषणा की है। यह फैसला शुक्रवार से प्रभावी हो गया।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने जबरन मजदूरी से बने सामान के आयात को लेकर भारत समेत 60 देशों पर यह कार्रवाई की है। इन देशों पर 10 से 12.5% तक अतिरिक्त आयात शुल्क लगाया है। वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत समेत 17 देशों पर 10 प्रतिशत और 43 देशों पर 12.5 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है। अमेरिका ने यह कार्रवाई ट्रेड एक्ट-1974 की धारा 301 के तहत की है। नया अतिरिक्त आयात शुल्क वीरवार-शुक्रवार की दरमियानी रात 12.01 बजे से प्रभावी हो गया है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्रिटेन, कंबोडिया, कनाडा, इक्वाडोर, अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, भारत, इंडोनेशिया, जॉर्डन, मलेशिया, मैक्सिको, पाकिस्तान, श्रीलंका और त्रिनिदाद एवं टोबैगो पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त आयात शुल्क तय किया गया है। वहीं, यूरोपीय संघ, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया और स्विट्जरलैंड के लिए ऐसी दरें तय की गईं, जिन्हें पहले से मौजूद 'मोस्ट-फेवर्ड-नेशन' टैरिफ दरों के साथ जोड़ने पर कुल दर 10 प्रतिशत या 12.5 प्रतिशत हो जाएगी। बाकी 38 देशों के लिए 12.5 प्रतिशत की दर तय की गई।

हिमाचल के लाहौल-स्पीति में पहाड़ी से गिरी चट्टान की चपेट में आई टाटा सूमो, 13 की मौत, दो घायल

भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में शुक्रवार को एक सड़क हादसे में 13 लोगों की जान चली गई। उदयपुर थाना क्षेत्र में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की मुख्य सड़क पर कढ़ूनाला-राहौली के पास पहाड़ी से अचानक गिरी भारी चट्टान की चपेट में एक टाटा सूमो आ गई। हादसे में वाहन में सवार 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हुए हैं।

दोनों घायलों को बचाकर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। हादसे के बाद पुलिस, प्रशासन और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। पुलिस के अनुसार, टाटा सुमो (एचपी-01एम-2210) में चालक सहित कुल 15 लोग सवार थे। वाहन को बीर सिंह चला रहे थे। कढ़ूनाला क्षेत्र में राहौली के पास पहुंचते ही पहाड़ी से अचानक बड़ी

चट्टान नीचे आ गिरी। वाहन सीधे उसकी चपेट में आ गया। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही अधिकांश यात्रियों की मौत हो गई। चट्टान गिरने से वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया। लाहौल-स्पीति की उपायुक्त किरण भड़ाना ने बताया कि हादसे में वाहन में सवार 13 लोगों की मौत हुई है, जबकि दो लोग घायल हैं और उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया है। उन्होंने कहा कि हादसा चंबा जिले के पांगी और लाहौल स्पीति जिले के सीमावर्ती इलाके में हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सभी मृतक चंबा जिले के पांगी क्षेत्र के रहने वाले थे। उन्होंने बताया कि जिला लाहौल की पुलिस चौकी तिंदी और उदयपुर थाना पुलिस मौके पर मौजूद है और आवश्यक कार्रवाई कर रही है। मृतकों की पहचान की जा रही है। पहचान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उन्हें परिजनों को सौंपा जाएगा। यह हादसा ऐसे समय हुआ है, जब प्रदेश में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन और चट्टानें गिरने की घटनाएं बढ़ रही हैं।

सहारनपुर में पटाखा फैक्टरी में विस्फोट 2 की मौत, 2 लापता

एजेंसी, सहारनपुर। सहारनपुर में शुक्रवार शाम पटाखा फैक्टरी में विस्फोट हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि ठेकेदार और और युवक लापता है। धमाका इतना तेज था कि शवों के चीथड़े उड़ गए। एक लाश फैक्टरी से करीब 100 मीटर दूर खेत किनारे मिली। उसके चीथड़े उड़ गए थे। सिर, एक हाथ और दोनों पैर गायब मिले। मौतों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी। आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में जुट गए। सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंच गईं। हादसे में फैक्टरी का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। मामला जिला मुख्यालय से करीब 60 किमी दूर गंगोह थाना क्षेत्र के नया गांव का है।

देहरा के चिड़ियाघर में बनेगा थीमैटिक गार्डन, सरकार ने जारी किए 4 करोड़

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के देहरा स्थित दुर्गेशरण्य अंतरराष्ट्रीय चिड़ियाघर में एक नए थीमैटिक गार्डन का निर्माण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की और इसके निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड (एचपीएसबीबी) के माध्यम से मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक (चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन) को चार करोड़ रुपये जारी किए। यह राशि परियोजना के क्रियान्वयन पर खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना हिमाचल प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण के साथ-साथ पर्यावरण शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान और टिकाऊ प्रकृति आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने की राज्य सरकार की सोच का हिस्सा है। करीब 22,247

◆ **प्रकृति, संरक्षण व पर्यटन को बढ़ावा देगा थीमैटिक गार्डन : सीएम सुक्खू**

वर्ग मीटर यानी लगभग 5.5 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाला यह थीमैटिक गार्डन प्रदेश की विविध वनस्पतियों और प्राकृतिक धरोहर को एक ही स्थान पर देखने और समझने का अवसर देगा।

उन्होंने बताया कि इस परियोजना में फिकेरियम विकसित किया जाएगा, जहां फाइकस प्रजाति के विभिन्न पौधों और उनके पर्यावरण, संस्कृति तथा संरक्षण से जुड़े महत्व को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा एक आर्बोरेटम बनाया जाएगा, जिसमें देशी और विदेशी पेड़ों की अलग-अलग प्रजातियां लगाई जाएंगी। यहां संरक्षण, शिक्षा और वैज्ञानिक अध्ययन से जुड़ी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। परियोजना में एक वॉच टावर भी बनाया जाएगा, जहां से आसपास के प्राकृतिक क्षेत्र का विस्तृत दृश्य देखा जा सकेगा। इसके साथ ही बांस की विभिन्न प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए बैंबूसेटम भी विकसित किया जाएगा, जिसमें बांस के पर्यावरणीय और आर्थिक महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी।

मत करें चिंता, सबकी समस्या पर होगी प्रभावी कार्रवाई : योगी

जनता दर्शन में अपराध व जमीन कब्जे की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

एजेंसी, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन, शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन का आयोजन किया। जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं।

इस अवसर पर उन्होंने समस्या-शिकायत लेकर आए लोगों को भरोसा देते हुए कहा, 'चिंता मत करें, सबकी समस्या पर प्रभावी कार्रवाई कराई जाएगी।' मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि यहां आई शिकायतों का निस्तारण और समस्याओं का समाधान शीघ्रता से कराया जाए। मुख्यमंत्री योगी शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान करीब 150 लोगों से मिले। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर लगी कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे

और एक-एक कर उनकी समस्याओं को सुना, उनके प्रार्थनापत्र लिए। उन्होंने पास में खड़े अधिकारियों को समस्या समाधान हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। अलग-अलग मामलों से जुड़े समस्याओं के निस्तारण के लिए उन्होंने संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र संदर्भित कर निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण निष्पक्ष और समयबद्ध होना चाहिए। अपराध व जमीन कब्जा किए जाने से संबंधी शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी ने पुलिस अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके साथ ही इलाज के लिए आर्थिक मदद से जुड़े प्रार्थना पत्रों पर उन्होंने अस्पतालों के इस्टीमेट की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने को कहा। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि इस्टीमेट मिलते ही सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी। जनता दर्शन में कुछ महिलाएं अपने बच्चों को लेकर आई थीं। मुख्यमंत्री ने इन बच्चों को खूब दुलारा और चॉकलेट के साथ आशीर्वाद दिया।

समीक्षा कांवड़ यात्रा के लिए दिल्ली सरकार की तैयारियां पूरी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की समीक्षा

कांवड़ यात्रा सेवा, श्रद्धा, सामाजिक समरसता का भी देती है संदेश

एजेंसी, नई दिल्ली। सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव की भक्ति में सराबोर होकर हरिद्वार व अन्य पवित्र स्थलों से गंगाजल लेकर दिल्ली पहुंचने वाले कांवड़ियों के स्वागत और उनकी सुविधाओं के लिए दिल्ली सरकार ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में कांवड़ यात्रा को सुगम, सुरक्षित, व्यवस्थित व भक्तिभाव से परिपूर्ण बनाने के लिए विभिन्न विभागों की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। दिल्ली सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कांवड़ यात्रा सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। सावन के दौरान जब लाखों शिवभक्त 'हर हर महादेव' व

'बोल बम' के जयघोष के साथ दिल्ली की सड़कों से गुजरते हैं, तो पूरा वातावरण श्रद्धा व भक्ति से भर उठता है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रवेश करने वाले प्रत्येक कांवड़िए को सम्मान, सुरक्षा और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का संकल्प है कि राजधानी में आने वाला प्रत्येक शिवभक्त स्वयं को सुरक्षित, सम्मानित और अपनत्व से घिरा हुआ महसूस करे। उन्होंने अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों को निर्देश देते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा की तैयारियों में सेवा भाव को केंद्र में रखते हुए आपसी समन्वय के साथ काम किया जाए। उन्होंने कहा कि कांवड़ समितियों को आवश्यक अनुमतियों व सुविधाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की गई है। सरकार का उद्देश्य है कि कांवड़ समितियों को विभिन्न विभागों के चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें आवश्यक सहयोग समयबद्ध तरीके से उपलब्ध हो।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ समितियों के साथ समन्वय मजबूत रखा जाए और उनकी वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए, ताकि शिविरों में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिल सकें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांवड़ शिविरों में साफ-सफाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिविरों में 24 घंटे सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और सफाईकर्मियों की पर्याप्त तैनाती की जाए। मोबाइल शौचालयों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ उनकी गुणवत्ता, नियमित सफाई और रखरखाव पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।

सीएम स्वयं करेंगी शिवभक्त कांवड़ियों का स्वागत

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ियों के स्वागत के लिए दिल्ली के विभिन्न प्रमुख मार्गों और प्रवेश स्थलों पर स्वागत द्वार बनाए जाएंगे। श्रद्धालुओं का पुष्पवर्षा के साथ स्वागत करने की भी व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री स्वयं भी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर शिवभक्त कांवड़ियों का स्वागत करेंगी। उन्होंने कहा कि भगवान शिव के भक्तों के प्रति दिल्लीवासियों की श्रद्धा व सेवा भावना सदैव अद्भुत रही है। इस बार भी सरकार और आम जनता मिलकर कांवड़ यात्रा को श्रद्धा, सेवा और आतिथ्य का यादगार पर्व बनाएगी।

51 शक्तिपीठ भारत की आध्यात्मिक विरासत राष्ट्रीय एकात्मता के सशक्त प्रतीक : राज्यपाल

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि 51 शक्तिपीठ केवल आस्था के केंद्र नहीं, बल्कि भारत की सनातन सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक विरासत और राष्ट्रीय एकात्मता के सशक्त प्रतीक हैं। उन्होंने शक्तिपीठों के इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिक परम्पराओं के वैज्ञानिक अध्ययन, व्यवस्थित प्रलेखन तथा वैश्विक स्तर पर उनके प्रचार-प्रसार की आवश्यकता पर बल दिया।

राज्यपाल श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, कटरा में केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, श्री महाराजा रणबीर सिंह परिसर, जम्मू तथा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित चतुर्दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी 'शक्तिमीमांसा' के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। संगोष्ठी का विषय '51 शक्तिपीठ : भारतीय विरासत के आध्यात्मिक स्तंभ' था। राज्यपाल ने कहा, 'शक्ति केवल आराधना का विषय नहीं, बल्कि सृजन, ज्ञान, करुणा, साहस और राष्ट्रचेतना की शाश्वत ऊर्जा है। भारतीय दर्शन में शक्ति सम्पूर्ण सृष्टि की मूल प्रेरक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है। उन्होंने कहा कि शक्तिपीठ सदियों से भारत की सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ करते आए हैं और ये केवल पूजा-अर्चना के स्थल नहीं, बल्कि भारतीय कला, स्थापत्य, साहित्य, संगीत और लोक परम्पराओं के महत्वपूर्ण केंद्र भी हैं। गुप्ता ने कहा, 'हमारी विरासत केवल स्मारकों के संरक्षण से सुरक्षित नहीं होती, बल्कि उससे जुड़ी परम्पराओं, ज्ञान और सांस्कृतिक मूल्यों को जीवित रखने से सुरक्षित रहती है। आधुनिक तकनीक के माध्यम से शक्तिपीठों का डिजिटल प्रलेखन और दस्तावेजीकरण समय की आवश्यकता है।' उन्होंने कहा कि आज विश्व भारतीय ज्ञान परम्परा, योग, आयुर्वेद और अध्यात्म की ओर आकर्षित हो रहा है।

पेपर लीक पर सरकार का ऐतिहासिक फैसला युवाओं के भविष्य की सुरक्षा का मजबूत संकल्प : जयराम

कहा- युवाओं के हितों पर राजनीति छोड़ विपक्ष सकारात्मक चर्चा में सहयोग दे

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। शिमला से जारी बयान में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक को मंजूरी दिए जाने का स्वागत करते हुए इसे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य की रक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक और निर्णायक कदम बताया है।

उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता किसी भी राष्ट्र की प्रतिभा-आधारित व्यवस्था की आधारशिला होती है। पेपर लीक जैसी घटनाएं न केवल लाखों मेहनती अभ्यर्थियों के सपनों को तोड़ती हैं, बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिह्न लगाती हैं। ऐसे में मोदी सरकार द्वारा कानून को और अधिक सख्त बनाते हुए पेपर लीक माफिया के खिलाफ कठोर दंड का प्रावधान करना यह स्पष्ट संदेश देता है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के लिए अब देश में कोई स्थान नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि संशोधित प्रावधानों के तहत दोषियों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कठोर कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने तथा मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था यह साबित करती है कि केंद्र सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती, बल्कि समस्या की जड़ पर प्रहार करने वाले ठोस और प्रभावी निर्णय लेती है। यह कानून परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वसनीयता को और मजबूत करेगा तथा ईमानदारी से तैयारी करने वाले लाखों युवाओं का विश्वास और अधिक सुदृढ़ करेगा। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल युवाओं के नाम पर लगातार राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि विपक्ष वास्तव में छात्रों और युवाओं के हितों के प्रति गंभीर है, तो उसे संसद और विधानसभाओं में सकारात्मक एवं रचनात्मक चर्चा के माध्यम से व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने में सहयोग देना चाहिए।

लोकतंत्र में कानूनों और नीतियों पर गंभीर विमर्श से समाधान निकलते हैं, जबकि सड़कों पर अराजकता फैलाकर और युवाओं को भ्रमित कर केवल राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को यह समझना चाहिए कि लोकतंत्र की शक्ति सदन में होने वाली सार्थक चर्चा, सुझाव और बहस में निहित है। व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का मार्ग संवाद, सुधार और विधायी प्रक्रिया से होकर जाता है, न कि अराजकता, भ्रामक प्रचार और राजनीतिक उकसावे से। देश के युवाओं को न्याय दिलाने और उनकी मेहनत का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए।

लाहौल हादसे पर जताया दुख, प्रकट की संवेदनाएं

जयराम ने लाहौल में कड़ू नाला के समीप पहाड़ी दरकने से कुल्लू से पांगी जा रही टैक्सी के मलबे में दबने की हृदयविदारक घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगतों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी गहरी संवेदनाएँ शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें, शोक-संतप्त परिवारों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति दें तथा घायलों को शीघ्र पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।

प्रदेश सरकार रोजगार देने में तय प्रक्रिया प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रही : संदीपनी

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की टिप्पणी को लेकर भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि राजस्व मंत्री की ओर से इस तरह की बयानबाजी बंद नहीं हुई तो भाजपा उनका सार्वजनिक घेराव करेगी।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने शुक्रवार को शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान राज्य सरकार की रोजगार नीति, भर्ती प्रक्रिया, छात्र आंदोलनों और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर भी कांग्रेस को निशाने पर लिया। संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी अपनी पार्टी की आंतरिक राजनीति और नाराजगी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की भाषा और बयान देने से बचना चाहिए। उनका कहना था कि यदि यह सिलसिला नहीं रुका तो भाजपा पूरे प्रदेश में उनके खिलाफ सार्वजनिक घेराव करेगी। उन्होंने कांग्रेस सरकार से यह भी पूछा कि विधानसभा चुनाव के दौरान युवाओं को एक लाख नौकरियां देने और कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु में पक्की नौकरी देने जैसी गारंटियों का क्या हुआ। भाजपा प्रवक्ता ने राज्य सरकार पर भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरतने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार रोजगार देने में तय प्रक्रिया और प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रही है। उनका आरोप था कि विधानसभा और अन्य विभागों में नियुक्तियों के दौरान अपने क्षेत्र के लोगों और रिश्तेदारों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री ने अपने परिवार, रिश्तेदारों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नौकरी दी है। भाजपा ने इन आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग भी की। पत्रकार वार्ता के दौरान संदीपनी भारद्वाज ने नीट पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्र आंदोलन का विपक्षी दल राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।

हिमालय की ऊंचाइयों में पहुंचा हरियल

भारतेन्दु संवाददाता, रक्छम। किन्नौर जिले की समृद्ध जैव विविधता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज हुई है। रक्छम-चितकुल वन्यजीव अभयारण्य में हरियल (येलो-फुटेड ग्रीन पिजन, हरियल का पहली बार प्रमाणित रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। यह अवलोकन लगभग 3,400 मीटर की ऊंचाई पर किया गया, जो हिमाचल प्रदेश में इस प्रजाति की अब तक की सबसे अधिक ऊंचाई वाली दर्ज उपस्थिति मानी जा रही है।

इस दुर्लभ पक्षी का अवलोकन एवं दस्तावेजीकरण वन खंड अधिकारी रक्छम संतोष कुमार ठाकुर और वन मित्र अल्पना नेगी द्वारा किया गया। रिकॉर्ड को सत्यापन एवं अभिलेखीकरण के लिए राज्य के पक्षी विशेषज्ञों और पक्षी अध्ययन समुदाय के साथ साझा किया गया है। हरियल सामान्य रूप से मैदानी क्षेत्रों, उप-पहाड़ी वनों, बाग-बगीचों और लगभग 2,400 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। हिमालय के अत्यधिक ठंडे और ऊंचाई वाले इलाकों में इसकी उपस्थिति बेहद दुर्लभ मानी जाती है। ऐसे में बस्पा घाटी के शीत मरुस्थलीय क्षेत्र से सटे हिस्से में 3,400 मीटर की ऊंचाई पर इसका मिलना वैज्ञानिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के प्रकृतिविद् हिमांशु चौधरी ने बताया कि यह संभवत: प्रदेश में हरियल का सबसे ऊंचाई वाला रिकॉर्ड है। उन्होंने वर्ष 2020 में लद्दाख के माथो गाँव से नागरिक विज्ञान मंच eBird पर दर्ज लगभग 3,500 मीटर ऊँचाई वाले रिकॉर्ड का भी उल्लेख किया। विशेषज्ञों के अनुसार, सामान्यत: निचले क्षेत्रों में रहने वाली यह प्रजाति बहुत कम परिस्थितियों में इतनी अधिक ऊंचाई तक पहुंचती है। पक्षी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे असामान्य रिकॉर्ड पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के वितरण में हो रहे बदलावों की ओर संकेत कर सकते हैं। हालांकि, इसके पीछे जलवायु परिवर्तन, भोजन की उपलब्धता या अस्थायी प्रवास जैसे कारणों को समझने के लिए लंबे समय तक वैज्ञानिक निगरानी की आवश्यकता होगी। उप अरण्यपाल (डीसीएफ) सराहन अशोक नेगी, आईएफएस ने कहा कि किन्नौर की जैव विविधता अत्यंत समृद्ध है और वन विभाग की सतत निगरानी के कारण क्षेत्र में पक्षियों की नई प्रजातियों का दस्तावेजीकरण संभव हो रहा है। उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा, आईएएस ने वन्यजीव टीम को बधाई देते हुए कहा कि भविष्य में भी किन्नौर की जैव विविधता से जुड़े कई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड सामने आने की उम्मीद है। यह रिकॉर्ड पश्चिमी हिमालय में पक्षियों के बदलते वितरण को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा और जैव विविधता संरक्षण में स्थानीय वन अधिकारियों एवं वन मित्रों की भूमिका को भी रेखांकित करता है।

सरकार पहले गलती करती है, फिर उसी सुधार पर जश्न मनाती है : आशीष शर्मा

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। सदर विधायक आशीष शर्मा ने हमीरपुर के दोनों स्कूलों की बहाली और सह-शिक्षा व्यवस्था दोबारा शुरू करने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय जनता की आवाज और लगातार हुए विरोध का परिणाम है।

उन्होंने कहा कि ये दोनों संस्थान कई दशकों से हमीरपुर के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे थे, लेकिन सरकार ने बिना पर्याप्त सोच-विचार के इन्हें एक-दूसरे में विलय करने का फैसला लिया, जब जनता व विपक्ष ने इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाया, तो सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। आशीष शर्मा ने कहा कि ऐसे में सरकार व कांग्रेस नेताओं द्वारा जश्न मनाना तथा बधाइयां बांटना समझ से परे है। उन्होंने सवाल किया कि जिस फैसले से हजारों छात्र, अभिभावक और शिक्षक परेशान हुए, उसे वापस लेने पर आखिर किस उपलब्धि का उत्सव मनाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार पहले गलती करती है व फिर उसी गलती को सुधार कर अपनी पीठ थपथपाने का प्रयास करती है। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील बिट्टू पर निशाना साधते हुए आशीष शर्मा ने कहा कि वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और मुख्यमंत्री ने उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर राजनीतिक सलाहकार बनाया है। उन्होंने पूछा कि सरकार में रहते हुए बिट्टू हमीरपुर के लिए ऐसा कौन-सा नया संस्थान या बड़ी सौगात लेकर आए हैं, जिसका सीधा लाभ जिले की जनता और बच्चों को मिला हो। उन्होंने कहा कि केवल बयानबाजी से विकास नहीं होता, जनता परिणाम देखना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा कभी भी जनहित के फैसलों का विरोध नहीं करती।

पांगी-साच जोत मार्ग ठप; राशन से लदा ट्रक खाई की ओर लटका, कई वाहन फंसे

भारतेन्दु संवाददाता, चंबा। चंबा जिले के अंतर्गत पढ़ने वाले जनजातीय क्षेत्र पांगी में राशन की सप्लाई लेकर जा रहा एक ट्रक बगोटू के पास सड़क के किनारे खाई की ओर हवा में लटक गया, जिससे पांगी-सचे जोत मार्ग पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। घटना बुधवार देर शाम की बताई जा रही है। जिसके बाद वीरवार भारी मात्रा में रही बारिश के बाद शाम के समय मार्ग बहाल किया है। जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से साच पास की ओर जाने वाला मार्ग तंग है । ऐसे में कभी भी किसी भी गाड़ी के खराब होने पर भी तुरंत समाधान हो पाना न मुमकिन है।

जानकारी के अनुसार, जैसे ही चालक ने एक तीखा मोड़ काटा, ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे खाई की ओर लटक गया। चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए तुरंत ब्रेक लगाए और सुरक्षित नीचे उतर गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

मार्ग बंद होने के कारण पांगी में करीब एक दर्जन टैक्सियां और मटर से लदे कई वाहन फंस गए हैं। ट्रक के हटने तक इस मार्ग पर यातायात बहाल होना संभव नहीं है। ट्रक को जेसीबी मशीन की सहायता से निकालने से पहले उसमें लदा राशन दूसरे वाहन में स्थानांतरित किया जाएगा। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने लोक निर्माण विभाग की टीम को मौके पर भेज दिया। अधिशासी अभियंता रवि कुमार शर्मा स्वयं मौके पर पहुंचकर राहत एवं मार्ग बहाली कार्य की निगरानी कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि ट्रक को सुरक्षित हटाने का कार्य जारी है और जल्द ही मार्ग को यातायात के लिए बहाल कर दिया जाएगा। यात्रियों से प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था होने तक धैर्य बनाए रखने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।

नीट पर कांग्रेस का प्रदर्शन महज राजनीतिक ड्रामा : बलबीर सिंह

भारतेन्दु संवाददाता, अंब। पूर्व विधायक व भाजपा के वरिष्ठ नेता बलबीर सिंह ने अम्ब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पार्टी और स्थानीय विधायक पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बीते दिन नीट परीक्षा के विरोध में कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन को केवल एक 'राजनीतिक ड्रामा' करार दिया। बलबीर सिंह ने कहा कि जिस कांग्रेस के अपने शासनकाल में पुलिस भर्ती सहित दर्जनों भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए और दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय अधिकारियों को ऊंचे पदों से नवाजा गया, वह आज किस मुंह से प्रदर्शन कर रही है। बलबीर सिंह ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार युवाओं के भविष्य के प्रति पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने पूरे घटनाक्रम का ब्योरा देते हुए कहा कि 3 मई को नीट परीक्षा हुई और 7 मई को गड़बड़ी का इनपुट मिलते ही 12 मई को सीबीआई जांच सौंप दी गई।

शिमला में एनडीपीएस मामले का फरार आरोपी गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। शिमला पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े एक मामले में फरार चल रहे आरोपी को गैर-जमानती वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से न्यायालय में पेश नहीं हो रहा था। इसके बाद उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। पुलिस ने उसे मंडी जिले के करसोग क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान 34 वर्षीय किशन चौहान पुत्र चमन लाल निवासी करसोग, जिला मंडी के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ वर्ष 2023 में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उस समय उसके कब्जे से 6 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुई थी। मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र जिला एवं सत्र न्यायालय शिमला में पेश कर दिया था। पुलिस ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी लगातार न्यायालय में पेश नहीं हुआ। इसके बाद जिला एवं सत्र न्यायालय, शिमला ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया। वारंट मिलने के बाद पुलिस थाना सदर की टीम ने उसकी तलाश शुरू की और 23 जुलाई को मंडी जिले की करसोग तहसील के खाडौनी गांव से उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी को नियमानुसार जिला एवं सत्र न्यायालय, शिमला के समक्ष पेश किया जाएगा। जिला शिमला पुलिस ने कहा है कि मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और न्यायालय से जारी वारंटों का समय पर पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिससे ऐसे मामलों में कानून का प्रभावी ढंग से पालन हो सके।

दिल्ली लाठीचार्ज के विरोध में गरजी एनएसयूआई

बड़सर कॉलेज में किया प्रदर्शन, छात्रों ने उठाई निष्पक्ष जांच की मांग

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। नीट परीक्षा में पेपर लीक प्रकरण तथा दिल्ली में अपने अधिकारों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्र-छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में शुक्रवार कोराजकीय महाविद्यालय बड़सर में हस्र्ढ्ढ द्वारा धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया।

इस प्रदर्शन में रूबल सिंह ठाकुर, निदेशक एचपीएमसी एवं रुद्राक्ष सिंह, जिला उपाध्यक्ष एनएसयूआई सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए सरकार से मांग की।

इस अवसर पर रूबल सिंह ठाकुर ने कहा कि नीट जैसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय परीक्षा में पेपर लीक होना देश के लाखों मेहनती विद्यार्थियों के भविष्य के साथ गंभीर खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से छात्रों का परीक्षा व्यवस्था और सरकार के प्रति विश्वास कमजोर होता है। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और परीक्षा प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

उन्होंने दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्र-छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि लोकतंत्र में छात्रों को अपनी आवाज उठाने का पूरा अधिकार है। सरकार को छात्रों की समस्याओं का समाधान संवाद के माध्यम से करना चाहिए, न कि बल प्रयोग के माध्यम से। ठाकुर ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, ताकि देश के छात्रों में परीक्षा व्यवस्था के प्रति विश्वास दोबारा कायम हो सके। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कड़ी सजा दी जाए और भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था लागू की जाए।

देश का युवा न्याय, पारदर्शिता और निष्पक्ष व्यवस्था चाहता है। छात्रों के हितों और उनके भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। धरना-प्रदर्शन के दौरान छात्र-छात्राओं नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तथा छात्रों के अधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।

घुमारवीं के गांधी चौक में सीवरेज समस्या से लोग परेशान, दुर्गंध और गंदगी से बढ़ी परेशानी

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। शहर के सबसे व्यस्त व्यापारिक केंद्र गांधी चौक क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था चरमराने से स्थानीय दुकानदारों और आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले काफी समय से एक सीवरेज चैंबर से गंदगी खुले में बह रही है, जिससे सड़क पर दूषित पानी जमा हो गया है और पूरे क्षेत्र में दुर्गंध फैल रही है।

स्थानीय समाजसेवियों रवि उप्पल, नरेश शर्मा, संजय कुमार, संजीव कुमार और मंजीत सिंह ने समस्या पर चिंता जताते हुए कहा कि इस मार्ग से प्रतिदिन गुजरने वाले स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और राहगीरों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि बदबू के कारण दुकानों में बैठना मुश्किल हो गया है और बाजार में आने वाले ग्राहक भी असुविधा महसूस कर रहे हैं, जिसका असर कारोबार पर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि खुले में बह रहे सीवरेज के कारण मच्छरों और कीड़ों का प्रकोप बढ़ रहा है। बरसात के मौसम में संक्रमण और बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। लोगों के अनुसार, इस समस्या की जानकारी कई बार संबंधित विभागीय अधिकारियों को दी गई है। अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर चैंबरों की खराब स्थिति को भी स्वीकार किया था, लेकिन अभी तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। लोगों और व्यापारियों ने प्रशासन तथा नगर परिषद से मांग की है कि टूटे हुए सीवरेज चैंबरों की तुरंत मरम्मत करवाई जाए और क्षेत्र की सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए। इस मामले में नगर परिषद अध्यक्ष अमित कुमार ने कहा कि शहर के सीवरेज प्रभावित संवेदनशील स्थानों का संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ जल्द संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि स्थिति का आकलन कर तय समय सीमा में समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा।

आयोजन डीसी शिमला ने कहा- अब हर 60 दिन में होगी बैंकिंग योजनाओं और ऋण वितरण की समीक्षा

बैंक अधिकारी सिर्फ ऋणदाता ही नहीं, मार्गदर्शक भी बनें

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में बचत भवन के सभागार में जिला स्तरीय त्रैमासिक समीक्षा एवं सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जिला के सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी बैंकों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने तथा पात्र लाभार्थियों को उदारता के साथ ऋण उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य करें। उपायुक्त ने कहा कि लोगों को बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है। इसके दृष्टिगत प्रत्येक 60 दिन में समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें लोगों को प्रदान की गई बैंकिंग सुविधाओं, ऋण तथा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने बताया कि अगली बैठक 24 अगस्त को आयोजित की जाएगी। बैठक में बताया गया कि जिला में 1 जनवरी से 31 मार्च, 2026 तक 729 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए गए। इस पर उपायुक्त ने बैंकों को निर्देश दिए कि वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करने से पूर्व संबंधित पंचायतों के जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक योजनाओं की जानकारी पहुंच सके। उन्होंने कहा कि इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने के निर्देश जारी किए जाएंगे। उपायुक्त ने सभी बैंक अधिकारियों से अपनी क्षमता से बढ़कर कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बैंक अधिकारी उनके पास आने वाले प्रत्येक ऋण आवेदक के लिए पथ-प्रदर्शक की भूमिका निभाएं। इससे न केवल समाज के कमजोर वर्गों को लाभ मिलेगा, बल्कि बैंक भी अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। उन्होंने कहा कि यदि सभी मिलकर समन्वित प्रयास करेंगे तो जिला शिमला प्रदेश के अग्रणी जिलों में अपनी अलग पहचान बनाएगा। बैठक में बैंकों के माध्यम से केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने की प्रगति की भी समीक्षा की गई तथा उपायुक्त ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 31 मार्च, 2026 तक जिला में 1 लाख 95 हजार खाते खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 4 लाख 4 हजार लाभार्थी तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 1 लाख 75 हजार लाभार्थी पंजीकृत हैं।

वहीं, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 88,058 लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया है।जिला के 437 स्वयं सहायता समूहों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ा गया है, जिन्हें 12 करोड़ 82 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया गया है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना के तहत 31 मार्च, 2026 तक 139 ऋण स्वीकृत किए गए, जिनके अंतर्गत 51 लाख 10 हजार रुपये वितरित किए गए। इस तिमाही में जमा-ऋण अनुपात 46.88 प्रतिशत से बढ़कर 47.93 प्रतिशत हो गया है। बैठक में यह भी बताया गया कि गत वित्तीय वर्ष के दौरान सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए 28 करोड़ 45 लाख रुपये का ऋण प्रदान किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के तहत 67,900 खाताधारकों को 3,846.82 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया गया। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रायोरिटी सेक्टर में जिला के बैंकों ने निर्धारित लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हासिल करते हुए 53.91 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है, जबकि नॉन-प्रायोरिटी सेक्टर में 624.22 प्रतिशत की उपलब्धि दर्ज की गई। इस प्रकार कुल उपलब्धि 97.98 प्रतिशत रही। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में इस तिमाही के दौरान 3.58 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि शिक्षा ऋण में 1.05 प्रतिशत तथा गृह ऋण में 1.50 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक ने उपायुक्त का स्वागत किया तथा उन्हें पिछली बैठक की कार्यवाही और अनुपालन रिपोर्ट से अवगत करवाया। इस अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), नाबार्ड तथा विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

विपक्ष के शासनकाल में हुए 100 से ज्यादा पेपर लीक, भागने की बजाय जवाब दें : अनुराग ठाकुर

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विपक्ष पेपर लीक की घटनाओं पर सरकार के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाने की बजाय छात्रों के आंदोलन पर अपनी राजनैतिक रोटियां सेंक रहा है।

सरकार ने नीट पेपर लीक पर की निर्णायक कार्रवाई , 13 काबू, तेज न्याय के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें

राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के समय 17 पेपर लीक हुए, विपक्ष की सरकारों में 100 से ज़्यादा पेपर लीक की घटनाएं हुईं मगर इन्होंने कार्यवाई करना तो दूर उसे संज्ञान में तक नहीं लिया। मोदी सरकार ने नीट पेपर लीक के 13 आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारियां सुनिश्चित कीं, समय पर पूरी पारदर्शिता से दोबारा परीक्षा कराई, मोदी फास्टट्रैक कोर्ट बनाने और भविष्य में पेपर लीक के अपराधियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की घोषणा की है। अनुराग ने परीक्षाओं में गड़बड़ियों को जड़ से खत्म करने के मोदी सरकार के व्यवस्थित दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए कहा कि पेपर लीक के खिलाफ कठोर कानूनी ढांचा बनाने के लिए एक व्यापक नया विधेयक कैबिनेट में लाया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी हमारे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, उसे कानून के तहत सबसे सख्त सजा दी जाएगी। यह नया विधेयक कानूनी ढांचे को पूरी तरह बदल देगा, जिससे भविष्य में लीक रोके जा सकें और ऐसे प्रयास करने वालों पर कठोर दंड लगे। कैबिनेट ने इस मुद्दे पर व्यापक रोडमैप तैयार कर लिया है और इस महत्वपूर्ण विषय पर सोमवार को संसद में पूरी चर्चा निर्धारित है। विपक्षी दलों के राजनीतिक पाखंड को उजागर करते हुए श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेताओं के ट्रैक रिकॉर्ड पर सवाल उठाए।

उन्होंने बताया कि केवल राजस्थान में कांग्रेस शासन के दौरान पांच वर्षों में 17 पेपर लीक हुए और देशभर में विपक्ष शासित राज्यों में 100 से अधिक पेपर लीक की घटनाएं हुईं। उन्होंने जोर देते हुए कहा, 'मैं अखिलेश जी, राहुल जी और अन्य विपक्षी नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जब आपके शासन में पेपर लीक नियमित रूप से युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे थे, तब आपकी सरकारों ने क्या ठोस कदम उठाए थे? उनके विपरीत मोदी सरकार ने दोषियों को गिरफ्तार कर तत्काल और अडिग कार्रवाई की है तथा संरचनात्मक संस्थागत सुधार लागू किए हैं' अनुराग सिंह ठाकुर ने विपक्षी दलों से सीधा आग्रह किया कि वे अपनी बाधक रणनीति छोड़ें और सोमवार को होने वाली संसदीय बहस में भाग लें। उन्होंने उन्हें युवाओं के प्रति सच्ची चिंता दिखाने की सलाह दी, न कि जवाबदेही से भागने की।

न्यूज ब्रीफ

दून अस्पताल में बंदी की उपचार के दौरान मौत, पुलिस ने शुरू की जांच

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सुद्धोवाला जेल में बंद एक कैदी दिलदार की उपचार के दौरान मौत हो गई। 29 वर्षीय दिलदार को गंभीर स्वास्थ्य समस्या के चलते 16 जुलाई को कोरोनेशन अस्पताल से दून अस्पताल रेफर किया गया था। कई दिनों तक चले इलाज के बाद गुरुवार रात चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन ने मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

पेपर लीक विवाद: कीर्तिनगर में प्रदर्शन निष्पक्ष जांच की मांग

भारतेंदु संवाददाता, गढ़वाल। कीर्तिनगर तहसील परिसर में युवाओं ने पेपर लीक मामलों के विरोध में प्रदर्शन किया और जंतर-मंतर पर आंदोलन कर रहे छात्रों के समर्थन में आवाज उठाई। समाजसेवी गणेश भट्ट के नेतृत्व में युवाओं ने बाजार से तहसील तक पैदल मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम ज्ञापन भेजा। युवाओं ने छात्रों पर हुई कार्रवाई की भी जांच कराने की मांग रखी।

चारधाम यात्रा पैकेज के नाम पर ओडिशा के परिवार से लाखों की ठगी, हरिद्वार में मुकदमा दर्ज

भारतेंदु संवाददाता, हरिद्वार। चारधाम यात्रा के पैकेज के नाम पर ओडिशा के एक परिवार से ठगी कर ली गई। आरोप है कि कंपनी ने होटल में ठहरने से लेकर हेलीकाप्टर तक का किराया लिया। पुलिस ने पीड़ित श्रद्धालु की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, झारसुगुड़ा ओडिशा निवासी सिबानंद प्रधान ने शहर कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि उन्होंने परिवार के 13 सदस्यों के लिए ट्रिपलांजा ट्रैवल एजेंसी से चारधाम यात्रा पैकेज बुक कराया था। एजेंसी की प्रतिनिधि रिधिमा वर्मा ने प्रति व्यक्ति 25 हजार 500 रुपये के हिसाब से हेलीकाप्टर यात्रा, होटल और भोजन का पैकेज तय किया था।

मवेशियों को लेकर जंगल गई महिला की खाई में गिरी, दर्दनाक मौत

भारतेंदु संवाददाता, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे से सटे औलिया गांव की महिला की खाई में गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना से गांव में हड़कंप मच गया। एसडीआरएफ की टीम ने ग्रामीणों के साथ मिलकर बामुश्किल शव को खाई से बाहर निकाला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतका के स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है।

हल्द्वानी में स्कूली बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ सड़कों पर दौड़ रही लापरवाही

भारतेंदु संवाददाता, हल्द्वानी। शहर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा भगवान भरोसे नजर आई। गुरुवार दोपहर में दैनिक जागरण टीम ने स्कूल बसों और निजी वाहनों की पड़ताल की तो सरेआम सुरक्षा से खिलवाड़ होता मिला। कई स्कूल बसें खुले दरवाजों के साथ दौड़ती दिखीं। बसों में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठे दिखे। बच्चों का हर सफर जोखिम भरा दिखाई दिया।

जलवायु परिवर्तन से उत्तराखंड की कोसी नदी बेसिन में बढ़ेगा जल संकट

भारतेंदु संवाददाता, हरिद्वार। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रुड़की और जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के संयुक्त अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि जलवायु परिवर्तन के कारण उत्तराखंड की कोसी नदी बेसिन की दीर्घकालिक जल सुरक्षा गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रुड़की के डॉ.बी.दास, डॉ.एस. एन.और जी.बी.पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के डॉ. संदीपन मुखर्जी ने बताया कि अध्ययन से पता चला है कि इस शताब्दी के अंत तक अधिकतम तापमान वर्तमान लगभग 38.4 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर मध्यम उत्सर्जन परिदृश्य में 41.6 डिग्री सेल्सियस तथा उच्च उत्सर्जन परिदृश्य में 43.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

मानव-वन्यजीव संघर्ष में मददगारों को मिलेगा राज्य पुरस्कार : सीएम धामी

मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने की तैयारी तेज, मददगारों को मिलेगा विशेष सम्मान

- वन्यजीव हमलों के दौरान दूसरों की जान बचाने वालों का होगा सम्मान
- उत्तराखंड में वन्यजीव सुरक्षा के लिए नई पहल

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने और वन्यजीव संरक्षण को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन में आयोजित उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड और राज्य स्तरीय बाघ संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव और वन्यजीवों के बीच बढ़ते संघर्ष को रोकने के लिए प्रभावी और दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वन्यजीवों के प्राकृतिक आवासों, वन्यजीव गलियारों और जल स्रोतों का संरक्षण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रबंधन व्यवस्था को अपनाया जाए। साथ ही वन्यजीवों की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने और समय पर सूचना तंत्र को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं के दौरान साहस दिखाकर दूसरों की जान बचाने वाले लोगों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। ऐसे लोगों को राज्य पुरस्कार देकर उनका उत्साह बढ़ाया जाएगा, ताकि समाज में भी वन्यजीव संघर्ष के समय मदद और जिम्मेदारी की भावना को प्रोत्साहन मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में वन्यजीव पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। राज्य की जैव विविधता और प्राकृतिक संपदा को ध्यान में रखते हुए वन्यजीव आधारित पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और संरक्षण के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने पर्यटन गतिविधियों को पर्यावरण संतुलन के साथ आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।

कारोबारियों के खाते पर रोक मामले में हाई कोर्ट सख्त

हाई कोर्ट का बड़ा फैसला : बिना आदेश बैंक नहीं करेगा खाता फ्रीज

भारतेंदु संवाददाता, नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हरिद्वार के एक कारोबारी के बैंक खाते को फ्रीज करने के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए बैंक की कार्रवाई को गलत ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के किसी बैंक खाते को फ्रीज नहीं किया जा सकता। साथ ही पुलिस भी बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए खाते की रकम पर रोक नहीं लगा सकती, जब तक कोई आपराधिक मामला दर्ज न हो।

मामला हरिद्वार के कारोबारी मुनव्वर के कोटक महिंद्रा बैंक की शिवालिक नगर शाखा के खाते से जुड़ा है। खाते में 44 लाख रुपये आने के बाद 10 अक्टूबर 2025 को बैंक ने इसे फ्रीज कर दिया था। बैंक को यह जानकारी दी गई थी कि यह रकम गलती से ट्रांसफर हुई है।

कारोबारी ने खाते पर लगी रोक को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का

- कारोबारियों को मिली राहत, बैंक आदेश रद्द

दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने बैंक की कार्रवाई को अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया और खाता दोबारा चालू करने के निर्देश दिए।

हाई कोर्ट के इस फैसले से कारोबारी को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बैंक खातों पर कार्रवाई करते समय निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। फैसले को बैंकिंग व्यवस्था और खाताधारकों के अधिकारों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

यूकेडी ने मनाया 48वां स्थापना दिवस, इंद्रमणि बडोनी को दी श्रद्धांजलि

उत्तराखंड क्रांति दल ने मनाया 48वां स्थापना दिवस, राज्य आंदोलन के संकल्प को दोहराया

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड क्रांति दल का 48वां स्थापना दिवस प्रदेशभर में उत्साह और गरिमापूर्ण वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर देहरादून स्थित केंद्रीय कार्यालय सहित सभी जिला मुख्यालयों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। दो दिवसीय कार्यक्रम के तहत 24 जुलाई 2026 को केंद्रीय कार्यालय में दल का ध्वजारोहण किया गया। कार्यकारी अध्यक्ष जय प्रकाश उपाध्याय ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

इसके बाद स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यकारी अध्यक्ष जय प्रकाश उपाध्याय ने कहा कि बडोनी का अहिंसक आंदोलन आज भी युवाओं को प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन की मूल भावना और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दल अपना संघर्ष लगातार जारी रखेगा।

कार्यक्रम के दौरान शहीद स्थल पर राज्य आंदोलनकारियों को भी श्रद्धांजलि दी गई। दल के केंद्रीय महामंत्री कर्नल कैलाश देवरानी ने धरने पर बैठे राज्य आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य गठन के 26 वर्ष बाद भी उत्तराखंड के शहीदों के सपनों का राज्य पूरी तरह साकार नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि अब सभी आंदोलनकारी ताकतों को एकजुट होकर राज्य हितों के लिए आगे बढ़ना होगा। उन्होंने आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत करने का आह्वान किया और कहा कि तभी

आंदोलनकारियों के सपनों को पूरा किया जा सकता है।

कार्यक्रम में शांति प्रसाद भट्ट, बहादुर सिंह रावत, देव चंद उत्तराखंडी, रमा चौहान, राजेश्वरी रावत, विजय बौड़ाई, प्रकाश भट्ट, टीकम राठौर, महिपाल सिंह पुंडीर, रामपाल, कर्नल सुनील चौहान, महानगर अध्यक्ष प्रवीण चंद रमोला, जिलाध्यक्ष पछवादून जितेंद्र पंवार सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

कांवड़ यात्रा 2026: श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे चलाएगा विशेष ट्रेनें

भारतेंदु संवाददाता, हरिद्वार। कांवड़ मेला 2026 को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। हरिद्वार पहुंचने वाले लाखों शिवभक्तों को सुगम यात्रा उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली और हरिद्वार के बीच मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही कई नियमित ट्रेनों का विस्तार हरिद्वार तक किया गया है, जिससे यात्रियों को आवागमन में परेशानी का सामना न करना पड़े। रेलवे के अनुसार दिल्ली-शामली-दिल्ली डीईएमयू ट्रेन को हरिद्वार तक विस्तारित किया गया है। यह विशेष सेवा 30 जुलाई से 13 अगस्त तक दिल्ली से और 31 जुलाई से 14 अगस्त तक हरिद्वार से प्रतिदिन संचालित होगी। इस ट्रेन के विस्तार से दिल्ली, शामली, रुड़की और हरिद्वार के बीच यात्रा करने वाले कांवड़ यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा दिल्ली-सहारनपुर-दिल्ली मेमू ट्रेन का भी हरिद्वार तक विस्तार किया गया है। रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रायवाला, मोतीचूर और ज्वालापुर जैसे प्रमुख स्टेशनों पर कई ट्रेनों को अतिरिक्त ठहराव देने का निर्णय लिया है। इससे श्रद्धालुओं को अपने गंतव्य तक पहुंचने में आसानी होगी। कांवड़ मेले के दौरान हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं और गंगाजल लेकर अपने क्षेत्रों की ओर लौटते हैं।

कोट स्वास्थ्य शिविर में 556 मरीजों को मिली निशुल्क सेवाएं

भारतेंदु संवाददाता, पौड़ी गढ़वाल। स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य सेवा सप्ताह के तहत 22 से 24 जुलाई तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) कोट में आयोजित तीन दिवसीय वृहद स्वास्थ्य शिविर में 556 मरीजों ने नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों की जांच कर परामर्श और उपचार उपलब्ध कराया। शिविर में एक्स-रे, रक्त जांच, टीबी स्क्रीनिंग, मधुमेह व उच्च रक्तचाप की जांच, गर्भवती महिलाओं की एएनसी जांच, ओरल, सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग सहित विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं दी गईं। पात्र लाभार्थियों के दिव्यांगता प्रमाण-पत्र भी बनाए गए। आंकड़ों के अनुसार, जनरल फिजिशियन ने 193, हड्डी रोग विशेषज्ञ ने 56, स्त्री रोग विशेषज्ञ ने 27, नेत्र रोग विशेषज्ञ ने 34 और दंत रोग विशेषज्ञ ने 48 मरीजों का परीक्षण किया। इसके अलावा 85 लोगों की रक्त जांच, 132 लोगों के टीबी एक्स-रे किए गए तथा तीन दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी किए गए।

मसूरी सड़क और पुल निर्माण का मंत्री सतपाल महाराज ने किया निरीक्षण

सतपाल महाराज ने सड़क मरम्मत और पुल निर्माण में तेजी के दिए निर्देश।

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने शुक्रवार को मसूरी के कोल्हूखेत स्थित पानी वाले बैंड और देहरादून-मसूरी राज्य मार्ग पर निर्माणाधीन डबल लेन पुल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं, ताकि स्थानीय लोगों और पर्यटकों को सुरक्षित तथा सुगम यातायात की सुविधा मिल सके।

मंत्री ने उस स्थान का भी जायजा लिया, जहां 20 जुलाई की रात भारी बारिश के कारण करीब 20 मीटर सड़क और पुश्ता क्षतिग्रस्त हो गया था। इस घटना के बाद सड़क की चौड़ाई घटकर लगभग ढाई मीटर रह गई थी। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग ने तुरंत जेसीबी मशीनों की मदद से मरम्मत कार्य शुरू कर दिया था। साथ ही अतिरिक्त पहाड़ कटान और सुरक्षा उपायों पर भी तेजी से काम किया जा रहा है, जिससे यातायात जल्द पूरी तरह सामान्य हो सके।

सतपाल महाराज ने बताया कि उत्तराखंड की स्लोप ट्रीटमेंट विशेषज्ञ संस्था यूएलएलएमसी ने भी प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर आवश्यक सुरक्षात्मक कार्यों की योजना तैयार की है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्थायी समाधान किए जाएंगे।

रुद्रप्रयाग पुलिस लाइन रतूड़ा में साप्ताहिक परेड हुई आयोजित

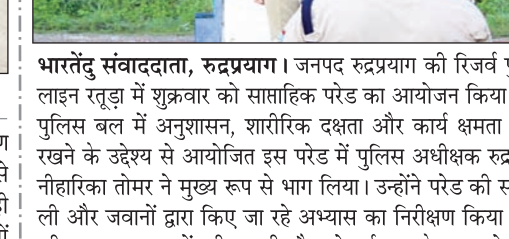

भारतेंदु संवाददाता, रुद्रप्रयाग। जनपद रुद्रप्रयाग की रिजर्व पुलिस लाइन रतूड़ा में शुक्रवार को साप्ताहिक परेड का आयोजन किया गया। पुलिस बल में अनुशासन, शारीरिक दक्षता और कार्य क्षमता बनाए रखने के उद्देश्य से आयोजित इस परेड में पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग नीहारिका तोमर ने मुख्य रूप से भाग लिया। उन्होंने परेड की सलामी ली और जवानों द्वारा किए जा रहे अभ्यास का निरीक्षण किया। परेड की शुरुआत जवानों की हल्की दौड़ से हुई। इसके बाद टोलीवार विभिन्न ड्रिल, कदमताल और शस्त्राभ्यास कराया गया। पुलिस अधीक्षक ने जवानों की शारीरिक तैयारी, अनुशासन और अभ्यास की गुणवत्ता का जायजा लिया।

उन्होंने कहा कि नियमित परेड पुलिस कर्मियों में आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ ही आपात परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण होती है। परेड के बाद पुलिस अधीक्षक ने रिजर्व पुलिस लाइन परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शस्त्रागार, राजकीय स्टोर और विभिन्न कार्यालयों की व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने संबंधित कर्मचारियों से रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जानकारी ली तथा सभी अभिलेखों को समय-समय पर अपडेट रखने के निर्देश दिए। एसपी ने पुलिस लाइन परिसर में साफ-सफाई और बेहतर व्यवस्थाएं बनाए रखने पर भी जोर दिया।

बागेश्वर में भ्रष्टाचार पर विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई

बागेश्वर में उरेडा अधिकारी 40 हजार रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार

- उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण बागेश्वर में तैनात है परियोजना अधिकारी धीरेंद्र सिंह पटवाल

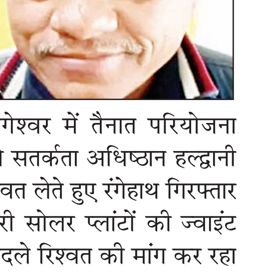

भारतेंदु संवाददाता, बागेश्वर। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) बागेश्वर में तैनात परियोजना अधिकारी धीरेंद्र सिंह पटवाल को सतर्कता अधिष्ठान हल्द्वानी की टीम ने 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अधिकारी सोलर प्लांटों की ज्वाइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार करने के बदले रिश्वत की मांग कर रहा था। सतर्कता अधिष्ठान के अनुसार शिकायतकर्ता की चार फाइलें लंबे समय से उरेडा कार्यालय में लंबित थीं। आरोप है कि प्रत्येक फाइल के लिए 10 से 15 हजार रुपये की मांग की गई थी। चारों फाइलों के निपटारे के लिए कुल 40 हजार रुपये मांगे गए थे। शिकायतकर्ता ने रिश्वत देने से इनकार करते हुए मामले की सूचना सतर्कता विभाग को दी। शिकायत का सत्यापन करने के बाद आरोप सही पाए जाने पर ट्रैप टीम गठित की गई। टीम ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए परियोजना अधिकारी धीरेंद्र सिंह पटवाल को शिकायतकर्ता से 40 हजार रुपये लेते हुए गिरफ्तार कर लिया।

बनभूलपुरा अतिक्रमण मामला : सुप्रीम कोर्ट में फिर टली सुनवाई, लोगों में बेचैनी

- 10 साल पुराने अतिक्रमण मामले में फैसले का इंतजार जारी

भारतेंदु संवाददाता, हल्द्वानी। बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई एक बार फिर टल गई है। लंबे समय से फैसले का इंतजार कर रहे क्षेत्रवासियों में इससे बेचैनी बढ़ गई है। गुरुवार को मामले की सुनवाई प्रस्तावित थी, लेकिन केस सूची में 120वें नंबर पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।

सुनवाई को देखते हुए हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई थी। इज्जतनगर से आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त मोहम्मद असलम सहित अन्य अधिकारियों ने स्टेशन और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। हालांकि सुनवाई नहीं होने के बाद अधिकारियों को वापस लौटना पड़ा। यह मामला हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से सटे बनभूलपुरा क्षेत्र की करीब 31 हेक्टेयर रेलवे भूमि से जुड़ा है। इस भूमि पर रेलवे अपना दावा करता है, जबकि यहां लंबे समय से हजारों परिवार रह रहे हैं। क्षेत्र में लगभग 4365 घर हैं, जिनमें करीब 50 हजार लोगों की आबादी निवास करती है। यहां कई धार्मिक स्थल, सरकारी स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र भी मौजूद हैं।

बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामला करीब दस वर्षों से न्यायालयों में चल रहा है। पहले यह मामला हाई कोर्ट में था, जिसके बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यदि फैसला उनके पक्ष में आता है तो हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के विस्तार का रास्ता साफ होगा।

वहीं क्षेत्रवासियों की ओर से याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन एक बार फिर तारीख आगे बढ़ने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। अब सभी की नजर अगली सुनवाई पर टिकी हुई है।

मासूम राकेश की तलाश खत्म, शव मिलने से मातम में गांव

बागेश्वर: पांच दिन बाद मिला सरयू में बहे मासूम का शव, घरवालों में मचा कोहराम

भारतेंदु संवाददाता, बागेश्वर। कपकोट क्षेत्र में सरयू नदी में बहे आठ वर्षीय मासूम राकेश सिंह का शव पांच दिन बाद बरामद होने से परिवार में दुख का माहौल छा गया। शुक्रवार को असौं गांव के समीप कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के सामने नदी से बच्चे का शव मिला। शव मिलने की पुष्टि राकेश के ताऊ खीम सिंह ने की। इसके बाद परिजनों में एक बार फिर से कोहराम मच गया।

कपकोट तहसील के लाहुर गांव निवासी राकेश सिंह पुत्र नारायण सिंह 20 जुलाई को अपनी मां कमला देवी के साथ शिवालय स्थित शिव मंदिर गया था। इसी दौरान पानी भरते समय अचानक उसका पैर फिसल गया और वह सरयू नदी की तेज धारा में बह गया। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी।

मासूम की तलाश के लिए पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों ने कई दिनों तक अभियान चलाया। नदी के तेज बहाव और कठिन परिस्थितियों के बावजूद बचाव दल लगातार बच्चे की खोज में जुटे रहे। पांच दिन बाद शुक्रवार को राकेश का शव नदी से बरामद किया गया। शव मिलने के बाद प्रशासन ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

हरिद्वार में स्कूली वाहनों पर कार्रवाई 65 के चालान, तीन बसें सीज

भारतेंदु संवाददाता, हरिद्वार। विद्यालयी बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग का विशेष प्रवर्तन अभियान लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 65 स्कूली वाहनों के चालान किए गए, जबकि तीन बसों को सीज कर दिया गया। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) नेहा झा और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) निखिल शर्मा के नेतृत्व में विभिन्न विद्यालयों की बसों एवं अन्य स्कूली वाहनों का सघन निरीक्षण किया गया। इस दौरान फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट, चालक के ड्राइविंग लाइसेंस, अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार किट, महिला परिचारिका की उपलब्धता, आपातकालीन निकास तथा वाहनों की तकनीकी स्थिति सहित सभी अनिवार्य सुरक्षा मानकों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 65 स्कूली वाहनों के चालान किए गए। वहीं, दो विद्यालय बसें बिना वैध फिटनेस प्रमाणपत्र और एक बस बिना पंजीकरण संचालित मिलने पर उन्हें सीज कर दिया गया। परिवहन विभाग का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। विशेष अभियान में परिवहन कर अधिकारी वरुणा सैनी, परिवहन कर अधिकारी मुकेश भारती और परिवहन उपनिरीक्षक अश्वनी कुमार भी शामिल रहे।

यूपीईएस-एचपीई साझेदारी से तैयार होंगे भविष्य के एआई इंजीनियर

यूपीईएस और एचपीई ने एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का किया शुभारंभ

- देहरादून में शुरू हुआ एआई आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। यूपीईएस ने हेवलेट पैकार्ड एंटरप्राइज यानी एचपीई के साथ एक रणनीतिक साझेदारी में, एचपीई नेटवर्किंग एआई-ड्रिवन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी सीओई का उद्घाटन किया। यह यूनिवर्सिटी की एआई-फर्स्ट लर्निंग इकोसिस्टम तैयार करने की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेंटर को छात्रों को एआई-ड्रिवन नेटवर्किंग, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबरसिक्योरिटी और एंटरप्राइज़ टेक्नोलॉजीज़ में फ्यूचर रेडी क्षमताओं से लैस करके एकेडेमिया और इंडस्ट्री के बीच की दूरी को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है।

फ्यूचर-फोकस्ड लर्निंग इकोसिस्टम के रूप में डिजाइन किया गया यह सेंटर करिकुलम इंटीग्रेशन, फैकल्टी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, हैंड्स-ऑन लैबोरेटरी अनुभव, लाइव डेमॉन्स्ट्रेशन्स, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, एचपीई-लेड बूटकैंप्स, सर्टिफिकेशन पाथवेज़ और इंटरडिसिप्लिनरी इनोवेशन तथा रिसर्च के अवसर प्रदान करेगा। छात्रों को एसोसिएट और स्पेशलिस्ट लेवल पर एचपीई नेटवर्किंग ट्रेनिंग, एचपीई, उसके पार्टनर्स और कस्टमर्स के बीच संभावित इंटर्नशिप्स और हायरिंग पाथवेज़ तक भी पहुंच मिलेगी, जिससे बदलती टेक्नोलॉजी वर्कफोर्स के लिए उनकी तैयारी मजबूत होगी।

नैसकॉम और डेलॉइट की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत को 2027 तक 1.25 मिलियन से अधिक एआई प्रोफेशनल्स की आवश्यकता होगी, जबकि 600,000 से अधिक कुशल वर्कर्स की अनुमानित कमी बताई गई है। एचपीई नेटवर्किंग एआई-ड्रिवन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना एआई, एंटरप्राइज़ नेटवर्किंग, क्लाउड और साइबरसिक्योरिटी में कुशल टैलेंट की इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए की गई है।

यूपीईएस के लिए, यह सीओई इस बात का प्रमाण है कि इसकी एआई-फर्स्ट यूनिवर्सिटी रणनीति केवल किसी एक कोर्स या विभाग तक सीमित नहीं है, बल्कि करिकुलम, फैकल्टी और इंडस्ट्री पार्टनरशिप में गहराई से शामिल है। दोनों पार्टनर्स को उम्मीद है कि यह सेंटर यूपीईएस ग्रेजुएट्स को केवल जॉब-रेडी नहीं, बल्कि नेटवर्किंग, क्लाउड और साइबरसिक्योरिटी में एंटरप्राइज़ एआई एडॉप्शन के फ्यूचर शेपर्स के रूप में तैयार करेगा, जहां एआई केवल कंप्यूटर साइंस तक सीमित न रहकर अलग-अलग डिसिप्लिन्स में शामिल होगा।

इस सेंटर का उद्घाटन यूपीईएस और एचपीई की ग्लोबल लीडरशिप के बीच दिनभर चले एंगेजमेंट का मुख्य आकर्षण रहा। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत और रिसेप्शन के साथ हुई, जिसके बाद एक लीडरशिप राउंडटेबल आयोजित की गई।

कैट के फैसले से चंडीगढ़ पुलिस अधिकारियों की पदोन्नति का रास्ता खुला

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़।

चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों के लिए भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त होने की दिशा में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की चंडीगढ़ पीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अधिकरण ने पुलिस उपाधीक्षक रामगोपाल की वर्ष 2019 से लंबित मूल याचिका स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि चंडीगढ़ पुलिस के पुलिस उपाधीक्षक संवर्ग को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम तथा केंद्र शासित प्रदेश संयुक्त संवर्ग के लिए भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति हेतु आधार संवर्ग बनाने की प्रक्रिया निर्धारित समय में पूरी की जाए।

यह फैसला न्यायिक सदस्य रमेश सिंह ठाकुर और प्रशासनिक सदस्य रश्मि सक्सेना साहनी की पीठ ने सुनाया। रामगोपाल ने वर्ष 2019 में अधिकरण का दरवाजा खटखटाते हुए अपने पदोन्नति दावे को अस्वीकार किए जाने को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि चंडीगढ़ पुलिस के पुलिस उपाधीक्षक संवर्ग को पदोन्नति के लिए मान्यता प्राप्त आधार संवर्ग नहीं माना गया, जबकि अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को यह सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने यह भी दलील दी थी कि चंडीगढ़ में भारतीय पुलिस सेवा के पद स्वीकृत होने के बावजूद यहां के पात्र अधिकारियों को पदोन्नति का अवसर नहीं मिल रहा है।

अधिकरण ने अपने निर्णय में प्रशासनिक देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि गृह मंत्रालय के निर्देश और भर्ती नियम अधिसूचित होने के बावजूद चंडीगढ़ प्रशासन ने आवश्यक प्रस्ताव समय पर आगे नहीं भेजे। इस कारण पात्र अधिकारियों के वैधानिक अधिकार प्रभावित हुए, जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। अधिकरण ने स्पष्ट कहा कि केवल प्रशासनिक निष्क्रियता के कारण किसी अधिकारी को उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

मोहाली के 16 गांवों में विकास कार्यों पर हाईकोर्ट की रोक

वन भूमि सीमांकन पूरा होने तक निर्माण, विकास, म्यूटेशन और संपत्ति हस्तांतरण पर रोक, मुख्य सचिव को सख्त निर्देश

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के आसपास स्थित पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील वन क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर बड़ा और सख्त आदेश जारी किया है। अदालत ने मोहाली जिले के 16 गांवों में सभी प्रकार के निर्माण, विकास कार्य, भूमि हस्तांतरण और संपत्ति से जुड़े लेनदेन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक संबंधित भूमि का विधिवत सीमांकन नहीं हो जाता, तब तक इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की नई गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। अदालत ने आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायाधीश रोहित कपूर की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को वन भूमि का सीमांकन करने के स्पष्ट निर्देश दिए थे, लेकिन 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी पंजाब सरकार इस दिशा में प्रभावी कार्रवाई नहीं कर सकी। अदालत ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए कहा कि वन भूमि की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर राज्य की जिम्मेदारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

हाईकोर्ट ने जिन गांवों में रोक लगाने का आदेश दिया है, उनमें करोरां, नाडा, परछ, सुंक, माजरियां, छोटी नागल, बड़ी नागल, परोल, सिसवां, पल्लनपुर, सैनी माजरा, दुलवां, बुराना, गोचर, मिर्जापुर, तारापुर और सुल्तानपुर शामिल हैं। अदालत ने कहा कि उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के अनुसार इन गांवों की भूमि प्रथम दृष्टया वन भूमि के रूप में दर्ज है, लेकिन इसका विधिवत सीमांकन अब तक नहीं किया गया। ऐसे में किसी भी प्रकार का निर्माण या व्यावसायिक गतिविधि पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है।

खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि सीमांकन पूरा होने तक इन गांवों में भवन निर्माण, कॉलोनियों का विकास, सड़क निर्माण, भूमि की खरीद-फरोख्त, रजिस्ट्री, म्यूटेशन, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए), पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) अथवा किसी अन्य माध्यम से संपत्ति के हस्तांतरण पर पूरी तरह रोक रहेगी। अदालत ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था आदेश की अवहेलना करती है तो उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने शिवालिक की तलहटी में स्थित इस पूरे क्षेत्र को अत्यंत संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्र बताया। अदालत ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में इस इलाके में तेजी से व्यावसायीकरण हुआ है, जिसके कारण प्राकृतिक वन क्षेत्र और जैव विविधता पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंच सकती है।

हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि जंगलों के संरक्षण के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाना पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1900 तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की भावना के विपरीत है। अदालत ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल कानूनी दायित्व नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी भी है।

अदालत ने पंजाब के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे वन विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम का गठन करें। इस टीम का नेतृत्व मुख्य वन संरक्षक करेंगे। टीम को छह सप्ताह के भीतर वर्ष 1980 में वन (संरक्षण) अधिनियम लागू होने के समय उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के आधार पर वास्तविक वन भूमि की पहचान कर उसका सीमांकन करने का कार्य पूरा करना होगा।

न्यूज ब्रीफ

मानसून में लापरवाही पड़ सकती है स्वास्थ्य पर भारी

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली। मानसून के दौरान पेट और पाचन संबंधी संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जिला अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन 15 से 20 मरीज दस्त, उल्टी, पेट दर्द और बुखार जैसी शिकायतों के साथ पहुंच रहे हैं। सिविल अस्पताल के डीएम नेफ्रोलॉजी डॉ. अंकुर चौधरी ने बताया कि बारिश के मौसम में दूषित पानी, खुले में बिकने वाला भोजन, कटे फल और बासी खाना संक्रमण का प्रमुख कारण बनते हैं। इससे फूड पॉइजनिंग, जठरांत्र शोथ, दस्त और टाइफाइड जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि बच्चों, बुजुर्गों तथा किडनी, मधुमेह और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। बचाव के लिए उबला या फिल्टर किया हुआ पानी पीना, ताजा और गर्म भोजन करना, हाथों की नियमित सफाई रखना तथा फल-सब्जियों को अच्छी तरह धोकर खाना जरूरी है। दस्त होने पर ओआरएस लें और बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी प्रतिजैविक दवा का सेवन न करें।

बिजली, सड़क और सीवरेज समस्याओं से बढ़ा जनआक्रोश

भारतेन्दु संवाददाता, जीरकपुर। नगर परिषद के वार्ड-27 में बिजली कटौती, टूटी सड़कें, ओवरफ्लो सीवरेज और जलभराव जैसी समस्याओं से लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि चुनाव के दौरान किए गए विकास के वादे अब तक पूरे नहीं हुए। बरसात में सड़कों पर जलभराव होने से गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। वहीं सीवरेज के गंदे पानी से मच्छरों का प्रकोप बढ़ने के कारण डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों की आशंका भी बनी हुई है। लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं हो रहा। समाजसेवी एवं भाजपा नेता योगेश अरोड़ा सोनी ने प्रशासन से समस्याओं का तत्काल समाधान कर लोगों को राहत देने की मांग की।

जंतर-मंतर लाठीचार्ज के विरोध में डॉक्टरों का प्रदर्शन

भारतेन्दु संवाददाता, जीरकपुर। दिल्ली के जंतर-मंतर पर युवाओं पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में वीरवार को जीरकपुर के सीएचसी ढकोली में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व सरकारी मेडिकल ऑफिसर राजेश और प्रभजोत कौर ने किया। प्रदर्शनकारियों ने घटना की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और अनावश्यक बल प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से युवाओं की समस्याओं का संवाद के माध्यम से समाधान निकालने और पूरे मामले की पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने की मांग की।

ग्रीन जोन फैसले के विरोध में किसानों का प्रदर्शन

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली। न्यू चंडीगढ़ के समीप स्थित गांव वजीदपुर के किसानों और विभिन्न किसान संगठनों ने गमाडा के खिलाफ प्रदर्शन कर अपनी उपजाऊ कृषि भूमि को प्रस्तावित ग्रीन/फॉरेस्ट जोन में शामिल किए जाने का विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि यह निर्णय वापस नहीं लिया गया तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू करने को मजबूर होंगे। किसानों का कहना है कि गांव वजीदपुर की भूमि सब-तहसील माजरी और मुख्य हाईवे के निकट स्थित है तथा यह अत्यंत उपजाऊ और करोड़ों रुपये मूल्य की कृषि भूमि है। उनका आरोप है कि कुराली प्लानिंग के तहत गमाडा ने उनकी जमीन को ग्रीन/फॉरेस्ट जोन में शामिल कर दिया, जबकि आसपास के गांवों की शामलात और नदियों-नालों के किनारे की कम उपयोगी भूमि को आर-जोन में रखा गया है। किसानों का कहना है कि ग्रीन जोन घोषित होने से भूमि के उपयोग पर कई प्रतिबंध लग जाएंगे, जिससे उनकी आय और संपत्ति के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की। किसानों ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करते हुए प्रशासन का घेराव किया जाएगा।

मांगें पूरी नहीं हुईं तो तीन से पांच अगस्त तक पंजाब में होगा रोडवेज कर्मचारियों का चक्का जाम

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन (25/11) ने राज्य सरकार पर कर्मचारियों से किए गए वादे पूरा न करने का आरोप लगाते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। यूनियन नेताओं ने चंडीगढ़ में प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो 3 से 5 अगस्त तक पूरे पंजाब में चक्का जाम किया जाएगा। इसके अलावा परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना तथा मानसून सत्र के दौरान भूख हड़ताल भी की जाएगी। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रेशम सिंह गिल ने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने और ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। उन्होंने ठेकेदारी व्यवस्था में कर्मचारियों के शोषण, ईपीएफ और ईएसआई में अनियमितताओं तथा विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। यूनियन का दावा है कि बसों के लिए स्पेयर पार्ट्स, टायर और बैटरियों की कमी के कारण सैकड़ों बसें खड़ी हैं, जिससे निजी परिवहन को लाभ मिल रहा है। 27 जुलाई को सभी डिपो पर गेट रैलियां आयोजित की जाएंगी।

सरकार की चुप्पी से बढ़ा कर्मचारियों का रोष

यूनियन नेताओं ने कहा कि 24 जून को सरकार और कर्मचारी प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया गया था, लेकिन तय समय बीत जाने के बावजूद किसी भी मांग पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया। उनका आरोप है कि बार-बार बातचीत के बावजूद केवल आश्वासन ही दिए गए, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। यूनियन का कहना है कि परिवहन विभाग में लंबे समय से रिक्त पदों को नहीं भरा जा रहा है, जिससे मौजूदा कर्मचारियों पर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ गया है। दूसरी ओर बसों के रखरखाव के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी के कारण कई वाहन डिपो में खड़े हैं, जिससे यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नेताओं ने आरोप लगाया कि इससे सरकारी परिवहन सेवा कमजोर हो रही है और निजी बस संचालकों को अप्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है यूनियन ने स्पष्ट किया कि यदि मांगें पूरी नहीं हुई और आंदोलन के दौरान कर्मचारियों पर दर्ज मामलों को वापस नहीं लिया गया तो संघर्ष को अनिश्चितकाल तक जारी रखा जाएगा।

लेबर बोर्ड निवेश घोटाले में सीबीआई जांच से बड़ा खुलासा आया सामने

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड के 50 करोड़ रुपये से अधिक के कथित निवेश घोटाले की जांच में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। जांच एजेंसी ने अदालत में दायर रिमांड आवेदन में दावा किया है कि बोर्ड के तत्कालीन अकाउंट्स ऑफिसर जुगल किशोर और कॉन्ट्रेक्ट अकाउंट्स क्लर्क अमित कुमार ने अन्य लोगों तथा कुछ लोक सेवकों के साथ मिलकर सुनियोजित साजिश रची और सरकारी धन के दुरुपयोग में अहम भूमिका निभाई।

सीबीआई के अनुसार आरोपितों ने निर्धारित नियमों की अनदेखी करते हुए चंडीगढ़ के सेक्टर-32 स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड के नाम से एक अनधिकृत बचत खाता खुलवाया। जांच में सामने आया है कि इसी खाते के माध्यम से करोड़ों रुपये विभिन्न शेल कंपनियों में स्थानांतरित किए गए। एजेंसी का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य सरकारी धन का गलत इस्तेमाल करना और वास्तविक लेनदेन को छिपाना था।

रिमांड आवेदन में सीबीआई ने बताया कि कॉन्ट्रेक्ट अकाउंट्स क्लर्क अमित कुमार ने सावधि जमा (एफडी) के नाम पर नोटशीट तैयार की, बैंक के साथ पत्राचार किया और बाद में विभागीय रिकॉर्ड में बैकडेटेड दस्तावेज तथा कथित फर्जी एफडी रसीदें संलग्न कर यह दिखाने का प्रयास किया कि राशि सुरक्षित रूप से सावधि जमा में निवेश की गई है। जांच एजेंसी का आरोप है कि इस तरीके से वास्तविक वित्तीय लेनदेन को छिपाने की कोशिश की गई।

वहीं, अकाउंट्स ऑफिसर जुगल किशोर पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता होने के बावजूद खाते के संचालन की निगरानी नहीं करने और कथित वित्तीय अनियमितताओं को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया गया है। सीबीआई का कहना है कि उनकी भूमिका की गहन जांच की जा रही है और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं।

ड्रोन सर्वे से होगा भूमि अधिग्रहण, गमाडा की नई व्यवस्था से मुआवजा प्रक्रिया होगी पारदर्शी

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली

ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और विवादमुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नई गाइडलाइन के तहत अब विकास परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की जाने वाली जमीन पर मौजूद मकान, पेड़, बाग, ट्यूबवेल, पाइपलाइन और अन्य अचल संपत्तियों का रिकॉर्ड ड्रोन सर्वे के माध्यम से तैयार किया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य मुआवजे के निर्धारण में निष्पक्षता सुनिश्चित करना, अनावश्यक विवादों को कम करना और विकास परियोजनाओं की गति तेज करना है।

नई व्यवस्था गमाडा की सभी वर्तमान और आगामी भूमि अधिग्रहण आधारित परियोजनाओं पर लागू होगी। इनमें एयरोट्रोपोलिस, ईको सिटी-3, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं, जिनके तहत हजारों एकड़ भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है। अधिकारियों का मानना है कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय बनेगी और किसानों व जमीन मालिकों का भरोसा भी बढ़ेगा।

अब तक भूमि अधिग्रहण के दौरान मकानों, पेड़ों, बागों और अन्य स्थायी संपत्तियों के मूल्यांकन को लेकर कई बार विवाद सामने आते रहे हैं। कई मामलों में मुआवजे की राशि को लेकर आपत्तियां दर्ज होती थीं, जिससे परियोजनाओं में देरी होती थी। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने ड्रोन सर्वे को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है।

नई गाइडलाइन के अनुसार गमाडा का मुख्य अभियंता किसी अधिकृत बाहरी एजेंसी के माध्यम से ड्रोन सर्वे करवाएगा। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों में ड्रोन से उच्च गुणवत्ता की तस्वीरें और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किए जाएंगे। इन रिकॉर्ड के आधार पर प्रत्येक मकान, पेड़, बाग, ट्यूबवेल और अन्य अचल संपत्ति का विस्तृत दस्तावेजीकरण किया जाएगा, जिससे बाद में किसी प्रकार के विवाद की संभावना कम रहेगी।

ड्रोन सर्वे के बाद गमाडा के बागवानी, सिविल और पब्लिक हेल्थ विंग के वरिष्ठ अधिकारियों की संयुक्त समिति सर्वे रिपोर्ट का सत्यापन करेगी। इसके बाद संबंधित विभाग अपनी विशेषज्ञता के अनुसार अंतिम मूल्यांकन करेंगे। भवनों का मूल्यांकन लोक निर्माण विभाग करेगा, जबकि ट्यूबवेल, पाइपलाइन और जल संबंधी ढांचे का आकलन सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग करेगा। फलदार पेड़ों और बागों का मूल्यांकन बागवानी विभाग तथा अन्य पेड़ों का मूल्यांकन वन विभाग द्वारा किया जाएगा। इस बहु-स्तरीय प्रक्रिया से मुआवजा तय करने में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

साठ वर्षों से इतिहास और विरासत सहेजे हुए है द्वारका लाइब्रेरी

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-15 स्थित लाजपत राय भवन की द्वारका दास लाइब्रेरी अपने 60 वर्ष पूरे होने का जश्न 29 अगस्त को मनाएगी। यह ऐतिहासिक पुस्तकालय केवल पुस्तकों का संग्रह नहीं, बल्कि देश के विभाजन, स्वतंत्रता आंदोलन और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत दस्तावेज भी है। लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित यह लाइब्रेरी विभाजन के बाद शिमला होते हुए वर्ष 1966 में चंडीगढ़ पहुंची और तभी से अपनी ऐतिहासिक धरोहर को संजोए हुए है।

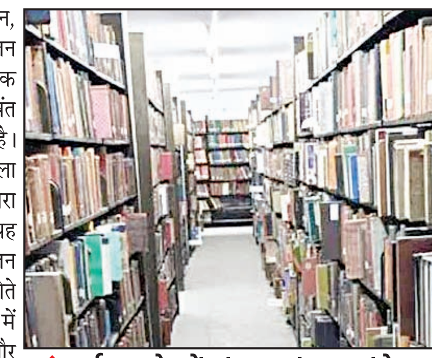

◆ दुर्लभ धरोहरों संग स्वतंत्रता आंदोलन की अमूल्य विरासत आज भी सुरक्षित है

लाइब्रेरियन अलका ने बताया कि 28 अगस्त को लाइब्रेरी के 60 वर्ष पूरे होंगे, जबकि 29 अगस्त को पूरे दिन विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आयोजन का उद्देश्य लोगों, विशेषकर युवाओं को आजादी के इतिहास, स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान और इस ऐतिहासिक पुस्तकालय की विरासत से परिचित कराना है। कार्यक्रम में परिचर्चा, सम्मान समारोह और पुराने सदस्यों के अनुभव साझा करने जैसे आयोजन होंगे। लाइब्रेरी में लगभग 90 हजार पुस्तकें सुरक्षित हैं। इनमें शहीद भगत सिंह द्वारा पढ़ी गई पुस्तकें, लाला लाजपत राय के वस्त्र, उनके निजी उपयोग की सामग्री, गोपाल कृष्ण गोखले को लिखे गए पत्र, दुर्लभ दस्तावेज और ऐतिहासिक तस्वीरें शामिल हैं।

चंडीगढ़ के उद्योगों को बड़ी सौगात, एफएआर बढ़ेगा, कारोबार को मिलेगी नई उड़ान

एफएआर बढ़ने, नई व्यावसायिक गतिविधियों और फैक्ट्री आउटलेट की मंजूरी से उद्योग विस्तार तथा निवेश को मिलेगा बढ़ावा

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

केंद्र सरकार जल्द ही चंडीगढ़ के उद्योगपतियों को बड़ी राहत देने जा रही है। प्रशासन की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजे गए औद्योगिक सुधार संबंधी प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी मिलने की संभावना है। प्रशासक गुलाब चंद कटारिया स्वयं इस मामले की निगरानी कर रहे हैं और गृह मंत्रालय के संपर्क में हैं। उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया गया है कि प्रस्ताव को जल्द स्वीकृति मिल सकती है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में कारोबार विस्तार और नए निवेश का रास्ता खुलेगा।

प्रस्ताव के अनुसार इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 और फेज-2 में फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) को वर्तमान 0.75 से बढ़ाकर 2 किया जाएगा, जबकि फेज-3 में इसे 2.50 तक करने का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त व्यावसायिक गतिविधियों और सेवा आधारित कारोबार को भी अनुमति देने की सिफारिश की गई है। सेंट्रल कोर्टयार्ड की अनिवार्यता समाप्त कर आगे और पीछे सेटबैक का प्रावधान लागू करने का प्रस्ताव भी शामिल है। इससे उद्योगपतियों को अतिरिक्त निर्माण क्षेत्र मिलेगा और वे अपने कारोबार का विस्तार कर सकेंगे।

प्रशासन के अनुसार गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद एफएआर बढ़ाने के लिए लागू होने वाले शुल्क का निर्धारण किया जाएगा। इसके लिए अलग से समिति गठित होगी। एफएआर बढ़ने से प्लॉटों का उपयोग क्षेत्र बढ़ेगा, जिससे उद्योगों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। साथ ही प्रशासन के राजस्व में भी इजाफा होने की उम्मीद है।

एफएआर बढ़ाने का मुद्दा संसद में भी उठ चुका है। सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में इस विषय पर सवाल उठाया था। इसके बाद प्रशासक के निर्देश पर गठित 11 सदस्यीय समिति ने उद्योगपतियों से चर्चा कर अपनी रिपोर्ट तैयार की और राहत संबंधी सिफारिशें प्रशासन को सौंपीं।

नई नीति के तहत उद्योगपतियों को फैक्ट्री आउटलेट खोलने की अनुमति भी मिलने की संभावना है। इससे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा और 'लोकल टू वोकल' अभियान को मजबूती मिलेगी। प्रशासन का मानना है कि इससे चंडीगढ़ की औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी और निवेश आकर्षित होगा।

एफएआर बढ़ने का एक बड़ा लाभ यह भी होगा कि भवन उपयोग से जुड़े कई लंबित मिसयूज और उल्लंघन संबंधी मामलों का समाधान हो सकेगा।

उद्योगों के लिए खुलेंगे विकास के नए द्वार

उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि एफएआर बढ़ने से चंडीगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में लंबे समय से रुकी विस्तार योजनाओं को नई गति मिलेगी। जिन उद्योगों के पास सीमित निर्माण क्षेत्र होने के कारण उत्पादन क्षमता बढ़ाने की गुंजाइश नहीं थी, उन्हें अब अतिरिक्त मंजिलें और आधुनिक सुविधाएं विकसित करने का अवसर मिलेगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के साथ-साथ सेवा क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों को भी सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रशासन का कहना है कि नई नीति लागू होने के बाद उद्योगों को अपने व्यवसाय के अनुरूप भवनों का बेहतर उपयोग करने की सुविधा मिलेगी। इससे नए उद्यमियों को भी चंडीगढ़ में निवेश के लिए आकर्षक माहौल मिलेगा। औद्योगिक क्षेत्र में आधुनिक कार्यालय, शोरूम, वेयरहाउस और सर्विस सेंटर विकसित होने से आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उद्योग संगठनों ने सुझाव दिया है कि मंजूरी की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और समयबद्ध बनाया जाए, ताकि उद्यमियों को अनावश्यक औपचारिकताओं का सामना न करना पड़े।

देश सेवा के बाद अंगदान से छह जिंदगियों में भरी नई सांसें

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

भारतीय सेना के नायब रिसालदार वीरेंद्र सिंह ने मातृभूमि की सेवा करते हुए अपना जीवन तो खो दिया, लेकिन अपने अंगदान के माध्यम से छह लोगों को नई जिंदगी देकर मानवता की ऐसी मिसाल पेश की, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। उनका यह प्रेरक निर्णय और उनकी पत्नी कुसुम का साहस समाज के लिए एक संदेश बनकर सामने आया है कि मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन में नई उम्मीद जगाई जा सकती है।

जानकारी के अनुसार, नायब रिसालदार वीरेंद्र सिंह लद्दाख में समुद्र तल से करीब 16 हजार फीट की ऊंचाई पर तैनात थे। ड्यूटी के दौरान उन्हें अचानक ब्रेन स्ट्रोक आया। सेना की मेडिकल टीम ने तत्काल प्राथमिक उपचार देकर उन्हें एयरलिफ्ट किया और 16 जुलाई को चंडीमंदिर स्थित कमांड अस्पताल (वेस्टर्न कमांड) में भर्ती कराया। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने कई दिनों तक लगातार उनका उपचार किया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। 21 जुलाई को डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया।

इस कठिन और भावुक समय में उनकी पत्नी कुसुम ने बेहद साहसिक निर्णय लेते हुए अपने पति के अंगदान की अनुमति दी। इसके बाद वीरेंद्र सिंह के दोनों गुर्दे, लीवर, दोनों फेफड़े और दोनों कॉर्निया सुरक्षित निकालकर प्रत्यारोपण के लिए अलग-अलग अस्पतालों में भेजे गए। इस फैसले से छह जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन मिलने की उम्मीद जगी।

कमांड अस्पताल (वेस्टर्न कमांड) के इतिहास में यह पहला अवसर रहा, जब सफलतापूर्वक फेफड़ों को सुरक्षित निकालकर प्रत्यारोपण के लिए भेजा गया। इसे अस्पताल की एक महत्वपूर्ण चिकित्सा उपलब्धि माना जा रहा है। सभी अंगों का आवंटन राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण नेटवर्क के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया।

एक किडनी और दोनों कॉर्निया का प्रत्यारोपण कमांड अस्पताल में ही किया गया। दूसरी किडनी हरियाणा के स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन (सोटो) को भेजी गई।

मुख्यमंत्री सेहत योजना बनी कैंसर मरीजों की जीवनदायिनी

8069 कैंसर मरीजों को मिला कैशलेस उपचार, सरकार ने खर्च किए 20.22 करोड़ रुपए, हजारों परिवारों को मिली आर्थिक राहत

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना कैंसर मरीजों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। योजना के तहत अब तक हजारों मरीजों को कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए), पंजाब के आंकड़ों के अनुसार, 18 जुलाई 2026 तक मुख्यमंत्री सेहत योजना के अंतर्गत 8069 कैंसर मरीजों का इलाज किया जा चुका है। इन मरीजों के उपचार पर सरकार ने कुल 20.22 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

योजना के आंकड़े बताते हैं कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए आर्थिक सहायता बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रही है। कैंसर उपचार में सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और टार्गेटेड थेरेपी जैसी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, इलाज की बढ़ती लागत कई परिवारों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। ऐसे में कैशलेस इलाज की सुविधा मरीजों और उनके परिवारों के लिए राहत लेकर आई है। आंकड़ों के अनुसार, मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत इलाज करवाने वाले मरीजों में सबसे अधिक संख्या 36 से 60 वर्ष आयु वर्ग की रही। कुल 8069 मरीजों में से 4285 मरीज इसी आयु वर्ग के हैं। वहीं 3376 मरीज 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं। इसके अलावा 399 मरीज 17 से 35 वर्ष आयु वर्ग के और नौ मरीज 17 वर्ष से कम आयु के शामिल हैं।

यह आंकड़े इस बात की ओर भी संकेत करते हैं कि कैंसर केवल बुजुर्गों तक सीमित बीमारी नहीं है, बल्कि बड़ी संख्या में लोग अपनी कार्यशील आयु में भी इस गंभीर बीमारी से प्रभावित हो रहे हैं। बीमारी के कारण इलाज, नौकरी, परिवार और आर्थिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना मरीजों और उनके परिवारों के लिए कठिन हो जाता है।

कैंसर इलाज का खर्च कई परिवारों के लिए आर्थिक संकट पैदा कर सकता है। बार-बार अस्पताल जाना, महंगी जांच, सर्जरी और लंबे समय तक चलने वाले उपचार के कारण परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ता है। मुख्यमंत्री सेहत योजना ने ऐसे मरीजों को इलाज की सबसे बड़ी बाधा यानी खर्च से राहत देने का काम किया है।

समाना निवासी दर्शन देवी भी इस योजना से लाभान्वित हुईं। बढ़ते दर्द के बाद डॉक्टरों ने उन्हें सर्जरी कराने की सलाह दी थी। इलाज का अनुमानित खर्च करीब चार से पांच लाख रुपये बताया गया था, जिससे उनका परिवार चिंतित था। मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत मंजूरी मिलने के बाद उनकी कैंसर सर्जरी बिना किसी अतिरिक्त खर्च के पूरी हो सकी।

आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में कैंसर उपचार की जरूरत पूरे वर्ष बनी रही। जनवरी में 842 मरीजों का इलाज किया गया। फरवरी में यह संख्या बढ़कर 1080, मार्च में 1175 और अप्रैल में 1350 पहुंच गई। मई में 1275 मरीजों का उपचार हुआ, जबकि जून महीने में सबसे अधिक 1468 मरीजों को योजना का लाभ मिला। जुलाई के शुरुआती 18 दिनों में ही 879 मरीजों का इलाज किया जा चुका है।

स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि मुख्यमंत्री सेहत योजना का उद्देश्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को समय पर गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराना है। सरकार का प्रयास है कि आर्थिक स्थिति किसी भी मरीज के इलाज में बाधा न बने और जरूरतमंद लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, मुख्यमंत्री सेहत योजना के माध्यम से प्रदेश में गंभीर बीमारियों के इलाज को अधिक सुलभ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। योजना के तहत पंजीकृत अस्पतालों में पात्र मरीजों को निर्धारित नियमों के अनुसार कैशलेस उपचार की सुविधा दी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और बेहतर निगरानी पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद मरीजों को इसका लाभ मिल सके।

एसआईआर अभियान में पंजाब में अव्वल रहा धर्मकोट

निर्वाचन आयोग ने ईआरओ गुरविंदर सिंह जौहल को किया सम्मानित

भारतेंदु संवाददाता, धर्मकोट (मोगा)। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) अभियान में मोगा जिले के धर्मकोट विधानसभा क्षेत्र ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। धर्मकोट विधानसभा क्षेत्र ने पूरे पंजाब में सबसे पहले इस अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

इस उपलब्धि के लिए पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) धर्मकोट गुरविंदर सिंह जौहल को विशेष रूप से सम्मानित किया। सम्मान समारोह के दौरान मुख्य चुनाव अधिकारी ने अभियान को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए जौहल और उनकी पूरी टीम के प्रयासों की सराहना की।

अनिंदिता मित्रा ने कहा कि धर्मकोट विधानसभा क्षेत्र की यह सफलता बेहतर योजना, प्रभावी नेतृत्व, अधिकारियों के बीच तालमेल और चुनावी कर्मचारियों की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के शुद्ध और पारदर्शी अद्यतन के लिए एसआईआर अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और धर्मकोट की टीम ने इसे पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा किया है। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी गुरविंदर सिंह जौहल ने सम्मान मिलने पर इसका श्रेय डिप्टी कमिश्नर मोगा सागर सेतिया के मार्गदर्शन और अभियान से जुड़े सभी अधिकारियों, सुपरवाइजरों, बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) तथा कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों को दिया। उन्होंने कहा कि पूरी टीम ने समर्पण और जिम्मेदारी के साथ काम करते हुए अभियान को समय पर पूरा किया।

बेहतरीन प्रबंधन और टीमवर्क से धर्मकोट ने हासिल की बड़ी उपलब्धि

डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया ने भी गुरविंदर सिंह जौहल और पूरी चुनावी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि धर्मकोट विधानसभा क्षेत्र का पूरे पंजाब में प्रथम स्थान हासिल करना मोगा जिले के लिए गर्व की बात है। यह उपलब्धि टीम भावना, बेहतर प्रबंधन और कर्मचारियों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का सही और पारदर्शी रूप से तैयार होना लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए बेहद जरूरी है। एसआईआर अभियान के माध्यम से मतदाताओं से जुड़ी जानकारी को व्यवस्थित और अद्यतन किया जाता है, जिससे चुनाव प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष और प्रभावी बनती है। डिप्टी कमिश्नर ने अभियान से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस तरह की उपलब्धियां प्रशासनिक टीमों को भविष्य में भी बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं।

आदमपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ी, पुलिस ने चलाया एंटी-सबोटाज चेकिंग अभियान

बम निरोधक दस्ते ने जांचा परिसर, सुरक्षा मानकों का पालन किया सुनिश्चित

भारतेंदु संवाददाता, जालंधर। जालंधर ग्रामीण पुलिस ने आदमपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक एंटी-सबोटाज चैकिंग अभियान चलाया। यह अभियान एसएसपी हरविंदर सिंह विर्क के दिशा-निर्देशों पर संचालित किया गया, जिसमें पुलिस टीमों और सुरक्षा एजेंसियों ने एयरपोर्ट परिसर के संवेदनशील क्षेत्रों की गहन जांच की।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मौजूदा सुरक्षा परिस्थितियों को देखते हुए महत्वपूर्ण स्थानों पर नियमित रूप से सुरक्षा जांच और ऑडिट किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आदमपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों ने प्रवेश और निकास द्वार, पार्किंग क्षेत्र, यात्री टर्मिनल, बैगेज एरिया सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की बारीकी से जांच की। चैकिंग अभियान के दौरान बम निरोधक दस्ते और अन्य सुरक्षा इकाइयों ने आधुनिक उपकरणों की मदद से पूरे एयरपोर्ट परिसर को खंगाला। सुरक्षा कर्मियों ने संदिग्ध वस्तुओं और गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया गया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान एयरपोर्ट परिसर में किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु या गतिविधि सामने नहीं आई। अभियान शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सामान्य पाई गई। एसएसपी हरविंदर सिंह विर्क ने कहा कि जालंधर ग्रामीण पुलिस आम लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील स्थानों पर समय-समय पर एंटी-सबोटाज चैकिंग और सुरक्षा अभ्यास किए जाते हैं, ताकि किसी भी संभावित खतरे से पहले ही निपटा जा सके।

उन्होंने लोगों से अपील की कि वे भी सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें। यदि किसी व्यक्ति को कहीं संदिग्ध वस्तु, व्यक्ति या गतिविधि दिखाई देती है तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम या नजदीकी पुलिस थाने को दें। उन्होंने कहा कि समय पर सूचना मिलने से किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सकता है।

नियम विरुद्ध टायर लगाने पर थार चालक पर कार्रवाई

भारतेंदु संवाददाता, लुधियाना। शहर में वाहन में नियमों के विपरीत बदलाव कराना एक युवक को महंगा पड़ गया। मॉडल टाउन निवासी युवक ने अपनी थार गाड़ी में निर्धारित मानकों से बड़े और चौड़े टायर लगवा रखे थे। इसकी शिकायत सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस विभाग तक पहुंची, जिसके बाद यातायात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन का चालान कर दिया। जानकारी के अनुसार शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने वाहन के पंजीकरण नंबर के आधार पर उसकी पहचान की। जांच में पाया गया कि वाहन में लगाए गए टायर निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थे। इसके बाद संबंधित युवक के खिलाफ वाहन में अवैध संशोधन करने के आरोप में पांच हजार रुपये का चालान किया गया। यातायात पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मोटर वाहन कानून के तहत किसी भी वाहन में निर्माता कंपनी द्वारा निर्धारित मापदंडों से अलग टायर या अन्य बदलाव बिना अनुमति नहीं किए जा सकते।

पंजाब में मानसून सक्रिय, भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी

27 से 29 जुलाई तक तेज बारिश और जलभराव की संभावना

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। उत्तर भारत में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। पंजाब के कई जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान अच्छी बारिश दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया और लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिली है। कई क्षेत्रों में तेज हवाओं, गरज-चमक और बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।

मौसम विभाग के अनुसार पंजाब में आने वाले दिनों में मानसूनी गतिविधियां लगातार जारी रहने की संभावना है। जालंधर सहित प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया गया है। वहीं, चंडीगढ़ मौसम विज्ञान केंद्र ने पंजाब और चंडीगढ़ के लिए 27 से 29 जुलाई तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि इस दौरान कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव की समस्या भी सामने आ सकती है। प्रशासन को भी संभावित परिस्थितियों को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

खराब मौसम में सावधानी बरतें, अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित रहें

बारिश के कारण जहां किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं शहरों में जल निकासी व्यवस्था को लेकर चुनौती बढ़ सकती है। कई क्षेत्रों में सड़क किनारे पानी जमा होने और यातायात प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की अपील की गई है।

मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और बिना जरूरी काम के घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। विभाग के अनुसार यदि मानसून की सक्रियता इसी तरह बनी रही तो आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से अधिक राहत मिलेगी।

विशेषज्ञों के अनुसार मानसूनी बारिश से जल स्रोतों में सुधार होगा और कृषि क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा। हालांकि, भारी बारिश के दौरान बिजली गिरने, तेज हवाओं और जलभराव जैसी परिस्थितियों से बचने के लिए लोगों को सावधानी बरतनी होगी।

लुधियाना केंद्रीय जेल में छह मोबाइल बरामद, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

भारतेंदु संवाददाता लुधियाना। लुधियाना की केंद्रीय जेल में विशेष तलाशी अभियान के दौरान बंदियों के पास से छह मोबाइल फोन बरामद होने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। घटना ने एक बार फिर जेल की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बरामद मोबाइल फोन अलग-अलग कंपनियों के बताए जा रहे हैं, जिनका उपयोग बंदी कथित रूप से अवैध रूप से कर रहे थे।

जानकारी के अनुसार सहायक सुपरिंटेंडेंट सुखपाल सिंह के नेतृत्व में जेल परिसर में अचानक तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान विभिन्न बैरकों में बंद हवालातियों की तलाशी लेने पर छह मोबाइल फोन बरामद हुए। जेल नियमों के अनुसार किसी भी बंदी के पास मोबाइल फोन रखना पूरी तरह प्रतिबंधित है, इसके बावजूद इन उपकरणों का मिलना सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक माना जा रहा है।

जेल प्रशासन की शिकायत पर थाना डिवीजन नंबर-7 पुलिस ने हरपिंदर सिंह उर्फ शिंदा, सरबजीत सिंह उर्फ सरबा, जय कुमार उर्फ जय देव शर्मा तथा सुखविंदर सिंह के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद मोबाइल फोन जेल के भीतर कैसे पहुंचे।

सीआईए स्टाफ की कार्रवाई में हथियार और मोबाइल भी बरामद

तरनतारन में तीन किलो हेरोइन और दो पिस्तौल के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

भारतेंदु संवाददाता, तरनतारन। सीआईए स्टाफ तरनतारन पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 किलो 116 ग्राम हेरोइन, एक 30 बोर पिस्तौल, एक 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल, दो मोबाइल फोन तथा एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की है। इस संबंध में थाना खालड़ा में आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सीआईए स्टाफ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर गांव बासरके की दाना मंडी के पास नाकाबंदी की हुई थी। इसी दौरान बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध युवकों को रोककर तलाशी ली गई। जांच के दौरान उनके पास से भारी मात्रा में हेरोइन और दो अवैध पिस्तौल बरामद हुए।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जगदीप सिंह पुत्र तेगा सिंह निवासी गांव डुगरी तथा आकाशदीप सिंह पुत्र हरदेव सिंह निवासी गांव माड़ी उदोके, जिला तरनतारन के रूप में हुई है।

विदेश भेजने के नाम पर लाखों की ठगी, केस दर्ज

भारतेंदु संवाददाता, गुरदासपुर। विदेश भेजने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपये की ठगी करने के आरोप में गुरदासपुर पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में केस दर्ज किए हैं। पुलिस ने शिकायतों की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों मामलों में आरोप है कि विदेश जाने की इच्छा रखने वाले लोगों से फर्जी वादे कर बड़ी रकम ऐंठी गई। पहले मामले में थाना दोरांगला पुलिस ने गांव शाहपुर अफगाना निवासी बिक्रमजीत सिंह की शिकायत पर कुलविंदर सिंह निवासी कलानौर तथा करतार सिंह और अवतार सिंह निवासी गांव भैणी खादर के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

शराब के नशे में मंदिर में हंगामा, आरोपी से तलवारें और पुलिस वर्दी हुई बरामद

भारतेंदु संवाददाता, फगवाड़ा। फगवाड़ा के पॉश इलाके मॉडल टाउन स्थित प्रसिद्ध श्री गीता भवन मंदिर में एक व्यक्ति द्वारा शराब के नशे में हंगामा करने और धार्मिक स्थल की मर्यादा भंग करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद मंदिर परिसर में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, आरोपी शराब के अत्यधिक नशे में मंदिर परिसर में पहुंचा और वहां सफाई कर रहे कर्मचारियों तथा सेवादारों के साथ अभद्र व्यवहार करने लगा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उसने धक्का-मुक्की करते हुए मंदिर के शांतिपूर्ण वातावरण को बाधित किया, जिससे श्रद्धालुओं में रोष फैल गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे काबू कर लिया और घटना की सूचना फगवाड़ा के विधायक बलविंदर सिंह धालीवाल को दी।

सूचना मिलते ही विधायक बलविंदर सिंह धालीवाल अपने सहयोगियों के साथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और पुलिस अधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नरेश भारद्वाज ने बताया कि सूचना मिलने पर वे भी मौके पर पहुंचे थे।

नीट परीक्षा में अनियमितताओं के विरोध में आज जालंधर में होगा छात्रों का बड़ा प्रदर्शन

भारतेंदु संवाददाता, जालंधर। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं, प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा व्यवस्था में कथित खामियों के विरोध में युवा कांग्रेस (जालंधर शहरी) ने आज शहर में दो चरणों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। युवा कांग्रेस के जालंधर शहरी अध्यक्ष अंगद दत्ता ने विद्यार्थियों, युवा संगठनों और जागरूक नागरिकों से बड़ी संख्या में शामिल होकर विद्यार्थियों के अधिकारों के समर्थन में आवाज उठाने की अपील की है।

अंगद दत्ता ने कहा कि देशभर के लाखों विद्यार्थी वर्षों की मेहनत और लगन से अपने भविष्य का सपना देखते हैं, लेकिन परीक्षा प्रणाली में सामने आ रही अनियमितताएं और प्रशासनिक लापरवाही उनकी मेहनत पर प्रश्नचिह्न लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी का अधिकार है तथा इसके लिए जवाबदेही तय होना आवश्यक है। आज का पहला कार्यक्रम सुबह नौ बजे तहसील परिसर के सामने स्थित पूडा मैदान में आयोजित होगा, जहां विद्यार्थी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद शाम साढ़े पांच बजे नारे और बैनरों के साथ मार्च निकाला जाएगा। इसी दौरान 26 जुलाई को प्रस्तावित राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थन में 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल की घोषणा भी की जाएगी।

इसके अलावा 'शोर और झूठ नहीं, हमें सच चाहिए' अभियान के तहत निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता की मांग उठाई जाएगी। वहीं 'नीट प्रश्नपत्र लीक जन आक्रोश प्रदर्शन' कंपनी बाग चौक में आयोजित किया जाएगा।

प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का पुनर्गठन, नीट मामले पर संसद में विस्तृत चर्चा, प्रश्नपत्र लीक के आरोपितों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई तथा प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर बल प्रयोग के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई शामिल है। अंगद दत्ता ने विद्यार्थियों और युवाओं से लोकतांत्रिक तथा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के भविष्य की सुरक्षा और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।

कार्रवाई 14 अस्पतालों पर जुर्माना, छह मरीजों को लौटाई गई अवैध वसूली की राशि

फर्जीवाड़े पर सख्ती, सर्वोदय अस्पताल मुख्यमंत्री सेहत योजना से बाहर

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना (एमएमएसवाई) में कथित अनियमितताओं और फर्जीवाड़े के आरोपों को लेकर सख्त कार्रवाई की है। सरकार ने जालंधर स्थित सर्वोदय अस्पताल को मुख्यमंत्री सेहत योजना के पैनल से बाहर कर दिया है। अब यह अस्पताल इस योजना के तहत मरीजों को कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकेगा।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि सर्वोदय अस्पताल के खिलाफ योजना के नियमों के उल्लंघन और कथित धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों की विभागीय स्तर पर जांच कराई गई। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल को योजना से डी-एम्पैनल करने का निर्णय लिया गया।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री सेहत योजना में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, फर्जीवाड़े या मरीजों के अधिकारों से खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनियमितताओं में शामिल किसी भी व्यक्ति या संस्थान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि केवल सर्वोदय अस्पताल पर कार्रवाई ही नहीं की गई है, बल्कि राज्यभर में योजना के तहत सूचीबद्ध 14 अन्य अस्पतालों पर भी नियमों के उल्लंघन के मामले में कुल 78.67 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा जांच के दौरान छह मरीजों के परिजनों से कथित तौर पर अवैध रूप से वसूली गई राशि भी वापस करवाई गई है।

सरकार ने स्वास्थ्य योजना में पारदर्शिता के लिए बढ़ाई सख्त निगरानी

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत मरीजों को बेहतर और निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए योजना से जुड़े सभी अस्पतालों का नियमित ऑडिट, निरीक्षण और निगरानी की जा रही है। यदि किसी अस्पताल में मरीजों से अतिरिक्त पैसे लेने, फर्जी दस्तावेज तैयार करने या योजना के नियमों की अनदेखी करने जैसी शिकायतें सामने आती हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मुख्यमंत्री सेहत योजना का लाभ जरूरतमंद और पात्र मरीजों तक पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ पहुंचे। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि यदि किसी अस्पताल में योजना से जुड़ी कोई अनियमितता सामने आती है तो उसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग को तुरंत दें, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके।

भगवान शनि का संदेश, अच्छे कर्म, धैर्य और ईमानदारी से ही मिलती है जीवन में सच्ची सफलता

सप्ताह के सातों दिनों का अपना अलग महत्व है, लेकिन शनिवार एक ऐसा दिन है जो धार्मिक आस्था, सामाजिक जीवन और आधुनिक जीवनशैली तीनों को एक साथ जोड़ता है। भारतीय संस्कृति में शनिवार को न्याय, अनुशासन, धैर्य और कर्म का प्रतीक माना गया है। वहीं आधुनिक समय में यह दिन व्यस्त जीवन से कुछ पल निकालकर स्वयं, परिवार और समाज के लिए समय देने का अवसर भी बन गया है। यही कारण है कि शनिवार केवल कैलेंडर का एक दिन नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित करने का संदेश देने वाला विशेष अवसर माना जाता है।

आज की तेज रफ्तार दुनिया में अधिकांश लोग पूरे सप्ताह काम, पढ़ाई और जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते हैं। लगातार काम करने से मानसिक और शारीरिक थकान बढ़ जाती है। ऐसे में शनिवार व्यक्ति को अपनी दिनचर्या पर दोबारा विचार करने का अवसर देता है। यह दिन यह सोचने का समय है कि बीते सप्ताह में हमने क्या सीखा, कौन-सी गलतियां कीं और आने वाले सप्ताह को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। आत्ममंथन की यही प्रक्रिया व्यक्ति को निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।

भारतीय समाज में शनिवार का संबंध भगवान शनि से जोड़ा जाता है। शनि देव को कर्म और न्याय का देवता कहा गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वे किसी भी व्यक्ति के साथ पक्षपात नहीं करते, बल्कि उसके कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। इस विचार का सबसे बड़ा संदेश यह है कि जीवन में सफलता पाने के लिए ईमानदारी, मेहनत और अनुशासन आवश्यक हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करता है तो उसे देर-सवेर उसका उचित फल अवश्य मिलता है। यही सोच भारतीय संस्कृति में कर्मयोग की भावना को मजबूत करती है।

शनिवार को भगवान हनुमान की पूजा का भी विशेष महत्व माना जाता है। देशभर के हनुमान मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई देती है। लोग हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करते हैं तथा अपने परिवार की सुख-समृद्धि और सुरक्षा की कामना करते हैं। धार्मिक दृष्टि से यह दिन लोगों में आस्था और विश्वास को मजबूत करता है। वहीं सामाजिक दृष्टि से मंदिरों में होने वाले सामूहिक कार्यक्रम लोगों के बीच एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ाते हैं।

दान और सेवा की परंपरा भी शनिवार को विशेष बनाती है। अनेक लोग इस दिन जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, फल या अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करते हैं। कई स्थानों पर सामूहिक भंडारों का आयोजन किया जाता है, जहां हर वर्ग के लोगों को सम्मानपूर्वक भोजन कराया जाता है।

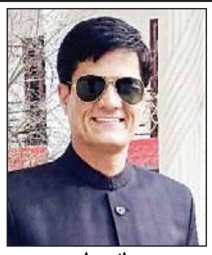

लकेश चंदेल
अध्यापक, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश

समाज सेवा का यह भाव भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है। जब समाज का सक्षम वर्ग जरूरतमंद लोगों की सहायता करता है, तब सामाजिक समानता और मानवीय संवेदनाएं मजबूत होती हैं।

यदि शनिवार को वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो इसका महत्व और भी स्पष्ट हो जाता है। लगातार कई दिनों तक काम करने के बाद शरीर और मस्तिष्क को विश्राम की आवश्यकता होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि पर्याप्त आराम, अच्छी नींद और परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक तनाव को कम करता है। शनिवार का उपयोग यदि योग, ध्यान, व्यायाम या प्रकृति के बीच समय बिताने में किया जाए तो यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है।

आज डिजिटल युग में अधिकांश लोग मोबाइल फोन, कंप्यूटर और इंटरनेट पर बहुत अधिक समय बिताते हैं। इसके कारण तनाव, अनिद्रा और आंखों से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं। शनिवार डिजिटल जीवन से थोड़ी दूरी बनाकर वास्तविक जीवन से जुड़ने का अवसर भी प्रदान करता है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

जब युवा ठान लें बदलाव का संकल्प, तब हर चुनौती बन जाती है विकास का नया अवसर

युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। उनमें कठिन परिस्थितियों से लड़ने की अद्भुत क्षमता, सहनशक्ति और कुछ नया कर दिखाने का जुनून होता है। यदि युवा किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प कर लें, तो बड़े से बड़े कठिन कार्यों को भी पूरा कर सकते हैं। उनकी ऊर्जा और इच्छाशक्ति समाज, प्रदेश और देश में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में हर वर्ष मौसम की कठिन परिस्थितियां, प्राकृतिक आपदाएं और भौगोलिक चुनौतियां सामने आती रहती हैं। इसके बावजूद यहां के युवाओं में ऐसी शक्ति और साहस दिखाई देता है, जो कठिन परिस्थितियों को अवसर में बदलने का कार्य करता है। केवल मजबूत मनोबल, मानसिक शक्ति और कार्य करने की इच्छा से बड़े बदलाव संभव हैं। आज समाज में युवाओं के दो अलग-अलग रूप दिखाई देते हैं। एक ओर ऐसे युवा हैं जो नशे और मोबाइल की दुनिया में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे युवा भी हैं जो पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सेवा और समाज सुधार के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के कासरी क्षेत्र के युवाओं का उदाहरण बताता है कि जब युवा अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, तो वे किसी भी समस्या का समाधान खोज सकते हैं।

जब किसी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा या कठिन परिस्थिति आती है, तो अक्सर लोग प्रशासन की सहायता का इंतजार करते हैं। प्रशासनिक कार्यों में निश्चित प्रक्रिया होने के कारण कभी-कभी समय लग सकता है। ऐसे समय में यदि स्थानीय लोग और युवा स्वयं आगे बढ़कर सहयोग करें, तो बड़ी समस्याओं को कम किया जा सकता है। कासरी के युवाओं ने इसी भावना का परिचय देते हुए लकड़ी के सहारे अस्थायी पुल बनाकर लोगों की आवाजाही को आसान बनाया।

उनका यह प्रयास केवल एक समस्या का समाधान नहीं था, बल्कि एकता, जिम्मेदारी और आत्मनिर्भरता का उदाहरण भी था। आज देश में बड़ी संख्या में युवा शिक्षा, साहित्य, प्रशासन, विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। वे अपने सपनों को पूरा करने के साथ-साथ समाज और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की क्षमता रखते हैं। आने वाले वर्षों में ऐसा युवा वर्ग सामने आएगा, जो केवल शिक्षित ही नहीं बल्कि संस्कारी, जिम्मेदार और सही निर्णय लेने में सक्षम होगा।

हालांकि युवाओं के एक वर्ग में नशे, अत्यधिक मोबाइल उपयोग और आभासी दुनिया की बढ़ती निर्भरता चिंता का विषय है। आवश्यकता है कि युवा अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं। उन्हें अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों को भी समझना होगा।

डॉ. सत्यवान सौरभ
सामाजिक विचारक

बुजुर्गों का सम्मान, छोटे लोगों के प्रति प्रेम और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना ही एक मजबूत राष्ट्र का आधार बन सकती है। युवाओं को यह समझना होगा कि बदलाव के लिए किसी चमत्कार या किसी बाहरी सहायता का इंतजार करने के बजाय स्वयं आगे बढ़ना होगा। जब युवा अपने आसपास की समस्याओं को अपनी समस्या समझकर समाधान के लिए कदम उठाते हैं, तो समाज में वास्तविक परिवर्तन आता है।

युवाओं में पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सुधार और राष्ट्र निर्माण की दिशा बदलने की क्षमता होती है। यदि युवा जागरूक, संगठित और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ें, तो वे समाज की अनेक समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। उनके छोटे-छोटे सकारात्मक प्रयास बड़े बदलाव का आधार बनते हैं। इसलिए युवाओं को अपनी ऊर्जा, प्रतिभा, साहस और रचनात्मक सोच का उपयोग देश, समाज और पर्यावरण के विकास में करना चाहिए। यही युवा शक्ति एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण की सबसे बड़ी नींव बन सकती है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

अकेलापन कई बार अपने आप से सार्थक बातें करता है। वैसी सार्थकता भीड़ में या भीड़ के चिंतन में नहीं मिलती।

-राजेंद्र अवस्थी

संपादकीय

सड़क सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी

भारत दुनिया के सबसे बड़े सड़क नेटवर्क वाले देशों में से एक है। हर दिन करोड़ों लोग निजी वाहनों, सार्वजनिक परिवहन और मालवाहक साधनों के माध्यम से यात्रा करते हैं। सड़कें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा होती हैं, लेकिन यही सड़कें तब चिंता का कारण बन जाती हैं जब उन पर होने वाले हादसे हजारों परिवारों की खुशियां छीन लेते हैं। सड़क दुर्घटनाएं केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि वे असमय समाप्त हो जाने वाले जीवन, टूटते परिवारों और समाज पर पड़ने वाले गहरे आर्थिक तथा मानसिक प्रभाव की कहानी हैं। वर्षों से सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान चलाए जा रहे हैं, नियम बनाए जा रहे हैं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, फिर भी दुर्घटनाओं की संख्या अपेक्षित गति से कम नहीं हो रही। यह स्थिति स्पष्ट संकेत देती है कि अब केवल अपीलों और नारों से काम नहीं चलेगा, बल्कि निर्णायक कार्रवाई का समय आ चुका है।

सड़क हादसों के पीछे अनेक कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण लापरवाही है। तेज गति से वाहन चलाना, शराब या नशे की हालत में ड्राइविंग करना, मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन चलाना, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग न करना तथा यातायात नियमों की अनदेखी करना दुर्घटनाओं को आमंत्रित करता है। कई बार चालक यह मान लेते हैं कि उनके साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन सड़क पर एक छोटी-सी गलती भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। ओवरटेक करने की जल्दबाजी, लालबत्ती की अवहेलना और गलत दिशा में वाहन चलाना भी दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में शामिल हैं।

सड़कों की खराब स्थिति भी दुर्घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जगह-जगह गड्ढे, टूटी हुई सड़कें, अपर्याप्त रोशनी, चेतावनी संकेतों का अभाव और अवैज्ञानिक ढंग से बनाए गए मोड़ दुर्घटना की संभावना बढ़ा देते हैं। कई बार निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी सड़क पर सुरक्षा संबंधी संकेत नहीं लगाए जाते। बारिश के मौसम में जलभराव और फिसलन की स्थिति खतरे को और बढ़ा देती है। इसलिए सड़क निर्माण केवल लंबाई बढ़ाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि गुणवत्ता और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

वाहनों की तकनीकी खराबी भी एक गंभीर समस्या है। समय पर सर्विस न कराना, घिसे हुए टायर, खराब ब्रेक, खराब हेडलाइट या अन्य तकनीकी खामियां दुर्घटनाओं का कारण बन सकती हैं। विशेष रूप से व्यावसायिक वाहनों की नियमित फिटनेस जांच बेहद आवश्यक है। यदि वाहन सुरक्षित स्थिति में नहीं है तो वह केवल चालक ही नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए खतरा बन जाता है।

यातायात नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। केवल नियम बनाना पर्याप्त नहीं है, उनका कठोर और निष्पक्ष क्रियान्वयन भी जरूरी है। नियम तोड़ने वालों पर त्वरित जुर्माना, बार-बार उल्लंघन करने वालों के लाइसेंस निलंबित करना तथा गंभीर मामलों में कानूनी कार्रवाई करना आवश्यक है। आधुनिक तकनीक जैसे सीसीटीवी कैमरे, स्वचालित चालान प्रणाली और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी व्यवस्था का उपयोग यातायात प्रबंधन को अधिक प्रभावी बना सकता है।

सड़क सुरक्षा की शुरुआत शिक्षा से होती है। बच्चों को विद्यालय स्तर से ही यातायात नियमों की जानकारी दी जानी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को अधिक कठोर और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए ताकि केवल प्रशिक्षित और सक्षम व्यक्ति ही वाहन चला सकें। ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाना भी आवश्यक है। सुरक्षित ड्राइविंग केवल परीक्षा पास करने का विषय नहीं बल्कि जीवनभर अपनाई जाने वाली जिम्मेदारी है।

सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना भी सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में सहायक हो सकता है। यदि लोग अच्छी बस, मेट्रो और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का अधिक उपयोग करेंगे तो निजी वाहनों की संख्या कम होगी, जिससे सड़क पर दबाव घटेगा और दुर्घटनाओं की संभावना भी कम होगी। इसके साथ ही पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए सुरक्षित फुटपाथ, साइकिल ट्रैक और पैदल पार पथ विकसित करना भी आवश्यक है।

दुर्घटना होने के बाद त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दुर्घटना को रोकना। विशेषज्ञ मानते हैं कि दुर्घटना के बाद का पहला एक घंटा अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि इस अवधि में घायल व्यक्ति को उचित चिकित्सा मिल जाए तो अनेक लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसलिए एंबुलेंस सेवाओं को अधिक सक्षम बनाना, ट्रॉमा सेंटरों की संख्या बढ़ाना और राजमार्गों पर आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं विकसित करना समय की मांग है। सामाजिक दृष्टि से भी सड़क सुरक्षा को एक जन आंदोलन का रूप देने की आवश्यकता है। परिवारों को बच्चों में जिम्मेदार यातायात व्यवहार विकसित करना चाहिए।

-शिवांश धाकड़

चलते जाना है

कविता

प्रवीण कुमार, गांव बाड़ा द घाट (सरेल) त. घुमारवीं

चलते जाना है, रुकना नहीं है, कोई तुम्हें समझे या ना समझे
कोई तुम्हें जाने या ना जाने, कोई तुम्हें पहचाने या ना पहचाने
कोई तुम्हें कहे अच्छा या कहे बुरा, कोई निंदा करे या करे स्तुति
कोई प्रीति करे या करे घृणा, रुकना नहीं है, चलते ही जाना है
जग में कोई नहीं है अपना, कौन कब स्वार्थ हेतु साथ छोड़ जाए
कोई नहीं जानता, अक्सर हमने लोगों को कलिकाल में
विश्वास को तोड़ते-मरोड़ते देखा है, हृदय को विदीर्ण करते देखा है
अरे! फिर भी, फरेब से भरी दुनिया में, चलना तो है,
हर कदम फंक-फूंक कर चलिए, रुकना नहीं है, बस चलते ही जाना है
हे मानव! जग में स्वकर्तव्य का कर निर्वहन,
ईश्वर का सुमिरन करते जाओ तुम, प्रेमपूर्ण, भक्तिपूर्ण प्रार्थनाएं होती हैं
दया भाव से, करुणा से नित्य कबूल, तभी उस करुणामय, प्रेम के सागर
ईश्वर को हृदय से नमन है, वाणी से वंदन है, जो है इस सृष्टि का पालक

देश की दिशा पर उठते सवाल जवाबदेही और जनविश्वास की चुनौती

लोग कह रहे हैं भारत में कुछ नहीं हो रहा, यह गलत बोल रहे हैं। भारत में वह सब होता है जो विश्व के किसी देश में नहीं होता। क्या विश्व के किसी भी चर्च में कभी चढ़ावा चोरी हुआ? क्या एक दिन में किसी देश में 35 करोड़ वृक्ष लगे। यह मात्र भारत में ही संभव हो सकता है। यहां विशाल जनता है जो एक दिन में कुछ भी कर सकती है। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 40 करोड़ पौधे लगे हैं, जबकि आबादी है 55 करोड़। सवाल उठता है कि क्या हर व्यक्ति ने दो पौधे लगाए? क्या 5 साल के लड़के भी शामिल थे पौधरोपण में? क्या एक दिन में 3 लाख पौधे किसी शहर में लगे हैं? भारत में लगे हैं और कहते कुछ नहीं हो रहा है। देखने सुनने का नजरिया बदल दें।

भारत में अब बस सुनने का अधिकार है, ऐसा किसी देश में है? हमारे देश से बैंकों का पैसा लेकर लोग भाग जाते हैं, कहा जाता है भारतीय पैसा था ले गया। 10 रुपए बैंक का कर्ज किसान कम वापस करता है तो कुर्की हो जाती है जमीन की, परंतु जो अरबों लेकर भाग गया वह सम्मानयोग्य है। यह नया भारत है। पांच साल में लगभग नौ लाख भारतीय भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं। क्या अन्य किसी देश के नागरिक ऐसा करते हैं? यहां शिक्षा बदल गई। सरकारी स्कूल बंद हो गए-किसी ने कुछ बोला। कभी पेट्रोल में इथेनॉल की लूट तो कभी नौकरी के पेपर की लूट। चिकित्सा महाविद्यालयों में डॉक्टर नहीं फिर भी डिग्री की लूट। निजी कॉलेजों में मानक के अनुसार अध्यापक नहीं, वेतन नहीं, परंतु डिग्री तो मिल रही है। विश्व में ऐसा कोई देश है, बस बोलते हैं भारत में कुछ नहीं हो रहा है।

भारत में ड्रोन तकनीकी से 7000 करोड़ की सड़क बनती है और वह एक बारिश में बह जाती है और कोई सड़क 3000 करोड़ की बनी उद्घाटन से पहले ही गड्ढे बन जाते हैं। यह सब हो रहा है और कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है।

डॉ. अशोक कुमार चौबे
सेवानिवृत्त प्रोफेसर, कृषि प्रसार शिक्षा

अनशन पर बैठे युवा-छात्र। क्या किसी देश में अनशन वालों को अनशन करने से रोका जाता है? भारत में व्यवस्था सही रहे इसलिए आंदोलनों को रोका जाता है। मुकदमे होते हैं और कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है।

भारत में इस समय बहुत तरह की समस्याओं की बाढ़ आ गई है। इस बाढ़ में राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपी चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपालराव से भाजपा सरकार परेशान भी है। कहीं न कहीं हर जगह कुछ हो रहा है। हर शहर हर प्रदेश में, लेकिन इस कुछ में कुछ जनता कुछ युवा छात्र ही बस आवाज दे रहे हैं। अब हर आवाज में चढ़ावा चोरी की गूंज जैसे कानों को विदिर्ण कर रही है, दर्द दे रही है। आस्था कमजोर हो रही है, विश्वास भागवान से उठ रहा है। इस विश्वासघात पर जनता हताश, निराश एक-दूसरे को बस देख रही है शक भरी नजर से कि क्या यह भी उसी गिरोह का हिस्सा तो नहीं है? बाकी जनता को पेंशन नौकरी में है, वह मौन है। परेशान है सबसे गरीब और मध्यम श्रेणी, परंतु मध्यम वर्गीय परिवार सरकार से डर कर बस जी रहा है। मंहगाई की मार से कमर टूट रही है।

वह अपने लड़कों को सही शिक्षा देने योग्य नहीं है। वह अब सरकारी नौकरी पर आस और विश्वास नहीं कर रहे हैं। निजी क्षेत्र की तरफ भी उतनी उम्मीद नहीं लगा रहे हैं। बस मौन है। जनता जानती है जब सरकारी नौकरी कम होती है तो निजी क्षेत्रों में भी नौकरियां कम होने लगती हैं। वेतन भी कम मिलने लगता है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

नारी शक्ति की ऐतिहासिक जीत, जब प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेकर रचा नया इतिहास

25 जुलाई 2007 का दिन भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में दर्ज है। इसी दिन प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने भारत के 12वें राष्ट्रपति तथा देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित भव्य समारोह में तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. जी. बालाकृष्णन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस ऐतिहासिक अवसर ने भारतीय लोकतंत्र की उस परिपक्वता को प्रदर्शित किया जिसमें महिलाओं को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने का अवसर मिला। यह केवल एक व्यक्ति की सफलता नहीं थी बल्कि देश की करोड़ों महिलाओं के लिए सम्मान और प्रेरणा का प्रतीक बन गया।

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल का जन्म 19 दिसंबर 1934 को महाराष्ट्र के जलगांव जिले के नदगांव में हुआ था। उन्होंने राजनीति में आने से पहले कानून की शिक्षा प्राप्त की और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहीं। युवावस्था से ही वे शिक्षा महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण विकास जैसे विषयों में रुचि रखती थीं। वर्ष

1962 में उन्होंने पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव जीता और इसके बाद लगातार कई वर्षों तक राज्य की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने विभिन्न विभागों में मंत्री के रूप में कार्य किया तथा प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया।

प्रतिभा पाटिल ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में स्वास्थ्य पर्यटन समाज कल्याण शिक्षा और महिला विकास जैसे अनेक क्षेत्रों में कार्य किया। वे राज्यसभा की सदस्य भी रहीं और बाद में राजस्थान की राज्यपाल नियुक्त की गईं। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव भी उन्हें प्राप्त हुआ। राज्यपाल के रूप में उनके शांत और संतुलित कार्यकाल ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक अनुभवी और विश्वसनीय नेता के रूप में स्थापित किया।

वर्ष 2007 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया। चुनाव में उनका मुकाबला तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत से था। मतगणना के बाद प्रतिभा पाटिल ने स्पष्ट अंतर से विजय प्राप्त की और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का इतिहास रच दिया। उनकी जीत को भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और समान अवसरों की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया।

25 जुलाई 2007 को शपथ ग्रहण समारोह के दौरान देश के प्रमुख राजनीतिक नेता न्यायपालिका के वरिष्ठ सदस्य सेना के अधिकारी विदेशी राजनयिक और विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियां उपस्थित थीं। यह समारोह भारतीय लोकतंत्र की गरिमा और संवैधानिक परंपराओं का उत्कृष्ट उदाहरण था। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद प्रतिभा पाटिल ने अपने पहले संबोधन में संविधान की रक्षा करने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने तथा समाज के कमजोर वर्गों महिलाओं किसानों युवाओं और वंचित लोगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहने का संकल्प व्यक्त किया।

डॉ. प्रियंका सौरभ
स्वतंत्र टिप्पणीकार

राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक रहा। इस दौरान उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों का दौरा किया और अनेक सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लिया।

(ये लेखिका के निजी विचार हैं)

तैराकी का ज्ञान और सुरक्षा उपाय ही डूबने जैसी दुखद घटनाओं को रोकने का सबसे प्रभावी माध्यम

हर वर्ष **25 जुलाई** को **विश्व डूबने से बचाव दिवस मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य डूबने से होने वाली रोकी जा सकने वाली मौतों के प्रति लोगों को जागरूक करना और प्रभावी सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देना है। वर्ष **2021** में संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस की शुरुआत की और तब से दुनिया भर में सरकारें स्वास्थ्य संस्थाएं शैक्षणिक संस्थान तथा सामाजिक संगठन लोगों को जल सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं। यह दिवस हमें यह याद दिलाता है कि थोड़ी सी सावधानी सही प्रशिक्षण और समय पर बचाव के उपाय अपनाकर हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती है।

डूबना दुनिया भर में एक गंभीर लेकिन अक्सर अनदेखी की जाने वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर वर्ष लाखों लोग डूबने की घटनाओं का शिकार होते हैं जिनमें बड़ी संख्या बच्चों और युवाओं की होती है। इनमें से अधिकांश मौतें ऐसी परिस्थितियों में होती हैं जिन्हें उचित जागरूकता और सुरक्षा उपायों के माध्यम से रोका जा सकता है। यही कारण है कि संयुक्त

राष्ट्र ने इस समस्या को वैश्विक स्तर पर गंभीरता से लेते हुए एक विशेष दिवस मनाने का निर्णय लिया।

भारत जैसे देश में जहां नदियों तालाबों झीलों समुद्र तटों और जलाशयों की संख्या बहुत अधिक है वहां डूबने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। मानसून के मौसम में नदियों का जलस्तर बढ़ने बाढ़ आने या तेज बहाव के कारण दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। कई बार लोग बिना सुरक्षा व्यवस्था के गहरे पानी में उतर जाते हैं या बच्चे खेलते समय पानी के पास चले जाते हैं जिससे दुखद हादसे हो जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खुले कुएं तालाब और सिंचाई के जल स्रोत भी बच्चों के लिए जोखिम पैदा करते हैं।

विश्व डूबने से बचाव दिवस का सबसे बड़ा संदेश यही है कि **डूबना एक रोकी जा सकने वाली दुर्घटना है।** यदि समाज और सरकार मिलकर आवश्यक कदम उठाएं तो बड़ी संख्या में जानें बचाई जा सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले लोगों को जल सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाना आवश्यक है। बच्चों को बचपन से ही पानी के आसपास सावधानी बरतने की शिक्षा दी जानी चाहिए। स्कूलों में जल सुरक्षा और प्राथमिक उपचार से जुड़े विशेष सत्र आयोजित किए जा सकते हैं।

तैराकी सीखना डूबने से बचाव का एक महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है। तैरना केवल एक खेल नहीं बल्कि जीवन रक्षा का कौशल है। यदि बच्चों और युवाओं को सुरक्षित वातावरण में प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की देखरेख में तैराकी सिखाई जाए तो आपात स्थिति में उनके बचने की संभावना काफी बढ़ जाती है। कई देशों ने विद्यालय स्तर पर तैराकी प्रशिक्षण को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है जिससे डूबने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है।

सुरेश कुमार
प्रबंध निदेशक, कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कुल्लू

इसके साथ ही जलाशयों के आसपास सुरक्षा संकेतक बोर्ड लगाना अत्यंत आवश्यक है। जिन स्थानों पर पानी गहरा हो या तेज बहाव हो वहां स्पष्ट चेतावनी संकेत होने चाहिए। पर्यटन स्थलों समुद्र तटों और नदी किनारों पर प्रशिक्षित लाइफगार्ड की नियुक्ति भी जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लाइफ जैकेट का उपयोग नौका विहार मछली पकड़ने या जल क्रीड़ाओं के दौरान अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है क्योंकि वहां कई बार तालाब और कुएं खुले रहते हैं।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

व्यक्तित्व विशेष

संसदीय गरिमा के प्रतीक सोमनाथ

भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सोमनाथ चटर्जी का नाम एक ऐसे नेता के रूप में दर्ज है जिन्होंने संसदीय परंपराओं, लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की गरिमा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनका जन्म 25 जुलाई 1929 को असम के तेजपुर में हुआ था। उनके पिता निर्मल चंद्र चटर्जी प्रसिद्ध अधिवक्ता और राजनेता थे। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अध्ययन किया और आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए। कानून की शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने वकालत शुरू की और जल्द ही सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हो गए।

सोमनाथ चटर्जी
जन्म : 25 जुलाई 1929

सोमनाथ चटर्जी लंबे समय तक भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के प्रमुख नेताओं में गिने गए। वे कई बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और अपने प्रभावशाली भाषणों, संसदीय नियमों की गहरी समझ तथा संतुलित दृष्टिकोण के लिए व्यापक सम्मान प्राप्त किया। वर्ष 2004 में उन्हें लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सदन की गरिमा बनाए रखने, सभी दलों के सदस्यों को निष्पक्ष अवसर देने और संसदीय कार्यवाही को सुचारु रूप से संचालित करने का प्रयास किया।

लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल कई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं का साक्षी रहा। उन्होंने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है और यहां स्वस्थ बहस तथा सार्थक संवाद होना चाहिए। उनके निष्पक्ष रवैये की सराहना सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने की। वे मानते थे कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती ही देश की प्रगति का आधार है। वकालत के क्षेत्र में उनकी गहरी समझ और कानून का व्यापक ज्ञान उनके राजनीतिक जीवन में भी स्पष्ट दिखाई देता था। संसदीय प्रक्रियाओं की व्याख्या और नियमों के पालन में उनकी दक्षता उन्हें अन्य नेताओं से अलग पहचान दिलाती थी। सार्वजनिक जीवन में उन्होंने सादगी, ईमानदारी और संवैधानिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखी।

'भारतेन्दु शिखर

प्रकाशक, मुद्रक, संपादक एवं स्वामी शिवांश धाकड़ द्वारा शर्मा भवन, न्यू रणजीत नगर, एप्पल फ्रूट मंडी, नजदीक ढली टनल, शिमला (हि.प्र.) 171006 से प्रकाशित एवं बायोसर्ट इंटरनेशनल प्रा. लि. प्लॉट नंबर 8, फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि.प्र.), पिन नंबर-176047 से मुद्रित। समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद शिमला न्यायालय के अधीन होंगे।

आरएनआई संदर्भ संख्या-HPHIN/2000/02437
ई-मेल : bhartendunewsmedia@gmail.com, फोन नंबर : 88946-77702

13 दिन में गोरखपुर को मिली 1753 करोड़ रुपए की सौगात

फोरलेन और फ्लाईओवर से बदलेगी गोरखपुर की तस्वीर

एजेंसी, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 13 दिनों के भीतर गोरखपुर को कुल **1753 करोड़ रुपये** की विकास परियोजनाओं की सौगात देकर जिले की आधारभूत संरचना को नई गति दी है। 11 जुलाई को 758 करोड़ रुपये और 23 जुलाई को 995 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इन योजनाओं में सड़क संपर्क को मजबूत बनाने वाली कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। सबसे पिछड़े क्षेत्रों में गिने जाने वाले भटहट को बांसस्थान से जोड़ने वाले फोरलेन मार्ग का लोकार्पण किया गया, जिससे क्षेत्र के लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। साथ ही पूर्वांचल के पहले सिक्सलेन फ्लाईओवर को भी जनता को समर्पित किया गया, जो शहर में यातायात को सुगम बनाने के साथ आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। इन परियोजनाओं से गोरखपुर की रोड कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है। बेहतर सड़क नेटवर्क से व्यापार, निवेश और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार संतुलित और समग्र विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है तथा पूर्वांचल को आधुनिक बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

न्यूज ब्रीफ

45 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर ने 20 वर्षीय पत्नी की गला घोंटकर की हत्या

एजेंसी, फतेहपुर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक 20 वर्षीय महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके 45 वर्षीय पति, प्रॉपर्टी डीलर गंगासागर लोधी और अन्य आरोपितों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी ने वर्ष 2025 में युवती से कोर्ट मैरिज की थी। बाद में महिला के गर्भवती होने पर उसका गर्भपात कराया गया।

धमकी से तंग युवती ने उठाया आत्मघाती कदम, तीन पर मुकदमा

एजेंसी, मेरठ। मेरठ में एक युवती ने आरोप लगाया है कि एक युवक ने अपनी पहचान छिपाकर उससे दोस्ती की और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। बाद में युवक की वास्तविक पहचान सामने आने पर विवाद बढ़ गया। पीड़िता का आरोप है कि युवक की मां और मामी ने उसे धमकाया, जिससे परेशान होकर उसने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया।

बस्ती में 33 लाख की अनियमितता पूर्व प्रधान और सचिव से होगी वसूली

एजेंसी, बस्ती। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के दुबौलिया विकास खंड की बरदिया लोहार ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर 33.62 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर निवर्तमान ग्राम प्रधान और तत्कालीन ग्राम सचिव से सरकारी धन की बराबर-बराबर वसूली करने के आदेश जारी किए गए हैं।

गोसेवा ट्रस्ट की आड़ में 36 करोड़ की साइबर ठगी का पर्दाफाश

एजेंसी, कानपुर। कानपुर पुलिस और साइबर क्राइम टीम ने गोवंश संरक्षण के नाम पर संचालित एक कथित ट्रस्ट के जरिए साइबर ठगी की रकम जुटाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में एक्सिस बैंक के एक कर्मचारी समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में ट्रस्ट के खाते से पिछले दो वर्षों में करीब 36 करोड़ रुपये के लेनदेन का पता चला है।

1.27 लाख रुपए के रिश्वत मामले में रेल अधिकारी गिरफ्तार

एजेंसी, वाराणसी। सीबीआई की लखनऊ टीम ने पूर्वोत्तर रेलवे के बनारस रेल मंडल में तैनात वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक (सीनियर डीएमएम) नितिश अग्रवाल को 1.27 लाख रुपये की कथित रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कार्रवाई रेलवे ठेकेदार की शिकायत पर की गई। गिरफ्तारी के बाद आरोपी अधिकारी से खरीद प्रक्रिया और अन्य मामलों में पूछताछ की गई।

उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की सुधरेगी गुणवत्ता, पांच साल के लिए बनेगा हेल्थ ब्लूप्रिंट

एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मरीजों को बेहतर, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराने के लिए स्टेट हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर-उत्तर प्रदेश (एसएचएसआरसी-यूपी) का पांच वर्षीय रणनीतिक रोडमैप तैयार किया जा रहा है। इसके तहत डिजिटल हेल्थ, मरीजों की सुरक्षा, गैर-संचारी रोगों की रोकथाम, अस्पतालों में गुणवत्ता सुधार और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर स्वास्थ्य नीति तैयार करने पर विशेष जोर रहेगा।

दो सगे भाई-बहन की गांगी नदी में डूबने से मौत

एजेंसी, लखनऊ। थाना क्षेत्र के माहेपुर गांव में शुक्रवार की सुबह गांगी नदी में डूबने से सगे भाई-बहन की मौत हो गई। हादसे में कृष्णा बिंद (3) और प्रिया बिंद (5) की जान चली गई। घटना के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

उत्तर प्रदेश में खत्म होगी पासपोर्ट आवेदन की लंबी वेटिंग लिस्ट

एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पासपोर्ट आवेदन की लंबी वेटिंग अब समाप्त होने वाली है। आवेदन की बड़ी लाइन देखते हुए पासपोर्ट विभाग एक अगस्त को शनिवार को भी 49 जिलों के आवेदकों के लिए 4500 अपॉइंटमेंट विशेष रूप से खोलेगा। इसके साथ ही 17 अगस्त से पासपोर्ट आवेदन के बाद होने वाली किसी भी समस्या के लिए अपॉइंटनेट लेकर लखनऊ आना होगा।

गोरखपुर-पानीपत एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण तेज

एजेंसी, मुजफ्फरनगर। गोरखपुर-पानीपत एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र में कई गांवों की भूमि का चिन्हांकन शुरू हो गया है। अधिग्रहित होने वाली जमीन पर पीले रंग के पिलर लगाए जा रहे हैं, ताकि एक्सप्रेसवे के मार्ग को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जा सके। प्रशासनिक टीमों ने क्षेत्र में पहुंचकर जमीन की पहचान और अन्य जरूरी प्रक्रियाएं शुरू कर दी हैं।

दिल्ली से प्रयागराज की यात्रा होगी और सुगम, बनेगा नया एक्सप्रेसवे लिंक

गंगा और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा नया संपर्क मार्ग

एजेंसी, प्रयागराज

- मेरठ बनेगा एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी का नया केंद्र
- खानपुर-भगवानपुर के बीच बनेगा संपर्क मार्ग, दो बड़े एक्सप्रेसवे आपस में जुड़े

दिल्ली से प्रयागराज तक की यात्रा को अधिक तेज, सुरक्षित और सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत गंगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ने की तैयारी तेज हो गई है। मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुण गोविल ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर इस महत्वाकांक्षी परियोजना में तेजी लाने का आग्रह किया। प्रस्ताव के अनुसार मेरठ के खानपुर और भगवानपुर के बीच लगभग तीन किलोमीटर लंबा संपर्क मार्ग बनाया जाएगा, जिससे दोनों एक्सप्रेसवे सीधे जुड़ सकेंगे। इस परियोजना के पूरा होने के बाद दिल्ली से प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को अधिक सुविधाजनक मार्ग मिलेगा और यात्रा का समय भी कम होने की संभावना है।

सांसद अरुण गोविल ने बताया कि इस संपर्क मार्ग का प्रस्ताव उन्होंने पिछले वर्ष केंद्र सरकार के समक्ष रखा था। प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया है कि डीपीआर का कार्य शीघ्र पूरा कर टेंडर प्रक्रिया भी जल्द शुरू कराई जाए, ताकि निर्माण कार्य में अनावश्यक देरी न हो। उन्होंने कहा कि यह संपर्क मार्ग केवल मेरठ ही नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

यह परियोजना क्षेत्र के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए भी लाभकारी मानी जा रही है। दोनों एक्सप्रेसवे के जुड़ने से माल परिवहन अधिक तेज और सुगम होगा, जिससे व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। किसानों, उद्योगों और छोटे व्यापारियों को अपने उत्पाद विभिन्न शहरों तक कम समय और कम लागत में पहुंचाने में सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही पर्यटन और धार्मिक यात्राओं को भी गति मिलेगी, क्योंकि प्रयागराज, मेरठ और दिल्ली के बीच आवागमन पहले की तुलना में अधिक आसान हो जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक सड़क अवसंरचना किसी भी क्षेत्र के विकास की आधारशिला होती है। यदि यह संपर्क मार्ग तय समय में तैयार हो जाता है तो मेरठ राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाएगा।

मेरठ में क्रिकेटर समीर रिजवी के पिता से जुड़ी संपत्ति पर चला बुलडोजर

- 2500 वर्ग फीट में बने अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर नोटिस के बाद कार्रवाई

एजेंसी, मेरठ। मेरठ कैंट क्षेत्र में रक्षा संपदा विभाग ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय क्रिकेटर समीर रिजवी के पिता हसीन अख्तर से जुड़ी संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई गुरुवार शाम पुलिस बल की मौजूदगी में मेरठ कैंट स्थित बंगला संख्या-86 परिसर में की गई। विभाग के अधिकारियों ने परिसर में बनाई गई अवैध दीवार को हटाते हुए स्पष्ट किया कि संबंधित निर्माण बिना अनुमति के किया गया था। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।

रक्षा संपदा विभाग के अनुसार, संबंधित संपत्ति एचओआर (हायर ऑफ राइट्स) रिकॉर्ड में सरदार करतार सिंह के नाम दर्ज है, जबकि पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर इसका संबंध हसीन अख्तर से बताया गया है, जो भारतीय क्रिकेटर समीर रिजवी के पिता हैं। विभाग का कहना है कि लगभग 2500 वर्ग फीट क्षेत्र में किए गए अवैध निर्माण को लेकर पहले भी नोटिस जारी किया गया था और निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर रक्षा संपदा अधिकारी विनीत सिंह ने 13 जुलाई को ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया था।

इसी आदेश के अनुपालन में विभागीय टीम ने पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई को अंजाम दिया। अभियान के दौरान एसडीओ वी.के. गुप्ता, प्रेम चंद्र, अधीक्षक देवेंद्र सिंह सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि कैंट क्षेत्र में सरकारी भूमि और रक्षा संपदा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। विभाग ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ समान रूप से कार्रवाई की जाएगी।

आलोक पाठक की भारतीय रेलवे में अधिवक्ता पद पर हुई नियुक्ति

एजेंसी, वाराणसी। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं विधि विशेषज्ञ आलोक पाठक को भारतीय रेलवे का अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति को विधि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इस निर्णय के बाद अधिवक्ता समुदाय, सामाजिक संगठनों और उनके शुभचिंतकों में खुशी का माहौल है। विभिन्न संस्थाओं और गणमान्य लोगों ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की है।

NORTH EASTERN RAILWAY
Office of the General Manager (Law)
Gorakhpur-273012

आलोक पाठक लंबे समय से विधि के क्षेत्र में सक्रिय हैं और कई महत्वपूर्ण मामलों में अपनी कानूनी विशेषज्ञता का परिचय दे चुके हैं। वे इससे पहले भारत सरकार, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ), काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) तथा कई राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों को अपनी विधिक सेवाएं प्रदान कर चुके हैं।

विभिन्न सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों के साथ काम करने के कारण उन्हें प्रशासनिक और विधिक मामलों का व्यापक अनुभव प्राप्त है। इसी अनुभव और कार्यकुशलता को देखते हुए भारतीय रेलवे ने उन्हें अपने अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है।

भारतीय रेलवे देश के सबसे बड़े सार्वजनिक उपक्रमों में से एक है, जहां भूमि विवाद, सेवा संबंधी मामलों, अनुबंधों और अन्य कानूनी मामलों में नियमित रूप से न्यायालयों में पक्ष रखा जाता है। ऐसे में अनुभवी अधिवक्ता की नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने वाला व्यक्ति पति की श्रेणी में नहीं: हाई कोर्ट

- पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी पर कोर्ट सख्त, नहीं मिलेगा पति का कानूनी दर्जा
- दूसरी शादी को नहीं मिलेगी मान्यता, हाई कोर्ट ने स्पष्ट की कानूनी स्थिति

एजेंसी, लखनऊ

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवाह कानून से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि पहली पत्नी के जीवित रहते और पहली शादी के कायम रहने के दौरान की गई दूसरी शादी कानून की नजर में अमान्य मानी जाएगी। अदालत ने कहा कि मुस्लिम धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों में यदि कोई व्यक्ति अपनी पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करता है तो वह विवाह शुरू से ही शून्य माना जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति को दूसरी पत्नी के संदर्भ में कानूनी रूप से पति का दर्जा नहीं दिया जा सकता।

न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकलपीठ ने यह टिप्पणी पीलीभीत निवासी सर्वेश उर्फ छोटू उर्फ छोटेलाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान की। अदालत ने कहा कि जब दूसरी शादी ही कानून की दृष्टि से वैध नहीं है तो उस व्यक्ति को उस विवाह के आधार पर पति की श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता। हालांकि अदालत ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर दी।

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि पहली शादी के रहते दूसरी शादी करने वाले व्यक्ति पर वैवाहिक संबंधों से जुड़े कानूनी प्रावधानों को लागू करने से पहले विवाह की वैधता देखना आवश्यक है। अदालत की इस टिप्पणी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि कई मामलों में दूसरी शादी के आधार पर पति-पत्नी के अधिकारों और कानूनी जिम्मेदारियों को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं।

भारतीय कानून में पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करना, जहां वैध नहीं है, वहीं विवाह की कानूनी मान्यता भी समाप्त हो जाती है। अदालत ने कहा कि कानून में पति की परिभाषा तभी लागू होती है जब वैवाहिक संबंध कानूनी रूप से मान्य हो। यदि विवाह ही शून्य है तो उससे जुड़े अधिकार और दायित्व भी उसी आधार पर तय नहीं किए जा सकते।

विशेषज्ञों के अनुसार, यह फैसला वैवाहिक कानूनों की व्याख्या के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इससे यह संदेश जाता है कि विवाह केवल सामाजिक परंपरा नहीं बल्कि कानूनी जिम्मेदारी भी है। किसी भी व्यक्ति को विवाह से जुड़े अधिकारों और दायित्वों को समझते हुए कानून का पालन करना चाहिए। हाई कोर्ट की यह टिप्पणी भविष्य में ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को दिशा देने में सहायक हो सकती है।

भगवान राम टिप्पणी मामला: राहुल गांधी को 12 अगस्त तक राहत

एजेंसी, वाराणसी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भगवान श्रीराम पर कथित अमर्यादित टिप्पणी से जुड़े मामले में वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट में प्रस्तावित सुनवाई शुक्रवार को नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए **12 अगस्त** की तारीख निर्धारित की है। यह प्रकरण राहुल गांधी के अमेरिका के बोस्टन स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी में अप्रैल 2025 के दौरान छात्रों के साथ हुए एक संवाद कार्यक्रम में दिए गए कथित बयान से जुड़ा है।

मामले में अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने मई 2025 में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) एवं एमपी-एमएलए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी की टिप्पणी से भगवान श्रीराम के प्रति आस्था रखने वाले लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। अदालत में इसी प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होनी थी, लेकिन न्यायिक अधिकारी के अवकाश के चलते कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी। अब अदालत 12 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई करेगी, जिसमें प्रार्थना पत्र पर आगे की कानूनी प्रक्रिया और पक्षों की दलीलों पर विचार किए जाने की संभावना है।

भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे प्रेम कुमार अले और अबू हुबैदा

एजेंसी, मुरादाबाद। लखनऊ। भारतीय पैरा बैडमिंटन की व्हीलचेयर वर्ग (डब्ल्यूएच-1/डब्ल्यूएच-2) की चर्चित युगल जोड़ी प्रेम कुमार अले और अबू हुबैदा ने 5वें एशियन पैरा गेम्स 2026 के लिए आधिकारिक रूप से क्वालिफाई कर लिया है। ऐची-नागोया (जापान) में आयोजित होने वाले इस प्रतिष्ठित महाद्वीपीय खेल आयोजन में दोनों खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बैडमिंटन एशिया द्वारा जारी आधिकारिक आमंत्रण सूची में दोनों खिलाड़ियों के नाम शामिल किए गए हैं,

जिससे भारतीय दल की पदक उम्मीदों को और मजबूती मिली है। अबू हुबैदा ने हाल के महीनों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने जून 2026 में फ्रांस के मुलहाउस में आयोजित बाबोलैट फ्रेंच पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में मिश्रित युगल वर्ग का कांस्य पदक जीता। इसके बाद डबलिन में आयोजित ब्रिटिश एवं आयरिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026 में भी कांस्य पदक जीतकर लगातार दो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का गौरव बढ़ाया। वहीं, प्रेम कुमार अले और अबू हुबैदा की जोड़ी पिछले पांच वर्षों से लगातार राष्ट्रीय चैंपियन बनी हुई है। उनकी निरंतर सफलता और अनुभव को देखते हुए एशियन पैरा गेम्स 2026 में उनसे उत्कृष्ट प्रदर्शन और पदक की उम्मीद की जा रही है।

फेस अथेंटिकेशन लागू होते ही वीबी-जी राम-जी योजना में मजदूरों की संख्या घटी

एजेंसी, गोरखपुर। गोरखपुर मंडल में भारत-गारंटी फार रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी राम-जी योजना के तहत आधार आधारित फेस अथेंटिकेशन प्रणाली लागू होने के बाद मजदूरों की उपस्थिति के आंकड़ों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पिछले वर्ष मार्च से जून के बीच जहां बड़ी संख्या में श्रमिकों ने योजना के तहत कार्य किया था, वहीं इस वर्ष इसी अवधि में कई जिलों में पंजीकृत और कार्यरत मजदूरों की संख्या में कई गुना तक गिरावट दर्ज की गई है। इस बदलाव ने योजना के क्रियान्वयन और नई डिजिटल व्यवस्था को लेकर कई सवाल भी खड़े किए हैं।

प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि इस गिरावट के पीछे दो प्रमुख कारण हैं। पहला, आधार आधारित फेस अथेंटिकेशन लागू होने से फर्जी हाजिरी, डुप्लीकेट उपस्थिति और कागजी मजदूरों की संभावना काफी हद तक समाप्त हो गई है। अब प्रत्येक श्रमिक की उपस्थिति उसके चेहरे के सत्यापन के बाद ही दर्ज हो रही है, जिससे योजना में पारदर्शिता बढ़ी है और वास्तविक लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित हो

- नई हाजिरी प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ी लेकिन तकनीकी दिक्कतें भी सामने आईं

रही है। इससे सरकारी धन के दुरुपयोग पर भी रोक लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

हालांकि दूसरी ओर नई डिजिटल व्यवस्था ने वास्तविक मजदूरों के सामने भी कई व्यावहारिक समस्याएं खड़ी कर दी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट नेटवर्क की कमी, स्मार्टफोन की अनुपलब्धता, मोबाइल एप में तकनीकी खराबी और चेहरे के सत्यापन में आने वाली दिक्कतों के कारण कई पात्र श्रमिक समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पा रहे हैं। इसका सीधा असर उन्हें मिलने वाले रोजगार और मजदूरी पर पड़ रहा है।

लापरवाही थोड़ी देर की बारिश से जलमग्न हुईं सड़कें, नगर निगम की व्यवस्थाओं पर उठे सवाल

बारिश में डूबीं वाराणसी की सड़कें, बढ़ा गंगा का जलस्तर

एजेंसी, वाराणसी

वाराणसी में दिनभर रुक-रुक कर हुई बारिश ने नगर निगम की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। शहर के कई हिस्सों में थोड़ी ही देर की बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो गईं और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अर्दली बाजार, लंका, भेलूपुर, महमूरगंज, सिगरा सहित कई इलाकों में सड़कों पर लंबे समय तक पानी जमा रहा। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश का असर अपेक्षाकृत कम दिखाई दिया, लेकिन जहां तेज वर्षा हुई वहां जलभराव ने यातायात और आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया।

सड़कों पर जमा पानी के कारण पैदल राहगीरों, दोपहिया वाहन चालकों और स्कूली बच्चों को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जगह-जगह गंदे पानी के छींटों से लोगों के कपड़े खराब हुए, जबकि कई स्थानों पर वाहन रेंगते नजर आए। निचले इलाकों में जलभराव के कारण लोगों को घरों और दुकानों तक पहुंचने में भी दिक्कत हुई। कई जगह जल निकासी न होने से पानी घंटों तक सड़कों पर जमा रहा, जिससे नगर निगम की तैयारियों पर सवाल उठने लगे।

बारिश के साथ ही गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। नदी का पानी कई घाटों की सीढ़ियों तक पहुंच गया है और कुछ निचले घाट जलमग्न होने लगे हैं। बालाजी घाट स्थित राघवेश्वर महादेव मंदिर परिसर में भी गंगा का पानी पहुंचने लगा है। प्रशासन गंगा के बढ़ते जलस्तर पर लगातार नजर बनाए हुए है और घाटों पर लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। नाव संचालन और स्नान के दौरान विशेष सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं।

मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है। इसके मद्देनजर नगर निगम और जिला प्रशासन को जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त रखने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी करने की आवश्यकता है। नागरिकों से भी अपील की गई है कि जलभराव वाले क्षेत्रों से गुजरते समय सावधानी बरतें और अनावश्यक रूप से गहरे पानी में प्रवेश न करें। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर वर्ष मानसून के दौरान शहर के कई इलाकों में यही स्थिति देखने को मिलती है।

उफनती गंगा ने बढ़ाई प्रशासन की चिंता

बारिश के साथ ही गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। नदी का पानी कई घाटों की सीढ़ियों तक पहुंच गया है और कुछ निचले घाट जलमग्न होने लगे हैं। बालाजी घाट स्थित राघवेश्वर महादेव मंदिर परिसर में भी गंगा का पानी पहुंचने लगा है। प्रशासन गंगा के बढ़ते जलस्तर पर लगातार नजर बनाए हुए है और घाटों पर लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। नाव संचालन और स्नान के दौरान विशेष सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है।

250 करोड़ की साइबर ठगी का मास्टरमाइंड दुबई में मौज करता मिला

- ठगी की रकम से दुबई में रूसी डांसरों पर उड़ाए नोट

एजेंसी, कानपुर। 250 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के मामले में पुलिस जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों राजवीर सिंह और शिवम सिन्हा से पूछताछ में सामने आया कि गिरोह का कथित मास्टरमाइंड अभय शुक्ला उर्फ सुल्तान मिर्जा उर्फ वेलेंटाइन दुबई में रहकर ठगी की रकम पर ऐश कर रहा था। पुलिस को शिवम सिन्हा के मोबाइल फोन से दो वीडियो मिले हैं, जिनमें अभय दुबई के एक पब में रूसी डांसरों के साथ नाचता और उन पर नोटों की गड्डियां उड़ाता दिखाई दे रहा है। जांच एजेंसियां इन वीडियो की सत्यता की पुष्टि करने के साथ ही इन्हें महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में परख रही हैं।

पुलिस के अनुसार, गिरोह ने साइबर ठगी के जरिए करोड़ों रुपये जुटाए और उस रकम का बड़ा हिस्सा विदेश में खर्च किया गया। अब अभय शुक्ला की गिरफ्तारी के लिए उसकी विदेश यात्राओं, पासपोर्ट, बैंक खातों और संपत्तियों का ब्योरा खंगाला जा रहा है। उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, ताकि भारत लौटते ही उसे गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। यदि जांच में और साक्ष्य मिलते हैं तो इस मामले में कई और गिरफ्तारियां होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

सोनीपत से दिल्ली आईएसबीटी तक दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

70 रुपए किराये में आईएसबीटी तक सफर, यात्रियों को मिलेगी बेहतर परिवहन सुविधा

भारतेन्दु संवाददाता,सोनीपत

हरियाणा के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अब सोनीपत से दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित अंतरराज्यीय बस अड्डे (आईएसबीटी) तक इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। इससे यात्रियों को सस्ती, सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन सेवा उपलब्ध होगी। दिल्ली रूट के लिए ई-बसों का किराया 70 रुपये निर्धारित करने पर सहमति बन गई है। शुक्रवार को ट्रायल के तौर पर दो इलेक्ट्रिक बसों को दिल्ली भेजा जाएगा। इसके बाद समयसारिणी तय कर नियमित संचालन शुरू कर दिया जाएगा।

दिल्ली रूट पर ई-बसों का किराया पहले 87 रुपये प्रस्तावित किया गया था, जबकि वातानुकूलित बसों का किराया 79 रुपये है। किराये में अधिक अंतर होने के कारण ई-बसों को दिल्ली तक चलाने की योजना पर रोक लगी हुई थी। रोडवेज अधिकारियों ने मुख्यालय से किराया कम करने की मांग की थी, जिसे मंजूरी मिलने के बाद अब 70 रुपये तय किया गया है।

इस फैसले से रोजाना दिल्ली जाने वाले नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों और अन्य यात्रियों को बड़ा लाभ मिलेगा। कम किराये के साथ इलेक्ट्रिक बसों से प्रदूषण में भी कमी आएगी। यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित सफर का विकल्प मिलेगा।

पहले सोनीपत डिपो की ई-बसों का संचालन केवल कुंडली बॉर्डर तक किया जा रहा था। इसके बाद यात्रियों को दिल्ली पहुंचने के लिए अन्य वाहनों का सहारा लेना पड़ता था। यात्रियों की सुविधा और मांग को देखते हुए अब रूट का विस्तार करते हुए बसों को सीधे दिल्ली आईएसबीटी तक चलाने का निर्णय लिया गया है। इससे यात्रियों का समय बचेगा और बार-बार वाहन बदलने की परेशानी समाप्त होगी।

सोनीपत डिपो के बेड़े में कुल 15 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। यह पहला अवसर होगा जब डिपो की ई-बसें अंतरराज्यीय रूट पर संचालित होंगी। इससे पहले ये बसें गोहाना, पानीपत, गन्नौर और रोहतक जैसे स्थानीय तथा अंतर-जिला मार्गों पर ही चल रही थीं। दिल्ली रूट पर ई-बसों के संचालन में सोनीपत डिपो के महाप्रबंधक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने दिल्ली में बसों के संचालन के लिए आवश्यक अनुमति प्रक्रिया पूरी करवाई है।

सोनीपत डिपो की ई-बसें पहली बार अंतरराज्यीय मार्ग पर दौड़ेंगी

छात्रों पर कथित बल प्रयोग के विरोध में इनेलो का प्रदर्शन, उठाई जांच की मांग

भारतेन्दु संवाददाता, यमुनानगर

दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं पर कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) ने यमुनानगर में प्रदर्शन किया। इनेलो कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता जगाधरी अनाज मंडी गेट पर एकत्र हुए। इसके बाद वे प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व विधायक दिलबाग सिंह ने किया।

दिलबाग सिंह ने कहा कि 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र और युवा नीट पेपर लीक सहित कई मुद्दों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों पर बल प्रयोग किया। उनके अनुसार, कार्रवाई में लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस और पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे कई छात्र घायल हुए। इनेलो नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से रखने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि छात्रों के आंदोलन को बल प्रयोग से दबाना उचित नहीं है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

राष्ट्रपति के नाम दिए गए ज्ञापन में जंतर-मंतर घटनाक्रम की न्यायिक जांच कराने, दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने की मांग की गई। इसके अलावा इनेलो ने नीट पेपर लीक मामले में दोषियों को कड़ी सजा देने, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, भर्ती और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने की मांग भी उठाई। ज्ञापन में समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया लागू करने, परीक्षा शुल्क और आयु सीमा में राहत देने तथा घायल छात्रों को उचित मुआवजा और निशुल्क उपचार उपलब्ध कराने की मांग भी शामिल रही।

न्यूज ब्रीफ

नाले की समस्या से परेशान किसानों ने उठाई आवाज

भारतेन्दु संवाददाता, यमुनानगर। नगर निगम क्षेत्र के ममीदी, ईशोपुर सहित अन्य गांवों के किसानों ने खेतों से होकर बह रहे नाले की समस्या को लेकर अब आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। किसानों का कहना है कि नाले को एसटीपी में डाइवर्ट करने की मांग को लेकर फरवरी 2025 में सीएम विंडो पर शिकायत दी गई थी, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ है। किसानों के अनुसार, वे चार बार लिखित रिमाइंडर दे चुके हैं और समाधान शिविरों में भी शिकायत दर्ज करा चुके हैं। इसके बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। अब किसानों ने मामले की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में करने का निर्णय लिया है। किसानों का आरोप है कि नाले के कारण हर साल उनकी फसलें खराब हो रही हैं। नाले का पानी खेतों में फैलने से भूमि की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने मांग की है कि नाले को जोड़िया से एसटीपी की ओर मोड़ा जाए, जिससे किसानों को राहत मिल सके। किसानों का आरोप है कि नाले में औद्योगिक इकाइयों का रसायनयुक्त पानी भी छोड़ा जा रहा है।

बरसात से निपटने को सोनीपत प्रशासन पूरी तरह अलर्ट

भारतेन्दु संवाददाता, सोनीपत। बरसात के मौसम में जनसुविधाएं प्रभावित न हों, इसके लिए उपायुक्त नेहा सिंह ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जलभराव वाले स्थानों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित कर पानी निकासी की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित की जाए। लघु सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने बरसाती तैयारियों, सीएम विंडो, समाधान शिविर, म्हारी सड़क पोर्टल और ई-ऑफिस प्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को पंपिंग सेट, मशीनों और कर्मचारियों की तैनाती पहले से करने के निर्देश दिए। उन्होंने बिजली निगम को पेड़ों की छंटाई और सड़कों के गड्ढे भरने के लिए संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि लापरवाही मिलने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

डिजिटल प्रेस सुरक्षा पर डॉ. मोहित करेंगे शोध

भारतेन्दु संवाददाता, हिसार। गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रिंटिंग विभाग के डॉ. मोहित कुमार ए3 कलर डिजिटल प्रेस की सुरक्षा बढ़ाने के लिए शोध करेंगे। उन्हें हरियाणा सरकार से 28 लाख रुपये की शोध परियोजना मिली है। परियोजना का विषय ए3 कलर डिजिटल प्रिंटिंग प्रेसों में सुरक्षा प्रोटोकॉल का मूल्यांकन है। दो वर्ष की इस परियोजना में डिजिटल प्रेस की हैकिंग, अनधिकृत प्रिंटिंग और मेमोरी से डाटा रिकवरी रोकने के उपाय विकसित किए जाएंगे। इसमें फर्मवेयर सुरक्षा, एन्क्रिप्टेड प्रिंट जॉब ट्रांसमिशन, सिक्योर बूट और ऑडिट लॉगिंग जैसी तकनीकों पर काम होगा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. नरसी राम बिश्नोई ने इसे डिजिटल प्रिंटिंग सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि शोध से संवेदनशील दस्तावेजों की सुरक्षा मजबूत होगी और सरकारी, बैंकिंग, स्वास्थ्य व शिक्षा क्षेत्रों को लाभ मिलेगा।

पेयजल संकट पर प्रशासन सक्रिय, ग्रामीणों ने टाला प्रदर्शन

भारतेन्दु संवाददाता, हिसार। गांव मैयड़ में लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या को लेकर 25 जुलाई को प्रस्तावित मटका फोड़ प्रदर्शन प्रशासन के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया है। ग्रामीणों ने कहा कि आंदोलन वापस नहीं लिया गया, बल्कि फिलहाल टाला गया है। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों और मंत्री रणबीर गंगवा के पुत्र संजीव गंगवा ने ग्रामीणों से बातचीत कर जल्द समाधान का भरोसा दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि तय समय में समस्या दूर नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ग्रामीण पेयजल के साथ बिजली व्यवस्था सुधारने की भी मांग कर रहे हैं।ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लंबे समय से अनियमित जलापूर्ति के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने प्रशासन से पेयजल और बिजली समस्याओं का स्थायी समाधान जल्द करने की मांग की है। अधिकारियों ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

मुरथल में ऑडी कार का शीशा तोड़कर लाखों का सामान चोरी

भारतेन्दु संवाददाता, सोनीपत

सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात

सोनीपत जिले के मुरथल स्थित जीटी रोड पर होटलों और ढाबों के बाहर खड़े वाहनों को निशाना बनाने वाला गिरोह एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहा है। ताजा मामले में नोएडा के एक कारोबारी की ऑडी कार का शीशा तोड़कर लाखों रुपये का सामान चोरी कर लिया गया। पूरी वारदात होटल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को दी शिकायत में नोएडा के सेक्टर-121 स्थित क्लियो काउंटी निवासी हेमंत गुप्ता ने बताया कि वह 23 जुलाई की सुबह अपनी ऑडी कार से करनाल जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने मुरथल स्थित बीकानेर होटल के बाहर कार पार्क की और नाश्ता करने के लिए होटल के अंदर चले गए।

कुछ देर बाद जब वह वापस लौटे तो कार की चालक सीट के पीछे वाली खिड़की का शीशा टूटा हुआ मिला। कार की जांच करने पर उसमें रखा बैग गायब पाया गया। बैग में एस जेनबुक-14 लैपटॉप, चार्जर, पावर बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, करीब 15 हजार रुपये नकद और जरूरी दस्तावेजों वाली डायरी थी। चोरी हुए सामान की कुल कीमत करीब 1.17 लाख रुपये बताई गई है। सीसीटीवी फुटेज में दो युवक मोटरसाइकिल से होटल के बाहर आते दिखाई दे रहे हैं। फुटेज के अनुसार, एक युवक बाइक से उतरकर कुछ ही सेकंड में ऑडी कार का शीशा तोड़ता है और बैग निकालकर साथी के साथ फरार हो जाता है।

सरकारी स्कूलों में अब गूंजेगा हरियाणा का राज्य-गीत

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़।

हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अब सप्ताह में एक दिन प्रार्थना सभा के दौरान राज्य-गीत का गायन किया जाएगा। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और प्रदेश के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करना है।

निर्देशों के अनुसार, सभी राजकीय विद्यालयों में सप्ताह में एक दिन हरियाणा राज्य-गीत का सामूहिक गायन अनिवार्य होगा। इसके लिए विद्यार्थियों को राज्य-गीत के बोल उपलब्ध कराए जाएंगे और एमपी-3 भी साझा की जाएगी। साथ ही प्रार्थना सभा का संचालन करने वाले विद्यार्थियों को राज्य-गीत के लिए विशेष अभ्यास करवाने के निर्देश दिए गए हैं।

पेपर लीक मामलों पर कांग्रेस का प्रदर्शन, दोषियों पर कार्रवाई और युवाओं को न्याय देने की मांग

भारतेन्दु संवाददाता, नारनौल

पेपर लीक मामलों और दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए घटनाक्रम के विरोध में शुक्रवार को नारनौल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व विधायक राव दान सिंह ने किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शहर की चितवन वाटिका में एकत्र हुए और वहां से पैदल मार्च करते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने एडीसी तरुण कुमार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर पेपर लीक मामलों में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक राव दान सिंह ने कहा कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के घटनाओं से लाखों युवाओं के भविष्य पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी और सरकारी परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन इस दिशा में अपेक्षित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

राव दान सिंह ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन और राहुल गांधी की गिरफ्तारी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने वाले विपक्षी नेताओं की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है।

कांग्रेस नेताओं अक्षत राव, चंद्रप्रकाश एडवोकेट और पूर्व जज राकेश यादव ने भी प्रदर्शन को संबोधित किया। उन्होंने मांग की कि पेपर लीक मामलों में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। नेताओं ने शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग भी रखी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली में मजबूत व्यवस्था लागू की जानी चाहिए।

यमुनानगर में जमानत पर आए हत्या आरोपी पर हमला, पुलिस ने शुरू की जांच

भारतेन्दु संवाददाता, यमुनानगर

यमुनानगर शहर में वर्ष 2025 के चर्चित विषेक हत्याकांड के एक आरोपी पर कथित रूप से जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर दो नामजद और तीन अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस वारदात के पीछे पुरानी रंजिश सहित अन्य संभावित कारणों की जांच कर रही है।

पुलिस को दी शिकायत में गोविंदपुरा निवासी विशेष कंबोज ने बताया कि वह गुरुवार रात टीचर कॉलोनी स्थित शनि मंदिर के पास से पैदल अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान एक कार ने उसके सामने आकर रास्ता रोक लिया। आरोप है कि कार से उतरे सेक्टर-17 हुडा, जगाधरी निवासी शुभम गर्ग, उसके साथी मनी और तीन अन्य युवकों ने उस पर हमला कर दिया।

शिकायतकर्ता के अनुसार, हमलावरों ने विषेक हत्याकांड का जिक्र करते हुए उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि युवकों ने लकड़ी के डंडों और लोहे की रॉड से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले में उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया, जबकि चेहरे, हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों पर भी चोटें आईं।

पुरानी रंजिश की आशंका, दो नामजद समेत पांच आरोपियों पर केस दर्ज

घटना के दौरान शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद घायल विशेष कंबोज को उपचार के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने जांच के दौरान उसके पैर में फ्रैक्चर की पुष्टि की। साथ ही चेहरे पर लगी चोटों को देखते हुए विशेषज्ञ चिकित्सकों से जांच कराने की सलाह दी गई है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, घायल विशेष कंबोज वर्ष 2025 में हुए चर्चित विषेक हत्याकांड का आरोपी है। पुलिस जांच के बाद उसे उस अन्य आरोपी के साथ गिरफ्तार किया गया था। वह करीब तीन महीने पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था।

सिटी थाना पुलिस ने विशेष कंबोज की शिकायत पर शुभम गर्ग, मनी और तीन अज्ञात युवकों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि घटना के पीछे हत्याकांड से जुड़ी रंजिश, व्यक्तिगत विवाद या अन्य किसी कारण की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है।

वैज्ञानिक अनुसंधान और आधुनिक तकनीक से आयुर्वेद को मिलेगी नई वैश्विक पहचान

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

आयुर्वेद को आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीक के सहयोग से चिकित्सा क्षेत्र में और अधिक मजबूत पहचान दिलाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य के तहत आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक प्रोफेसर वैद्य रबीनारायण आचार्य ने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, पंचकूला का दौरा किया और संस्थान में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं तथा अनुसंधान कार्यों का निरीक्षण किया।

संस्थान के डीन प्रोफेसर गुलाब चंद पमनानी ने महानिदेशक का स्वागत किया और उन्हें संस्थान की विभिन्न इकाइयों का अवलोकन कराया। इस दौरान उन्होंने पंजीकरण इकाई, पंचकर्म विभाग, बाह्य रोगी विभाग, आंतरिक रोगी विभाग, फार्मेसी और अत्याधुनिक केंद्रीय प्रयोगशाला की कार्यप्रणाली की जानकारी ली। प्रोफेसर आचार्य ने चिकित्सकों और कर्मचारियों से संवाद कर संस्थान की शैक्षणिक गतिविधियों तथा स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने संस्थान के शैक्षणिक खंड के साथ-साथ छात्रावासों की सुविधाओं का भी जायजा लिया। इसमें अंतरराष्ट्रीय छात्रावास, छात्राओं और छात्रों के छात्रावास शामिल रहे। प्रोफेसर गुलाब चंद पमनानी ने बताया कि संस्थान में प्रतिदिन 500 से अधिक मरीज बाह्य रोगी विभाग के माध्यम से परामर्श और उपचार प्राप्त कर रहे हैं।

प्रोफेसर रबीनारायण आचार्य ने संस्थान में उपलब्ध आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता की सराहना की। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद को प्रभावी चिकित्सा प्रणाली के रूप में स्थापित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान, आधुनिक तकनीक का उपयोग और मरीजों की जरूरतों पर आधारित सेवाओं पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

रेवाड़ी बार की हड़ताल पांचवें दिन भी जारी एसडीएम तबादले की मांग पर अड़े अधिवक्ता

भारतेन्दु संवाददाता, रेवाड़ी

रेवाड़ी जिला बार एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुक्रवार को लगातार पांचवें दिन भी जारी रही। अधिवक्ताओं ने साफ कर दिया है कि जब तक एसडीएम सुरेश कुमार का तबादला नहीं किया जाता, तब तक उनका धरना और न्यायिक कार्यों का बहिष्कार जारी रहेगा। सरकार की ओर से एसडीएम को छुट्टी पर भेजे जाने के बाद भी अधिवक्ता अपनी मांग पर अड़े हुए हैं।

बार एसोसिएशन ने कहा कि केवल अवकाश पर भेजना उनकी मांग का समाधान नहीं है। उनका कहना है कि एसडीएम का स्थायी तबादला किया जाना चाहिए। अधिवक्ताओं के अनुसार, एसडीएम सुरेश कुमार के कामकाज को लेकर लंबे समय से शिकायतें थीं। आरोप है कि वे मनमाने तरीके से फैसले लेते हैं और अधिवक्ताओं के साथ व्यवहार भी उचित नहीं रहा।

जानकारी के अनुसार, बार एसोसिएशन ने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी। इससे पहले भी अप्रैल महीने में अधिवक्ताओं ने सांकेतिक धरना दिया था और उपायुक्त, स्वास्थ्य मंत्री तथा क्षेत्रीय सांसद को ज्ञापन सौंपकर एसडीएम के स्थानांतरण की मांग उठाई थी। अधिवक्ताओं का आरोप है कि उस समय भी उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा।

एसडीएम को छुट्टी पर भेजने के बाद भी अधिवक्ताओं का आंदोलन जारी

अधिवक्ताओं ने कहा कि सरकार जब तक लिखित रूप से एसडीएम के तबादले का आदेश जारी नहीं करती, तब तक हड़ताल वापस नहीं ली जाएगी। बार एसोसिएशन का कहना है कि यह आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि न्यायिक व्यवस्था में बेहतर कार्यप्रणाली और सम्मानजनक माहौल की मांग को लेकर किया जा रहा है।

हड़ताल का असर जिला अदालतों के कामकाज पर साफ दिखाई दे रहा है। पिछले चार दिनों में बड़ी संख्या में मामलों की सुनवाई प्रभावित हुई है। शुक्रवार को भी कई मामलों में अगली तारीख देनी पड़ी। इससे अदालतों में आने वाले वादकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अधिवक्ताओं की हड़ताल लंबी चलने की स्थिति में न्याय की प्रतीक्षा कर रहे लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। वहीं प्रशासन और सरकार की अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अब देखना होगा कि सरकार और बार एसोसिएशन के बीच इस विवाद का समाधान कब तक निकल पाता है। आंदोलन के कारण न्यायिक कार्य प्रभावित हैं, जिससे आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

महिला आयोग अध्यक्ष का अस्पताल में औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी

मरीजों से ली सुविधाओं की जानकारी, गर्भवती महिला की जांच में देरी पर अधिकारियों को फटकार

भारतेन्दु संवाददाता, पानीपत

पानीपत जिला नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष उषा प्रियदर्शनी ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं में कई खामियां मिलने पर उन्होंने अधिकारियों और चिकित्सकों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने अस्पताल के विभिन्न विभागों, वार्डों, जांच केंद्रों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा किया। उन्होंने मरीजों से सीधे बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली। मरीजों से उपचार, जांच प्रक्रिया, दवाइयों की उपलब्धता और चिकित्सकीय सुविधाओं को लेकर फीडबैक लिया गया। इस दौरान कई मरीजों ने जांच और उपचार में देरी होने की शिकायतें भी सामने रखीं।

निरीक्षण के दौरान उषा प्रियदर्शनी अल्ट्रासाउंड केंद्र पहुंचीं। वहां एक गर्भवती महिला जांच कराने के लिए आई हुई थी, लेकिन उसे उसी दिन जांच की सुविधा देने के बजाय अगले बुधवार की तारीख दे दी गई थी। इस पर आयोग अध्यक्ष ने नाराजगी जताई और संबंधित चिकित्सक से देरी का कारण पूछा।

उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बार-बार अस्पताल के चक्कर लगवाना गंभीर लापरवाही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्भवती महिलाओं और अन्य जरूरतमंद मरीजों को समय पर जांच और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इसके बाद आयोग अध्यक्ष ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों, जांच केंद्रों और मरीजों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण किया। कई स्थानों पर साफ-सफाई की स्थिति, व्यवस्थाओं और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं में कमियां मिलने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से इन कमियों को जल्द दूर करने को कहा। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) से भी व्यवस्थाओं को लेकर जवाब-तलब किया गया। आयोग अध्यक्ष ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकारी अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज को समय पर उपचार, आवश्यक जांच और सम्मानजनक व्यवहार मिलना चाहिए।

उषा प्रियदर्शनी ने कहा कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में बड़ी संख्या में आम लोग इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में अस्पताल प्रशासन की

महिला आयोग अध्यक्ष ने अस्पताल में खामियां पकड़ीं, सुधार के सख्त दिए निर्देश

जिम्मेदारी है कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि मरीजों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और शिकायतों का समय पर समाधान होना चाहिए।

उन्होंने अस्पताल अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने, मरीजों की सुविधा बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि भविष्य में यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

राज्य महिला आयोग अध्यक्ष के इस औचक निरीक्षण के बाद अस्पताल प्रशासन में भी हलचल देखने को मिली। अधिकारियों ने जल्द ही कमियों को दूर करने और मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए नियमित निगरानी जरूरी है, ताकि मरीजों को बिना परेशानी के गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सके।

सिरसा में भाजपा नेता के आवास बोर्ड पर कालिख, पुलिस ने शुरू की जांच

भारतेन्दु संवाददाता, सिरसा

हरियाणा श्रम बोर्ड के चेयरमैन और भाजपा नेता रोहताश जांगड़ा के आवास के बाहर लगे संकेतक बोर्ड पर शरारती तत्वों द्वारा कालिख पोतने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, यह घटना गुरुवार देर रात की बताई जा रही है। भाजपा नेता रोहताश जांगड़ा का आवास सिरसा के हिसार रोड स्थित एक कॉलोनी में है। कॉलोनी के प्रवेश द्वार पर नगर परिषद सिरसा की ओर से एक संकेतक बोर्ड लगाया गया था। इसी बोर्ड पर शरारती तत्वों ने कालिख पोत दी और कुछ अक्षर भी लिख दिए।

रोहताश जांगड़ा ने बताया कि अज्ञात लोगों ने रात के समय इस घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है, ताकि घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा सके।

बताया जा रहा है कि कॉलोनी क्षेत्र में दिल्ली के जंतर-मंतर पर युवाओं और छात्रों द्वारा किए जा रहे आंदोलन से जुड़े कुछ पोस्टर भी लगाए गए हैं।

रोहताश जांगड़ा के आवास बोर्ड पर शरारती तत्वों की हरकत

हालांकि, बोर्ड पर कालिख पोतने की घटना को लेकर पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

घटना की जानकारी मिलने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष है। कार्यकर्ताओं ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि रोहताश जांगड़ा की पुत्रवधू नगर परिषद सिरसा में मनोनीत पार्षद हैं। उनके पार्षद मनोनीत होने के बाद नगर परिषद की ओर से कॉलोनी के प्रवेश द्वार पर यह संकेतक बोर्ड लगाया गया था। फिलहाल पुलिस घटना से जुड़े सभी तथ्यों की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और जल्द आरोपियों की पहचान का भरोसा जताया है।

न्यूज ब्रीफ

5 साल की मासूम से हैवानियत पर अदालत सख्त, दोषी को 40 साल की सख्त सजा

एजेंसी ,नई दिल्ली पानीपत की फास्ट ट्रैक कोर्ट (पाक्सो) ने पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी कृष्ण को 40 साल के कठोर कारावास और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट (पाक्सो) के न्यायाधीश पीयूष शर्मा की अदालत ने सुनाया। अभियोजन के अनुसार, 27 नवंबर 2024 को मतलौडा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी पांच वर्षीय बेटी घर के बाहर गली में खेल रही थी। उसी दौरान पड़ोसी कृष्ण उसे 20 रुपये देकर चीज दिलाने का झांसा देकर अपने घर ले गया और बच्ची के साथ गलत काम किया। रोती हुई बच्ची जब घर पहुंची, तब परिजनों को इस घिनौनी करतूत का पता चला। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल परीक्षण करवाने के बाद परिजनों के बयान के आधार पर केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह सख्त सजा सुनाई।

फरीदाबाद में रिश्तों का कत्ल, गर्भवती पत्नी की हत्या में पति गिरफ्तार

एजेंसी, नई दिल्ली ग्रीनफील्ड कॉलोनी में गर्भवती महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। अपराध शाखा एनआईटी की टीम ने हत्या के आरोप में मृतका के पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने पत्नी की हत्या करने की बात स्वीकार की है। पुलिस के अनुसार, आरोपी पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। इसी वजह से उसने घर में विवाद के बाद चुन्नी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए हत्या को चोरी की घटना का रूप देने की साजिश रची। आरोपी ने घर से कुछ आभूषण निकाल लिए और ऐसा दिखाने की कोशिश की कि चोरी के दौरान महिला की हत्या की गई है। लेकिन पुलिस जांच में कई अहम सुराग मिले, जिसके आधार पर मामले का खुलासा हुआ और पति को गिरफ्तार कर लिया गया। अपराध शाखा की टीम ने पूछताछ के दौरान आरोपी से सख्ती से जानकारी जुटाई, जिसमें उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान मिले सबूतों और पूछताछ के आधार पर आरोपी तक पहुंच बनाई गई। फिलहाल आरोपी को अदालत में पेश कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में खेल कोटे से प्रवेश शुरू, 27 जुलाई से काउंसलिंग

एजेंसी, नई दिल्ली प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सीयूईटी 2026 के तहत स्पोर्ट्स कोटा से प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग और फिजिकल फिटनेस टेस्ट की प्रक्रिया 27 जुलाई से शुरू होगी। विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स बोर्ड ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। स्पोर्ट्स कोटा के तहत प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि पर चैथम लाइंस स्थित प्रवेश भवन में उपस्थित होना होगा। यहां अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के साथ-साथ उनकी शारीरिक फिटनेस का परीक्षण भी किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभ्यर्थियों को समय पर पहुंचने और आवश्यक दस्तावेज साथ लाने के निर्देश दिए हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड के अनुसार, प्रवेश प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की खेल उपलब्धियों, प्रमाणपत्रों और फिटनेस टेस्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उम्मीदवारों को अपने सभी मूल प्रमाणपत्र, पहचान पत्र और संबंधित दस्तावेज लेकर पहुंचना होगा। विश्वविद्यालय ने कहा है कि स्पोर्ट्स कोटा के माध्यम से प्रवेश पाने वाले छात्रों का चयन निर्धारित नियमों और मानकों के अनुसार किया जाएगा। फिटनेस टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों को ही आगे की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

गाजियाबाद में परिवहन विभाग की पहल, पुराने वाहनों को हटाने के लिए जागरूकता अभियान

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ

कांवड़ यात्रा और श्रावण मेला-2026 की तैयारियों के साथ केंद्र सरकार की नई स्क्रैप नीति के प्रचार-प्रसार को लेकर परिवहन विभाग ने महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। यह बैठक बृहस्पतिवार को संभागीय परिवहन कार्यालय में हुई, जिसकी अध्यक्षता उप परिवहन आयुक्त, मेरठ परिक्षेत्र हरिशंकर सिंह ने की। बैठक में ट्रक और बस यूनियन के पदाधिकारियों, वाहन स्वामियों तथा अधिकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर (आरवीएसएफ) के संचालकों ने हिस्सा लिया।

बैठक में अधिकारियों ने वाहन स्वामियों को सरकार की नई योजना और इसके लाभों की जानकारी दी। बताया गया कि पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर पर जमा कर स्क्रैप कराने के बाद नए वाहन खरीदने पर विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। यदि वाहन मालिक अपने पुराने वाहन को स्क्रैप कराकर भारत सरकार की 'नया सफर योजना' के तहत यूरो-6 मानक वाले नए वाहन खरीदते हैं तो उन्हें वाहन कर में 10 साल तक छूट का लाभ मिलेगा।

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नई स्क्रैप नीति का उद्देश्य सड़कों से पुराने और अनुपयोगी वाहनों को हटाना तथा प्रदूषण को कम करना है। इसके साथ ही वाहन मालिकों को आधुनिक और सुरक्षित वाहनों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बैठक में मौजूद आरवीएसएफ संचालकों ने भी स्क्रैपिंग प्रक्रिया और इससे जुड़े नियमों की जानकारी साझा की।

कांवड़ यात्रा को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। अधिकारियों ने कहा कि यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना विभाग की प्राथमिकता है। इसके लिए वाहन संचालन, परमिट, फिटनेस और सुरक्षा मानकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वाहन यूनियन के प्रतिनिधियों से भी सहयोग की अपील की गई।

अधिकारियों ने वाहन स्वामियों से अपील की कि वे अधिकृत केंद्रों पर ही पुराने वाहनों को स्क्रैप कराएं, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि नई नीति से जहां वाहन मालिकों को आर्थिक फायदा मिलेगा, वहीं पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। परिवहन विभाग आने वाले दिनों में इस योजना को लेकर और जागरूकता अभियान चलाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।

कारगिल योद्धा 26 साल से अपने हक की लड़ाई में, जमीन और पेट्रोल पंप का इंतजार

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ

कारगिल युद्ध के वीर योद्धा लांस नायक सतबीर सिंह पिछले 26 वर्षों से अपने अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देश की रक्षा करते हुए घायल हुए सतबीर सिंह का आरोप है कि उन्हें सरकार की ओर से आवंटित जमीन वापस ले ली गई और पेट्रोल पंप देने का वादा भी अब तक पूरा नहीं किया गया। मुखमेलपुर गांव निवासी लांस नायक सतबीर सिंह ने कारगिल युद्ध के दौरान अदम्य साहस दिखाते हुए दुश्मनों का सामना किया था। युद्ध में घायल होने के बाद भी उन्होंने देश सेवा में अपना योगदान जारी रखा।

लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें अपने ही अधिकारों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। सतबीर सिंह का कहना है कि वीर सैनिकों के सम्मान और सुविधाओं के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन उनका लाभ समय पर नहीं मिल पाता। उन्होंने बताया कि उन्हें जो जमीन दी गई थी, उसे वापस ले लिया गया। इसके अलावा पेट्रोल पंप आवंटन का आश्वासन भी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कई बार संबंधित विभागों और अधिकारियों से शिकायत कर अपनी समस्या रखी, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं मिल सका है। उनका कहना है कि यह केवल उनकी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि उन सभी सैनिकों के सम्मान का सवाल है, जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया।

गाजीपुर ड्रेन की सफाई के लिए दो आधुनिक एक्सकेवेटर मशीनों का हुआ शुभारंभ

एजेंसी, नई दिल्ली

मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने और बड़े नालों की सफाई व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र के चिल्ला गांव स्थित गाजीपुर ड्रेन पर दो आधुनिक लॉन्ग बूम एम्फीबियस एक्सकेवेटर मशीनों का शुभारंभ किया गया। इन अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से गाजीपुर ड्रेन, यमुना नदी और अन्य बड़े नालों की डी-सिल्टिंग तथा सफाई कार्य को तेज गति से पूरा किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे जल निकासी व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार होगा और बरसात के दौरान जलभराव की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।

कार्यक्रम का नेतृत्व त्रिलोकपुरी के विधायक रविकांत ने किया, जबकि दिल्ली सरकार के लोक निर्माण, जल, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने मशीनों का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मशीनों की कार्यप्रणाली का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को सफाई कार्य में आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए लगातार आधुनिक संसाधनों और तकनीकों का उपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि बड़े नालों की समय पर सफाई और गाद निकालना मानसून प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन मशीनों के उपयोग से कम समय में अधिक क्षेत्र की सफाई संभव होगी और नालों की जल प्रवाह क्षमता भी बढ़ेगी।

विधायक रविकांत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन में दिल्ली को स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त और विकसित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।

नोएडा में निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक महंगी किताबें बेचने वालों पर कार्रवाई तय

एजेंसी, नई दिल्ली

नोएडा में 20 निजी स्कूलों पर जुर्माने की तैयारी

नोएडा। महंगे दामों पर किताबें और अन्य शैक्षणिक सामग्री बेचने वाले निजी स्कूलों पर अब जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। अभिभावकों से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद नोएडा जिला प्रशासन ने ऐसे 20 से अधिक निजी स्कूलों पर जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रशासन का कहना है कि स्कूलों द्वारा नियमों का उल्लंघन कर अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डाला जा रहा है।

अभिभावकों ने शिकायत की थी कि कई निजी स्कूल निर्धारित दुकानों से ही किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य सामान खरीदने के लिए दबाव बनाते हैं। इसके अलावा कुछ स्कूलों पर बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर किताबें उपलब्ध कराने के आरोप भी लगाए गए हैं। शिकायतों के आधार पर प्रशासन ने जांच कराई, जिसमें कई स्कूलों में अनियमितताएं सामने आने की बात कही जा रही है। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि जांच के बाद दोषी पाए गए स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों पर जुर्माना लगाने के साथ ही उन्हें भविष्य में ऐसी गतिविधियों से बचने के निर्देश दिए जाएंगे।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि छात्रों और अभिभावकों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है। निजी स्कूलों को नियमों का पालन करना होगा और अभिभावकों पर किसी भी प्रकार की जबरन खरीदारी का दबाव नहीं बनाया जा सकता। प्रशासन ने अभिभावकों से भी अपील की है कि यदि किसी स्कूल द्वारा अतिरिक्त शुल्क, महंगी किताबें या अन्य सामान खरीदने के लिए दबाव बनाया जाता है तो इसकी शिकायत संबंधित विभाग से करें। नोएडा प्रशासन की इस कार्रवाई से निजी स्कूलों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी स्कूलों की व्यवस्थाओं और फीस संबंधी मामलों की निगरानी जारी रखी जाएगी।

फरीदाबाद के कॉलेजों में एडमिशन का दौर शुरू, सीट सुरक्षित करने में जुटे छात्र

एजेंसी, नई दिल्ली

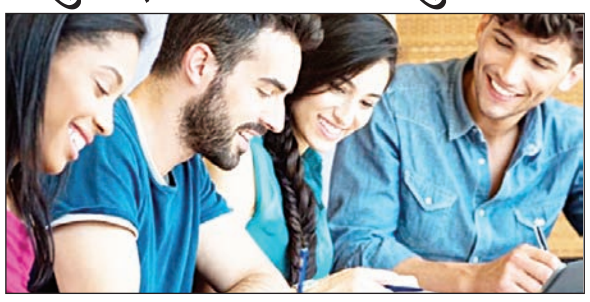

फरीदाबाद उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फरीदाबाद के कॉलेजों में पहली मेरिट सूची जारी होने के बाद अब विद्यार्थियों ने फीस जमा कर अपनी सीट पक्की करनी शुरू कर दी है। पहली मेरिट सूची में नाम आने वाले विद्यार्थियों को फीस भुगतान के लिए समय दिया गया है, ताकि वे अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकें। शिक्षा विभाग के अनुसार, पहली मेरिट सूची में शामिल विद्यार्थियों के लिए फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 27 जुलाई निर्धारित की गई है।

इसके बाद खाली बची सीटों के लिए दूसरी मेरिट सूची जारी की जाएगी। कॉलेजों में दाखिले को लेकर विद्यार्थियों में उत्साह देखा जा रहा है और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं ऑनलाइन माध्यम से फीस जमा कर रहे हैं। कॉलेज प्रशासन ने विद्यार्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय के अंदर फीस जमा कर दाखिला सुनिश्चित करें। फीस जमा नहीं करने वाले विद्यार्थियों की सीट रद्द हो सकती है और उनका स्थान दूसरे योग्य उम्मीदवारों को दिया जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि दाखिला प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन रखा गया है। विद्यार्थियों को किसी भी परेशानी से बचाने के लिए कॉलेजों में हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। जिन विद्यार्थियों का नाम पहली मेरिट सूची में नहीं आया है, उन्हें अगली सूची का इंतजार करना होगा। उच्चतर शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेजों को निर्देश दिए हैं कि दाखिला प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी की जाए।

कॉलेजों में नए सत्र की पढ़ाई जल्द शुरू करने की तैयारी भी की जा रही है। विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे विभाग की वेबसाइट और कॉलेजों की सूचनाओं पर लगातार नजर बनाए रखें, ताकि किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित न रहें।

ग्रेटर नोएडा में रेरा कार्यशाला में खरीदारों को जागरूक किया

एजेंसी, नई दिल्ली

ग्रेटर नोएडा ,उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (यूपी रेरा) ने घर खरीदारों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने के लिए एक विशेष जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संभावित खरीदारों और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला के दौरान यूपी रेरा के अधिकारियों ने घर खरीदने से पहले बरती जाने वाली सावधानियों, बिल्डर की जिम्मेदारियों और खरीदारों के अधिकारों की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि रेरा कानून का उद्देश्य खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाना है। अधिकारियों ने कहा कि घर खरीदने से पहले खरीदारों को प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी, रेरा पंजीकरण, बिल्डर का रिकॉर्ड और आवश्यक दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए।

दिल्ली के इस व्यस्त मार्ग को मिलेगी नई रफ्तार, एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए अध्ययन शुरू

एजेंसी, नई दिल्ली

दक्षिणी दिल्ली में 5 किमी एलिवेटेड कॉरिडोर की तैयारी

नई दिल्ली,दक्षिणी दिल्ली के अरुणा आसफ अली मार्ग पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव और जाम की समस्या को कम करने के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रस्तावित कॉरिडोर की लंबाई करीब 5 किलोमीटर होगी। इस परियोजना के पूरा होने के बाद क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और वाहन चालकों को जाम से राहत मिलने की उम्मीद है।

दिल्ली सरकार ने इस परियोजना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन (फिजिबिलिटी स्टडी) कराने को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 1.97 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। अध्ययन के दौरान यह देखा जाएगा कि एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किस प्रकार किया जाए, इसकी लागत कितनी होगी और इससे यातायात व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अरुणा आसफ अली मार्ग दक्षिणी दिल्ली का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में वाहन चलते हैं। पीक ऑवर के दौरान यहां अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

खासकर ऑफिस समय में वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं और यात्रा का समय बढ़ जाता है। अधिकारियों के अनुसार, एलिवेटेड कॉरिडोर बनने से मुख्य सड़क पर वाहनों का दबाव कम होगा और यातायात का संचालन अधिक सुगम हो सकेगा। परियोजना के तहत आधुनिक तकनीक और यातायात जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजना तैयार की जाएगी। व्यवहार्यता अध्ययन पूरा होने के बाद परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके आधार पर निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य दक्षिणी दिल्ली के प्रमुख इलाकों में यातायात व्यवस्था को सुधारना और लोगों को सुरक्षित व तेज आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना है।

आगरा में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 10 तेंदुओं की खाल समेत चार तस्कर गिरफ्तार

ड्राइंग रूम की सजावट के लिए बिक रही थी तेंदुओं की खाल, दिल्ली-हरियाणा तक होती थी सप्लाई

एजेंसी, नई दिल्ली

वन्यजीव तस्करी का बड़ा नेटवर्क उजागर

आगरा में वन विभाग ने वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना सैंया क्षेत्र में आगरा-ग्वालियर हाईवे स्थित एक होटल पर छापेमारी के दौरान टीम ने आरोपियों के कब्जे से 10 तेंदुओं की खाल और उनके सिर बरामद किए। बरामदगी के बाद वन विभाग ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से वन्यजीवों की तस्करी से जुड़े हुए थे और मध्य प्रदेश के शिवपुरी क्षेत्र से तेंदुओं की खाल लाकर दिल्ली तथा हरियाणा के ग्राहकों तक पहुंचाते थे।

वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, तेंदुओं की खाल और सिर की अवैध बाजार में काफी मांग रहती है। इनका उपयोग कुछ लोग अपने घरों, फार्महाउस और आलीशान भवनों के ड्राइंग रूम की सजावट के लिए करते हैं। तस्कर इसी मांग का फायदा उठाकर वन्यजीवों का शिकार करवाते और उनके अंगों की अवैध खरीद-फरोख्त करते थे। बरामद खाल और सिर को सुरक्षित कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाया जा रहा है कि बरामद अवशेष कितने अलग-अलग तेंदुओं के हैं और इनका शिकार कब तथा किस क्षेत्र में किया गया। पूछताछ में कई अन्य लोगों के नाम भी सामने आने की संभावना जताई जा रही है। वन विभाग अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटा है, ताकि तस्करी से जुड़े अन्य आरोपियों तक भी पहुंचा जा सके। अधिकारियों ने बताया कि वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत आरोपियों के खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। वन विभाग ने कहा कि तेंदुआ संरक्षित वन्यजीव है और उसके शिकार तथा अंगों की तस्करी गंभीर अपराध है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि यदि कहीं वन्यजीवों के अवैध शिकार या तस्करी की जानकारी मिले तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। अधिकारियों का कहना है कि वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए ऐसे अभियान आगे भी लगातार चलाए जाएंगे, ताकि जैव विविधता और प्राकृतिक संतुलन को सुरक्षित रखा जा सके तथा अवैध वन्यजीव कारोबार पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बरामद तेंदुओं की खाल और सिर की फॉरेंसिक तथा वन्यजीव विशेषज्ञों से जांच कराई जाएगी, जिससे यह पता लगाया जा सके कि इनका शिकार किस क्षेत्र में और कब किया गया। जांच एजेंसियां आरोपियों के मोबाइल फोन, संपर्कों और आर्थिक लेनदेन की भी पड़ताल कर रही हैं, ताकि तस्करी के पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके। अधिकारियों का मानना है कि इस गिरोह के तार अन्य राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं। वन विभाग ने स्पष्ट किया कि वन्यजीवों की तस्करी करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वन्यजीव संरक्षण में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित विभाग या स्थानीय प्रशासन को दें।

दिल्ली में छात्रों पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में गुरुग्राम कांग्रेस का डीसी कार्यालय तक मार्च

एजेंसी, नई दिल्ली

गुरुग्राम में गुरुवार को जिला कांग्रेस (शहरी एवं ग्रामीण) के बैनर तले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में छात्रों पर कथित लाठीचार्ज और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ हुए व्यवहार के विरोध में जिला सचिवालय स्थित डीसी कार्यालय तक मार्च निकाला। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जताई। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सचिवालय के मुख्य गेट पर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया।

इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई, हालांकि स्थिति नियंत्रण में रही और किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि दिल्ली में छात्रों की आवाज दबाने के लिए बल प्रयोग किया गया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। उन्होंने राहुल गांधी के साथ हुए कथित व्यवहार को भी लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि विपक्ष की आवाज दबाने और छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध को बलपूर्वक रोकने की कोशिश लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।

प्रदर्शन के बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। ज्ञापन में छात्रों के साथ हुई कथित कार्रवाई की जांच, लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा तथा विपक्षी नेताओं के सम्मानजनक व्यवहार की मांग उठाई गई। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। पुलिस बल पूरे समय मौके पर तैनात रहा और प्रशासन ने स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी।

खेल प्रतिभाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, सीधी भर्ती प्रक्रिया हुई शुरू

एजेंसी, नई दिल्ली

ग्रेटर नोएडा में अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार की सीधी भर्ती नियमावली-2022 के तहत विभिन्न विभागों में खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पात्र खिलाड़ी निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 अगस्त निर्धारित की गई है। इसके बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। खेल विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह भर्ती प्रक्रिया उन खिलाड़ियों के लिए है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर अपनी प्रतिभा साबित की है। चयन पूरी तरह नियमावली-2022 के प्रावधानों और पात्रता मानकों के आधार पर किया जाएगा। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। खिलाड़ियों को आवेदन करते समय अपनी शैक्षणिक योग्यता, खेल उपलब्धियों और अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में अपलोड करने होंगे।

जम्मू का होगा विस्तार, 777 वर्ग किमी में फैलेगा जम्मू शहर

बदलेगी जम्मू की तस्वीर, नए मास्टर प्लान के तहत 350 ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा शहरी स्वरूप

◆ **विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जम्मू का होगा व्यापक विस्तार**

जम्मू के भविष्य का नया खाका तैयार, विस्तार योजना से बदलेंगे गांव और शहर।

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू शहर के विकास और बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं को देखते हुए इसके विस्तार की बड़ी योजना तैयार की गई है। नए मास्टर प्लान के तहत जम्मू शहर के क्षेत्रफल में करीब **125 वर्ग किलोमीटर** की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस विस्तार के बाद जम्मू शहर का कुल क्षेत्रफल मौजूदा **652 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 777 वर्ग किलोमीटर** हो जाएगा। प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मंजूरी के बाद जम्मू की भौगोलिक सीमा और विकास का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा।

नए मास्टर प्लान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें करीब 350 ग्रामीण क्षेत्रों को जम्मू शहर के विस्तारित शहरी दायरे में शामिल करने की योजना बनाई गई है। इन क्षेत्रों के शामिल होने से गांवों में भी शहरी सुविधाओं का विस्तार होगा। बेहतर सड़क व्यवस्था, जल आपूर्ति, सीवरेज, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सुविधाएं और अन्य बुनियादी ढांचे को विकसित करने की दिशा में काम किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।

प्रशासन का मानना है कि जम्मू के तेजी से बढ़ते विस्तार और आबादी के दबाव को देखते हुए शहर की सीमाओं का विस्तार जरूरी हो गया है। वर्तमान में शहर के सीमित क्षेत्र में बढ़ती आबादी और निर्माण गतिविधियों के कारण कई तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं। नए मास्टर प्लान के माध्यम से भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुनियोजित विकास को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा।

इस विस्तार योजना से रियल एस्टेट क्षेत्र को भी नई गति मिलने की संभावना है। नए क्षेत्रों में आवासीय कॉलोनियों, व्यावसायिक केंद्रों और औद्योगिक गतिविधियों के विकास के अवसर बढ़ेंगे। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। युवाओं और व्यापारियों के लिए भी यह योजना आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली साबित हो सकती है। मास्टर प्लान में केवल क्षेत्रफल बढ़ाने पर ही नहीं बल्कि व्यवस्थित शहरी विकास पर भी जोर दिया गया है।

नए क्षेत्रों के जुड़ने से बदलेगा विकास का नक्शा

नए मास्टर प्लान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें करीब 350 ग्रामीण क्षेत्रों को जम्मू शहर के विस्तारित शहरी दायरे में शामिल करने की योजना बनाई गई है। इन क्षेत्रों के शामिल होने से गांवों में भी शहरी सुविधाओं का विस्तार होगा। बेहतर सड़क व्यवस्था, जल आपूर्ति, सीवरेज, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सुविधाएं और अन्य बुनियादी ढांचे को विकसित करने की दिशा में काम किया जाएगा।

25 जुलाई को होने वाली 11वीं बोर्ड परीक्षा स्थगित

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (जेकेबोस) ने 25 जुलाई 2026 को प्रस्तावित हायर सेकेंडरी पार्ट-1 यानी कक्षा 11वीं की सालाना (प्राइवेट) और द्विवार्षिक परीक्षा को स्थगित करने का फैसला लिया है। बोर्ड की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना में बताया गया कि शनिवार को होने वाली परीक्षा अब निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित नहीं की जाएगी। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बोर्ड की ओर से बाद में अलग से की जाएगी। जेकेबोस के निदेशक अकादमिक डॉ. परवीन सिंह की ओर से जारी सूचना में सभी संबंधित छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को नए परीक्षा कार्यक्रम के लिए बोर्ड की आधिकारिक अधिसूचनाओं पर नजर रखने की सलाह दी गई है। बोर्ड ने छात्रों से किसी भी तरह की अफवाह या भ्रम से बचने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है। हालांकि जम्मू-कश्मीर स्टेट ओपन स्कूल (जेकेएसओएस) की 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये परीक्षाएं जम्मू, श्रीनगर, लेह और करगिल स्थित परीक्षा केंद्रों पर पहले से जारी डेट शीट के अनुसार ही आयोजित होंगी।

झेलम नदी ने बढ़ाई चिंता, घाटी में बाढ़ जैसे हालात

झेलम का बढ़ा जलस्तर, घाटी में बाढ़ जैसे हालात की आहट

बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, कश्मीर की नदियां उफान पर।

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। कश्मीर घाटी में लगातार चौथे दिन हो रही बारिश से हालात चिंताजनक हो गए हैं। भारी बारिश के कारण झेलम नदी समेत कई नदियों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि शुक्रवार को कुछ स्थानों पर पानी का स्तर धीरे-धीरे कम होना शुरू हुआ, लेकिन कई निगरानी केंद्रों पर स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। दक्षिण कश्मीर में बारिश का सबसे अधिक असर देखने को मिला। अनंतनाग और श्रीनगर में झेलम नदी का जलस्तर बाढ़ की चेतावनी सीमा के करीब पहुंच गया था।

संगम क्षेत्र में जलस्तर में कमी दर्ज की गई, लेकिन कई स्थानों पर नदी अभी भी खतरे के निशान के आसपास बह रही है। श्रीनगर के मुंशी बाग इलाके में झेलम का जलस्तर बाढ़ स्तर से ऊपर दर्ज किया गया। लगातार बारिश को देखते हुए प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में बारिश जारी रहने की संभावना है, जिसके चलते नदी-नालों के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है।

यात्रा स्थगित होते ही खाली दौड़ रहीं कटड़ा की वंदे भारत ट्रेनें

कटड़ा में वैष्णो देवी यात्रा बंद, वंदे भारत की सीटें रह गईं खाली

◆ **छठे दिन भी वैष्णो देवी यात्रा स्थगित, 20 हजार श्रद्धालु कटड़ा में फंसे**

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में खराब मौसम और लगातार बारिश का असर अब धार्मिक पर्यटन और रेल सेवाओं पर भी दिखाई देने लगा है। माता वैष्णो देवी की यात्रा लगातार छठे दिन स्थगित रहने के कारण कटड़ा जाने वाले यात्रियों की संख्या में भारी कमी आई है। इसका सीधा असर अमृतसर-कटड़ा रूट पर चलने वाली वंदे भारत समेत कई ट्रेनों की बुकिंग पर पड़ा है। जिन ट्रेनों में सामान्य दिनों में यात्रा करने के लिए सीटों की लंबी प्रतीक्षा सूची रहती थी, उनमें अब यात्रियों की संख्या काफी कम हो गई है और कई सीटें खाली नजर आ रही हैं।

माता वैष्णो देवी मंदिर देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है। हर साल लाखों श्रद्धालु देश के अलग-अलग हिस्सों से कटड़ा पहुंचकर माता के दर्शन करते हैं। विशेष रूप से गर्मियों और छुट्टियों के मौसम में कटड़ा जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिलती है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने कई विशेष ट्रेनों का संचालन भी किया है। इनमें वंदे भारत जैसी आधुनिक और तेज गति वाली ट्रेनें यात्रियों की पहली पसंद बनी हुई हैं। लेकिन इस समय मौसम की स्थिति ने यात्रा की पूरी व्यवस्था को प्रभावित कर दिया है।

जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश और कई क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका के कारण प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए माता वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया है। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा जांच और हालात की समीक्षा की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और मौसम सामान्य होने के बाद ही यात्रा को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया जाएगा।

यात्रा बंद होने के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु कटड़ा में फंस गए हैं। बताया जा रहा है कि हजारों यात्रियों को यात्रा शुरू होने का इंतजार करना पड़ रहा है। कई श्रद्धालुओं ने अपनी यात्रा की योजना को आगे बढ़ा दिया है या टिकट रद्द करा दिए हैं। इसका असर रेलवे की बुकिंग व्यवस्था पर भी पड़ा है।

शहीद आशिक कुरैशी के घर पहुंचे मनोज सिन्हा, दिया हर मदद का आश्वासन

◆ **बलिदानी हेड कांस्टेबल के परिवार को एलजी ने दी सांत्वना**

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अनंतनाग आतंकी हमले में बलिदान हुए हेड कांस्टेबल **आशिक हुसैन कुरैशी** के परिवार से मुलाकात कर उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिया। शुक्रवार को उपराज्यपाल बडगाम जिले के लालपोरा, बीरवाह स्थित बलिदानी पुलिसकर्मी के घर पहुंचे और परिजनों से बातचीत कर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान जम्मू-कश्मीर पुलिस के महानिदेशक नलिन प्रभात, आईजी वीके बर्डी और बडगाम के डिप्टी कमिश्नर अथर आमिर खान भी मौजूद रहे। मनोज सिन्हा ने आशिक हुसैन कुरैशी के बलिदान को नमन करते हुए कहा कि देश को उनकी वीरता, कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण पर गर्व है। उन्होंने कहा कि बलिदानी पुलिसकर्मी की सेवा भावना और साहस आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। उपराज्यपाल ने परिवार को आश्वासन दिया कि प्रशासन हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा रहेगा और उनकी आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि बलिदानी के बेटे की पढ़ाई पूरी होने और पात्रता पूरी करने तक प्रशासन पूरा सहयोग करेगा, ताकि उसे अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी मिल सके। गौरतलब है कि 22 जुलाई को अनंतनाग के लाल चौक इलाके में आतंकियों ने ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी को निशाना बनाकर हमला किया था, जिसमें वे बलिदान हो गए थे। घटना के बाद सुरक्षाबलों ने आतंकवाद विरोधी अभियान तेज कर दिया है।

जेएंडके में 80वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को भव्य और सुरक्षित तरीके से आयोजित करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य सचिव अटल दुल्लू ने नागरिक प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्रीनगर और जम्मू में होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के अलावा जिला, उपमंडल, तहसील, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि समारोह से जुड़ी सभी तैयारियां समय से पहले पूरी कर ली जाएं। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पेयजल, चिकित्सा सुविधाओं, बिजली आपूर्ति, स्वच्छता और बैठने की व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया।

न्यूज ब्रीफ

जम्मू-कश्मीर में बारिश का कहर, पांच दिन में 32 मौतें

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में लगातार पांच दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। झेलम समेत कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। खराब मौसम के कारण माता वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है, जिससे हजारों श्रद्धालु प्रभावित हुए हैं।

ऑपरेशन पहचान में बड़ा खुलासा, बांग्लादेश से जम्मू कश्मीर तक फैले घुसपैठ नेटवर्क की जांच तेज

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। ऑपरेशन पहचान के तहत जांच एजेंसियों ने घुसपैठियों के एक बड़े नेटवर्क की पड़ताल शुरू की है। जांच में सामने आया है कि बांग्लादेश के रास्ते भारत में प्रवेश करने वाले कुछ विदेशी नागरिकों को फर्जी पहचान दस्तावेज उपलब्ध कराकर अलग-अलग क्षेत्रों में बसाने में मदद की गई। यह नेटवर्क जम्मू-कश्मीर के कुछ सीमावर्ती जिलों तक फैला होने की आशंका जताई जा रही है। एजेंसियां विदेशी फंडिंग, दस्तावेज तैयार करने वाले लोगों और स्थानीय मददगारों की भूमिका की जांच कर रही हैं। कठुआ सहित कई इलाकों में कार्रवाई के बाद जांच का दायरा और बढ़ाया गया है।

अनंतनाग हमले पर मंत्री सकीना इटू सख्त बोलीं- हिंसा से प्रभावित होता है विकास

भारतेंदु संवाददाता, अनंतनाग। अनंतनाग में पुलिस अधिकारी पर हुए हमले की मंत्री सकीना इटू ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि हिंसा की ऐसी घटनाएं समाज और क्षेत्र के विकास को पीछे धकेलती हैं। मंत्री ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान हिंसा नहीं हो सकता और शांति एवं स्थिरता के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और क्षेत्र में अमन बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया। घटना के बाद प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

अनंतनाग आतंकी हमले के बाद कश्मीर में बड़ा अभियान, ओजीडब्ल्यू नेटवर्क पर शिकंजा

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। अनंतनाग आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे कश्मीर में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। पुलिस हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी की शहादत के बाद घाटी में हाई अलर्ट जारी है। जांच में घटनास्थल और सीसीटीवी फुटेज से अहम सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर हमलावर की पहचान की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों के मददगार ओजीडब्ल्यू नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए कई संदिग्धों से पूछताछ शुरू की है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षाबल तैनात कर निगरानी बढ़ा दी गई है।

अमरनाथ सहित सभी यात्राएं आज भी रहेंगी स्थगित

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में खराब मौसम व लगातार हो रही बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा, माता वैष्णो देवी यात्रा, शिव खोड़ी यात्रा और मचैल माता यात्रा शनिवार को भी नहीं शुरू हो पाई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के खराब मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए प्रशासन ने 19 जुलाई शनिवार शाम को ही इन यात्रों को रोक दिया था। जम्मू-श्रीनगर राष्टीय राजमार्ग भारी बारिश, भूस्खलन व पत्थर गिरने से आज लगातार तीसरे दिन भी बंद है और रामबन में अभी भी कई गाड़ियां फंसी हुई है।

आसिफ जलाल जम्मू सीमांत के नए आईजी बीएसएफ का संभालेंगे कार्यभार

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। आईपीएस अधिकारी आसिफ जलाल सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जम्मू सीमांत के नए महानिरीक्षक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। आईजी जलाल शशांक आनंद का स्थान लेंगे जिन्होंने पिछले वर्ष फरवरी में जम्मू सीमांत का कार्यभार संभाला था। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार हिमाचल प्रदेश कैडर के 2002 बैच के आईपीएस अधिकारी आसिफ जलाल अगले कुछ दिनों में रणनीतिक जम्मू सीमांत की कमान संभाल लेंगे जो पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। जलाल को फरवरी 2022 में सीमा सुरक्षा बल में महानिरीक्षक नियुक्त किया गया था और बीएसएफ में उनका कार्यकाल 23 सितंबर, 2027 तक है।

नौशहरा में बाढ़ पीड़ितों से मिले रविंदर रैना, मानवर नदी पर तटबंध की उठी मांग

◆ **लोगों ने उठाई सुरक्षा दीवार और तटबंध निर्माण की मांग**

भारतेंदु संवाददाता, राजौरी। जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के नौशहरा क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने प्रभावित परिवारों से बातचीत कर बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी ली। इस दौरान लोगों ने क्षेत्र में हर वर्ष आने वाली बाढ़ की समस्या को प्रमुखता से उठाते हुए स्थायी समाधान की मांग की।

स्थानीय नागरिकों ने बताया कि मानवर नदी में बारिश के दौरान जलस्तर अचानक बढ़ जाता है, जिससे आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बाढ़ के कारण खेतों, मकानों, सड़कों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचता है। लोगों का कहना है कि लंबे समय से इस समस्या से जूझने के बावजूद अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। ग्रामीणों ने रविंदर रैना के सामने मानवर नदी के किनारे मजबूत और स्थायी तटबंध बनाने की मांग रखी।

उनका कहना था कि यदि नदी के किनारे सुरक्षा बांध का निर्माण किया जाता है तो बाढ़ के समय होने वाले कटाव और जलभराव को काफी हद तक रोका जा सकता है। इसके अलावा लोगों ने श्मशान घाट के पास सुरक्षा दीवार बनाने की भी मांग उठाई, ताकि नदी के तेज बहाव से वहां होने वाले नुकसान को रोका जा सके।

रविंदर रैना ने लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों तक उनकी मांग पहुंचाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सुरक्षा और क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाने का प्रयास किया जाएगा।

उड़ी में बादल फटने से तबाही, सेना ने देवदूत बन बचाई ग्रामीणों की जान

भारतेंदु संवाददाता, बारामुला। जम्मू-कश्मीर के उड़ी क्षेत्र के मायन इलाके में बादल फटने से अचानक आई फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचा दी। तेज पानी के बहाव के कारण घोरेताल नाले ने अपना रास्ता बदल लिया, जिससे मुकामपुरान गांव के कई घर पानी से घिर गए। हालात इतने गंभीर हो गए कि कई ग्रामीण अपने घरों में ही फंस गए और उनका बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया। बाढ़ के साथ आए मलबे ने गांव तक पहुंचने वाले रास्तों को भी बंद कर दिया, जिससे राहत और बचाव कार्य में मुश्किलें बढ़ गईं। संकट की इस घड़ी में भारतीय सेना ने तुरंत मोर्चा संभाला और बचाव अभियान शुरू किया। सेना के जवानों ने जोखिम उठाते हुए फंसे हुए ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाला। बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों को विशेष प्राथमिकता देते हुए उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। सेना की तत्परता और साहसिक प्रयासों से कई परिवारों को राहत मिली। स्थानीय लोगों ने आपदा के समय सेना की मदद और मानवीय प्रयासों की सराहना की। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अब प्रभावित क्षेत्रों में हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आपदा से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है और प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं।

रेलवे परिसरों की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंपने पर मंथन, बोर्ड ने मांगी रिपोर्ट

◆ **आरपीएफ से सीआईएसएफ को सुरक्षा हस्तांतरण की तैयारी**

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। देशभर के रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने की संभावना है। रेलवे बोर्ड ने रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) से सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को सौंपने की संभावनाओं को लेकर जोनल रेलवे और आरपीएफ के मुख्य सुरक्षा आयुक्तों से रिपोर्ट मांगी है। हालांकि इस संबंध में अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

रेलवे बोर्ड ने सभी जोनों से सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसमें पिछले तीन वर्षों में आरपीएफ के स्वीकृत और कार्यरत बल की स्थिति, रेलवे संपत्ति के खिलाफ दर्ज अपराधों का विवरण, यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में की गई कार्रवाई और लंबित मामलों की जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति का भी आकलन किया जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, यह जानकारी संसद में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों के उत्तर की तैयारी के लिए जुटाई जा रही है। रेलवे बोर्ड सरकार और संसद के सामने सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करना चाहता है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे की प्रक्रिया और निर्णय पर विचार किया जाएगा। आरपीएफ वर्तमान में रेलवे परिसरों, ट्रेनों और यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालता है।

भूस्खलन 36 घंटे बाद खुला जम्मू-श्रीनगर हाईवे फिर बंद, देवाल में भारी भूस्खलन से बढ़ी यात्रियों की परेशानी

जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर सात जगह लैंडस्लाइड, यातायात ठप

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। उधमपुर। जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही मूसलधार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। भारी बारिश के कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग ह॥-44 पर कई स्थानों पर भूस्खलन और पहाड़ों से मलबा गिरने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है। राजमार्ग बंद होने के कारण बड़ी संख्या में वाहन और पर्यटक रास्ते में फंस गए हैं। कई यात्री पिछले करीब 36 घंटे से मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं।

प्रशासन ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर जखैनी से चिनैनी तक कई संवेदनशील स्थानों पर पत्थर गिरने और मलबा आने से सड़क बंद हुई है। देवाल क्षेत्र में भारी भूस्खलन के कारण राजमार्ग को दोबारा बंद करना पड़ा। इससे पहले करीब 36 घंटे तक बंद रहने के बाद सिंगल ट्यूब के जरिए नियंत्रित तरीके से वाहनों की निकासी शुरू की गई थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद हालात फिर बिगड़ गए।

समरोली क्षेत्र में जल निकासी मार्ग मलबे से भर जाने के कारण बारिश का पानी सड़क पर बहने लगा, जिससे सड़क के कमजोर हिस्सों को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ गया है। इसके अलावा कैफेटेरिया, मंकी मोड़, बैटरी चश्मा, डलवास और नाशरी से बनिहाल के बीच भी कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं दर्ज की गई हैं।

सड़क बहाली के लिए संबंधित विभागों की टीमें लगातार काम कर रही हैं और मलबा हटाने का प्रयास जारी है। हालांकि लगातार बारिश के कारण राहत और मरम्मत कार्यों में बाधाएं आ रही हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मौसम की स्थिति सामान्य होने तक अनावश्यक यात्रा से बचें। साथ ही यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सफर शुरू करने से पहले राष्ट्रीय राजमार्ग की ताजा स्थिति की जानकारी जरूर लें।

प्रशासन ने लोगों से यात्रा टालने की अपील की

प्रशासन ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर जखैनी से चिनैनी तक कई संवेदनशील स्थानों पर पत्थर गिरने और मलबा आने से सड़क बंद हुई है। देवाल क्षेत्र में भारी भूस्खलन के कारण राजमार्ग को दोबारा बंद करना पड़ा। इससे पहले करीब 36 घंटे तक बंद रहने के बाद सिंगल ट्यूब के जरिए नियंत्रित तरीके से वाहनों की निकासी शुरू की गई थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद हालात फिर बिगड़ गए। समरोली क्षेत्र में जल निकासी मार्ग मलबे से भर जाने के कारण बारिश का पानी सड़क पर बहने लगा, जिससे सड़क के कमजोर हिस्सों को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ गया है। इसके अलावा कैफेटेरिया, मंकी मोड़, बैटरी चश्मा, डलवास और नाशरी से बनिहाल के बीच भी कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं दर्ज की गई हैं। सड़क बहाली के लिए संबंधित विभागों की टीमें लगातार काम कर रही हैं और मलबा हटाने का प्रयास जारी है। हालांकि लगातार बारिश के कारण राहत और मरम्मत कार्यों में बाधाएं आ रही हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मौसम की स्थिति सामान्य होने तक अनावश्यक यात्रा से बचें।

उधमपुर में मडस्लाइड, तीन घर मलबे की चपेट में

उधमपुर में लगातार बारिश से भूस्खलन, स्कूल में बनाए गए अस्थायी आश्रय

जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश से मडस्लाइड, जनजीवन प्रभावित।

भारतेंदु संवाददाता, उधमपुर। जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। चिनैनी क्षेत्र के बप्प तहसील अंतर्गत बरकुंडा गांव में बारिश के चलते भूस्खलन की घटना सामने आई, जिसमें मिट्टी और कीचड़ युक्त मलबा तीन मकानों तक पहुंच गया। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रभावित तीनों परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

भूस्खलन की चपेट में सरन दास, प्रीतम चंद और मक्खन लाल के मकान आए थे। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इन परिवारों को सरकारी मिडिल स्कूल बरकुंडा में अस्थायी रूप से ठहराया है। अधिकारियों की टीम लगातार प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर रही है और हालात पर नजर बनाए हुए है।

भारी बारिश के कारण क्षेत्र की कई सड़कों पर पत्थर गिरने और मलबा आने से यातायात भी प्रभावित हुआ है। संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंचकर सड़कों से मलबा हटाने और आवाजाही सुचारु करने के काम में जुटी हुई हैं। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से सतर्क रहने और संवेदनशील क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है।

न्यूज ब्रीफ

अवैध खनन के खिलाफ 5 आरोपियों पर मामला दर्ज

भारतेन्दु संवाददाता, इंदौरा। पुलिस जिला नूरपुर द्वारा क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत, मंड इंदौरा पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के तहत 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मंड इंदौरा क्षेत्र (वार्ड न. 11) में मानसून सत्र के दौरान सरकार द्वारा लगाए गए खनन प्रतिबंध का उल्लंघन कर लोडर एवं ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के माध्यम से अवैध खनन करने पर यह मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में अवैध खनन में संलिप्त पाए जाने पर बंटी, शिव, शाकू तथा लोडर मालिक नरेंद्र सिंह उर्फ बब्बू और नासर (सभी निवासी मंड इंदौरा) के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की विस्तृत जांच जारी है, ताकि घटना में प्रयुक्त अन्य वाहनों, मशीनरी एवं संलिप्त सह-आरोपियों की पहचान कर आगे की सख्त कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जा सके।

नशे के खिलाफ युवा निभाएं जिम्मेदार भूमिका: डीएसपी

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय, घुमारवीं के हेल्थ अवेयरनेस एंड एंटी ड्रग सेल द्वारा 'एंटी चिट्टा अभियान' के तहत 'नशे के दुष्प्रभाव एवं जागरूकता' विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में घुमारवीं के डीएसपी विशाल वर्मा ने मुख्य वक्ता के रूप में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए 'चिट्टा' सहित विभिन्न नशीले पदार्थों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभावों की जानकारी दी। उन्होंने युवाओं से नशे और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी किसी भी सूचना को तुरंत पुलिस या प्रशासन तक पहुंचाने का आह्वान किया तथा एनडीपीएस अधिनियम के कठोर प्रावधानों से भी अवगत कराया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. प्रीतम सिंह ने विद्यार्थियों से परिसर में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना प्रशासन को देने और 'नशामुक्त हिमाचल' अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने का आग्रह किया। कार्यक्रम में लगभग 100 विद्यार्थियों ने भाग लेकर नशामुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया। अंत में प्रोफेसर जीवेश नड्डा ने सभी का आभार व्यक्त किया।

सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए आवेदन आमंत्रित

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र बिलासपुर मनोज सकलानी ने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण योजना (पीएमएफएमई) के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना व उन्नयन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना का उद्देश्य स्थानीय कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करना है। 18 वर्ष से अधिक आयु के युवा, महिलाएं, किसान, स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन, सहकारी समितियां तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़े उद्यमी इसका लाभ उठा सकते हैं। योजना के अंतर्गत परियोजना लागत पर 35 प्रतिशत तक (अधिकतम 10 लाख रुपये) की क्रेडिट लिंक्ड पूंजी अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। लाभार्थी को न्यूनतम 10 प्रतिशत अंशदान देना होगा, जबकि शेष राशि बैंक ऋण के माध्यम से मिलेगी। इच्छुक आवेदक जिला उद्योग केंद्र बिलासपुर से संपर्क कर सकते हैं तथा पीएमएफएमई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।

दूसरे चरण में एमबीए-एमसीए की 165 सीटें आवंटित

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने संबंधित शिक्षण संस्थानों में एमबीए व एमसीए की सीटें ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से आवंटित की दूसरे चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग में एचपीसीईटी की मेरिट के आधार पर कुल 165 सीटें आवंटित की गई, जिसमें एमबीए की 88 और एमसीए की 77 सीटें शामिल है। काउंसलिंग में जिन अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित हुई हैं, उन्हें संबंधित शिक्षण संस्थान में 27 जुलाई सायं पांच बजे तक रिपोर्ट करनी होगी। तकनीकी विवि के अधिष्ठाता शैक्षणिक डॉ. राजेश कुमार शर्मा ने कहा कि एमबीए और एमसीए की तीसरे चरण की सीटें 29 जुलाई को आवंटित की जाएगी।

कैडेटों ने दिखाया अनुशासन व नेतृत्व का उत्कृष्ट परिचय

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर के राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) आर्मी विंग के कैडेटों ने द्वितीय हिमाचल प्रदेश एनसीसी बटालियन, मंडी द्वारा आयोजित वार्षिक प्रशिक्षण शिविर (एटीसी-231) में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर महाविद्यालय एवं बटालियन का नाम गौरवान्वित किया। यह 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर 13 से 22 जुलाई 2026 तक राजकीय बहु-तकनीकी संस्थान, सुंदरनगर में आयोजित किया गया, जिसमें महाविद्यालय के 47 कैडेटों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शिविर के दौरान सभी कैडेटों को चार कंपनियों में विभाजित किया गया, जबकि बिलासपुर महाविद्यालय के कैडेटों को ब्रावो कंपनी में स्थान मिला। ब्रावो कंपनी का नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर करण चौहान ने कंपनी सीनियर के रूप में किया। उनके साथ अंडर ऑफिसर पंकज शर्मा, कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट रिया कुमारी तथा सार्जेंट मुस्कान ने अनुशासन बनाए रखने, प्रशिक्षण गतिविधियों के सफल संचालन और कैडेटों के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नेतृत्व और समर्पण की सराहना शिविर में व्यापक रूप से की गई।

एक माह के भीतर करवाएं ई-केवाईसी सत्यापन

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों का सत्यापन (ई-केवाईसी) जिला कल्याण अधिकारी व तहसील कल्याण अधिकारी के माध्यम से जुलाई 2025 में आरम्भ किया गया था। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा सत्यापन की अन्तिम तिथि 28 फरवरी, 2026 निर्धारित की गई थी और कुल 7,84,976 लाभार्थियों का आधार आधारित ई-केवाईसी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि ऐसे सामाजिक सुरक्षा पेंशनर जिन्होंने अभी तक अपना ई-केवाईसी सत्यापन नहीं किया है वे सम्बधित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में एक माह के भीतर अपनी ई-केवाईसी सत्यापन सुनिश्चित करवाएं।

प्रदेश की आईटीआई में प्रशिक्षकों की भारी कमी 200 यूनिटें बंद, 4500 छात्र दाखिले से वंचित

131 सरकारी आईटीआई में प्रशिक्षकों के 722 पद लंबे समय से रिक्त पड़े

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में प्रशिक्षकों की भारी कमी का असर अब तकनीकी शिक्षा व्यवस्था पर साफ दिखने लगा है।

केंद्र सरकार के प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) की सख्ती के बाद प्रदेश के विभिन्न आईटीआई में 200 से अधिक यूनिट (कक्षाएं) बंद कर दी गई हैं। इसके चलते चालू शैक्षणिक सत्र में करीब 4500 से 5000 सीटों पर प्रवेश नहीं हो पाएगा, जिससे हजारों युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्रभावित होंगे। प्रदेश की 131 सरकारी आईटीआई में प्रशिक्षकों के 722 पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं। डीजीटी ने प्रशिक्षकों की ई-केवाईसी और पदों की मैपिंग के बाद स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्येक यूनिट के लिए अलग नियमित प्रशिक्षक होना अनिवार्य होगा। पहले कई संस्थानों में एक ही प्रशिक्षक दो से तीन यूनिटों को संभाल रहा था, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था को मान्यता नहीं दी जा रही। इसके परिणामस्वरूप प्रशिक्षक विहीन यूनिटों को बंद करना पड़ा है। सबसे अधिक प्रभावित ट्रेडों में प्लंबर, मोटर मेकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, वेल्डर, फैशन डिजाइनिंग, पंप ऑपरेटर, कढ़ाई, स्टेनो हिंदी और एम्ब्रॉयडरी शामिल हैं। इन ट्रेडों की यूनिटें विभिन्न आईटीआई में बंद होने से विद्यार्थियों के लिए विकल्प सीमित हो गए हैं। डीजीटी ने फिलहाल कुछ मामलों में 50 प्रतिशत तक की राहत देकर व्यवस्था को चलाने की अनुमति दी है। इसके बावजूद 200 से अधिक यूनिट बंद हो चुकी हैं। यदि रिक्त पदों पर जल्द भर्ती नहीं हुई तो अगले शैक्षणिक सत्र में 80 प्रतिशत तक ट्रेड प्रभावित हो सकते हैं। इससे कई आईटीआई की कार्यक्षमता और अस्तित्व पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। यह संकट केवल विद्यार्थियों तक सीमित नहीं है। ट्रेड बंद होने से उद्योगों को मिलने वाला प्रशिक्षित मानव संसाधन भी प्रभावित होगा। साथ ही करोड़ों रुपये की लागत से स्थापित मशीनरी, कार्यशालाएं और प्रशिक्षण अवसंरचना का पूरा उपयोग नहीं हो सकेगा। उधर, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बताया कि बीते दिनों हुई कैबिनेट बैठक में प्रशिक्षकों के 140 पद भरने को मंजूरी दी गई है। डीजीटी से भी छूट देने के लिए पत्राचार जारी है। सीटों में बड़ी कटौती के कारण हजारों अभ्यर्थियों को अब निजी आईटीआई का रुख करना पड़ सकता है। निजी संस्थानों में प्रशिक्षण शुल्क सरकारी आईटीआई की तुलना में काफी अधिक होता है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों के सामने अतिरिक्त बोझ खड़ा होने की आशंका है।

हर यूनिट के लिए अलग प्रशिक्षक अनिवार्य

आईटीआई में एक ट्रेड के तहत सामान्यतः एक से तीन यूनिट संचालित होती हैं और प्रत्येक यूनिट में 20 से 24 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। डीजीटी के नए मानकों के अनुसार हर यूनिट के लिए अलग प्रशिक्षक की उपलब्धता अनिवार्य है। इसी आधार पर संस्थानों की प्रवेश क्षमता तय की जा रही है। प्रशिक्षक उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित यूनिट में दाखिले की अनुमति नहीं दी जा रही।

आईटीआई में सीटों की कटौती से हजारों युवाओं पर असर निजी संस्थानों का बढ़ेगा दबाव

दो चचेरे भाईयों ने एक साथ नीट की परीक्षा पास कर डॉक्टर बनने की राह की सशक्त

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। ऐसा बहुत कम वाकया हुआ है कि एक ही परिवार के दो भाईयों ने एक साथ कोई प्रतियोगी परीक्षा पास की हो। यह कारनामा कर दिखाया है नादौन विधानसभा क्षेत्र के गलोड़ के गांव बुधवीं के दक्ष और हर्ष ने। इन दोनों भाईयों ने दक्ष और हर्ष ने प्रारंभिक शिक्षा नवदीप पब्लिक स्कूल बुधवीं से हासिल की। इसके बाद हर्ष ने केंद्रीय विद्यालय हमीरपुर से 12वीं की, जबकि दक्ष ने हिम अकादमी पब्लिक स्कूल विकासनगर से 10वीं और सुपर मैग्नेट पब्लिक स्कूल हमीरपुर से 12वीं की पढ़ाई पूरी की। डॉक्टर बनने के सपने को साकार करने के लिए दोनों ने आकाश इंस्टीट्यूट हमीरपुर से नीट की तैयारी की और नीट-2026 व री-नीट परीक्षा में सफलता हासिल की।

दक्ष के माता-पिता सविता और विकेश कौशल सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं, जबकि हर्ष के पिता कंवरजीत कौशल भी शिक्षक हैं और माता सुमन गृहिणी हैं। बुधवीं गांव में उस समय खुशी का माहौल बन गया, जब एक ही परिवार के दो चचेरे

भाइयों दक्ष और हर्ष ने नीट-2026 परीक्षा उत्तीर्ण कर डॉक्टर बनने की दिशा में कदम बढ़ाया। दोनों की सफलता ने न केवल परिवार, बल्कि पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। गांव में बधाइयों का दौर जारी है। दोनों भाई स्वर्गीय भागीरथ कौशल के पोते हैं। उनकी दादी तारा कौशल ने भावुक होते हुए कहा कि यदि आज उनके दादा जीवित होते तो दोनों की इस उपलब्धि पर सबसे अधिक खुश होते। दोनों ने सफलता का श्रेय माता-पिता, गुरुजनों को दिया है पंचायत के पूर्व प्रधान संजीव शर्मा बीडीसी सदस्य सहित अन्य लोगों ने दोनों की उपलब्धि पर खुशी प्रकट की। दोनों युवाओं ने कहा कि लक्ष्य के प्रति दृढ़ विश्वास और निरंतर मेहनत सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है।

डमटाल पुलिस के पकड़े गए 41.40 ग्राम चिट्टे मामले में 5वां आरोपी काबू

भारतेन्दु संवाददाता, नूरपुर। पुलिस जिला नूरपुर द्वारा नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त असामाजिक तत्वों एवं तस्करों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है।

इसी कड़ी में थाना डमटाल पुलिस की टीम द्वारा पूर्व में पकड़े गए चिट्टे के एक मामले में 5वें आरोपी को भी धर दबोचा है। बीते 15 मई 2026 को 41.40 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद की गई थी। इस मामले की गहन जांच तथा डिजिटल लेन-देन के विश्लेषण के दौरान यह पाया गया कि आरोपी दीपक उर्फ दीपू (उम्र 27 वर्ष) निवासी गांव व डाकघर कंडवाल, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा ने मुख्य आरोपी अमन से डिजिटल पेमेंट के माध्यम से हेरोइन खरीदी थी। वित्तीय व तकनीकी विश्लेषण के आधार पर नशीले पदार्थों के इस नेटवर्क में आरोपी की संलिप्तता (फॉरवर्ड लिंक) स्थापित होने पर

पुलिस चौकी ढांगूपीर की टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपी दीपक उर्फ दीपू को धारा 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी नूरपुर इल्मा अफरोज ने बताया कि मामले में आगामी कानूनी कार्रवाई व जांच नियमानुसार जारी है, ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा सके। उन्होंने बताया कि नूरपुर पुलिस अपने क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार एवं तस्करी में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति अपनाते हुए सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

मंडी के टिहरा में होगा कारगिल विजय दिवस समारोह

भगत सिंह गुलेरिया, भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। मंडी जिला के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के टिहरा में 26 जुलाई को राज्य स्तरीय कारगिल विजय दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा।

इस समारोह की अध्यक्षता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता व सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल (डॉ.) धनीराम शांडिल करेंगे। समारोह की की तैयारियों की समीक्षा के लिए उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त ने कहा कि कारगिल विजय दिवस राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों के सम्मान में हर वर्ष मनाया जाता है। इस बार यह राज्य स्तरीय समारोह मंडी जिला में आयोजित किया जा रहा है। इस अति महत्वपूर्ण समारोह के सफल आयोजन के लिए उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश

दिए। उन्होंने उपमंडलाधिकारी (ना.) धर्मपुर को समारोह स्थल पर सभी आवश्यक प्रबंध समय रहते सुनिश्चित करने को कहा। लोक निर्माण विभाग को मंच एवं पंडाल सहित आगंतुकों के लिए पार्किंग व्यवस्था इत्यादि के समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि समारोह में पधारने वाली सभी वीर नारियों, शहीदों के परिजनों व पूर्व सैनिकों के स्वागत सम्मान के लिए समुचित प्रबंध किए जाएं।

उन्होंने जिला सैनिक कल्याण विभाग को वीर नारियों, युद्ध वीरों, शहीदों के आश्रितों, पूर्व सैनिकों एवं विशिष्ट अतिथियों के स्वागत, ठहराव व परिवहन इत्यादि में संबंधित विभागों से समन्वय करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस समारोह में देशभक्ति पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए स्थानीय प्रशासन को पूर्व सैनिक लीग एवं जिला भाषा, संस्कृति विभाग के समन्वय से तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। पुलिस विभाग को कानून एवं व्यवस्था, सुरक्षा व यातायात व्यवस्था से संबंधित आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने को कहा।

झंडूता में एचपीवी टीकाकरण अभियान, बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव का प्रयास

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। स्वास्थ्य खंड झंडूता में महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाने के लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस (एचपीवी) टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. अतुल भारद्वाज ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण एचपीवी संक्रमण है, जिससे समय पर टीकाकरण के माध्यम से बचाव संभव है। उन्होंने बताया कि भारत में हर वर्ष इस बीमारी के बड़ी संख्या में मामले सामने आते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपनी पात्र बेटियों का समय पर टीकाकरण करवाने की अपील की है। अभियान के तहत 14 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी तथा 15 वर्ष से कम आयु की बालिकाएं पात्र हैं। 15 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद भी 90 दिनों की अतिरिक्त अवधि में टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध है। एचपीवी वैक्सीन की एक खुराक सर्वाइकल कैंसर से 90 से 95 प्रतिशत तक सुरक्षा प्रदान करती है।

अक्तूबर में बनकर तैयार होगा हमीरपुर का नया बस स्टैंड

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। हमीरपुर शहर में पानी, बिजली व अन्य केबल को अंडरग्राउंड करने के लिए ढाई किमी लंबा यूटिलिटी डक्ट बनाया जाएगा, जिसकी डीपीआर लगभग तैयार हो गई है। डीपीआर को मंजूरी मिलते ही इसका कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

मुख्य बाजार और मेन रोड़ दोनों सड़कों के भीतर इसका निर्माण होगा। नया निर्माणाधीन बस अड्डा अक्तूबर माह के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी आठ मंजिलें होंगी, चार मंजिलें

बेसमेंट में हैं, एक ग्राउंड फ्लोर है और तीन मंजिलें ऊपर तैयार होंगी। जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर रहेगा। चार मंजिलों के बेसमेंट में वैंक्वेट हाल भी तैयार होगा, जिसे किराए पर दिया जा सकता है। तैयार होने के बाद इसका परपज कोई और होगा, तो उस पर भी इसकी सुविधा मिल सकती है, जिसे जितनी जरूरत होगी, उस हिसाब से इसकी जगह आवंटित होगी। बस अड्डे के बगल से निकलने वाले नाले की चेनेलाइजेशन का काम भी चल रहा है और यह सारा काम अक्तूबर माह तक मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा 150 करोड़ रुपए की लागत से मौजूदा बस अड्डे की जगह सिटी सेंटर का भी निर्माण किया जाएगा। इसकी भी डीपीआर तैयार हो रही है।

6 मंजिल वाले इस केंद्र में पहली तीन बेसमेंट में कार पार्किंग की सुविधा बनेगी और बाकी जगह अलग तरह का सिस्टम तैयार होगा। विशेष बातचीत में पीडब्ल्यूडी के हमीरपुर स्थित एक्सीईंट दीपक कपिल और एसडीओ संजय कटोच ने बताया कि इन दोनों डीपीआर पर काम हो रहा है। सिटी सेंटर के लिए 150 करोड़ सरकार ने निर्माण के लिए पैसा आवंटित भी कर दिया है, जबकि यूटिलिटी डक्ट के लिए 15 करोड़ डिपॉजिट मनी भी मिल गया है। इन अधिकारियों ने बताया कि सिटी सेंटर की 6 मंजिलें बनेंगी। पार्किंग की ज्यादा समस्या है, इसीलिए तीन बेसमेंट में कार पार्किंग की सुविधा होगी। मुख्य बाजार से जोड़ने के लिए, फिलहाल वहां पर ओवरब्रिज की कोई प्लानिंग नहीं है। लेकिन उनका कहना था कि आगे चलकर यदि इसकी जरूरत महसूस हुई तो इसका भी निर्माण हो सकता है। उनका कहना था कि यूटिलिटी डक्ट की चैड़ाई 5 फिट रहेगी और हाइट कम से कम 6 फुट तैयार होगी, यह हाइट व्यवस्था के हिसाब से बढ़ भी सकती है। डीसी ऑफिस से लेकर मुख्य बाजार से भोटा चैक तक और फिर भोटा चैक से नादौन चैक तक इसका निर्माण होगा। डीपीआर तैयार हो रही है। करीब ढाई किलोमीटर लंबा यह यूटिलिटी डक्ट बनेगा। इसके लिए फिलहाल 15 करोड़ रुपए मिल गया है और यह प्रोजेक्ट बड़े बजट का होगा शुरुआत में जितना बन पाएगा उतना तैयार होगा उसे इसकी यूटिलिटी का भी अंदाजा होगा और जैसे-जैसे बजट का प्रोविजन होगा, इसका निर्माण मुकम्मल हो जाएगा।

हमीरपुर शहर में ढाई किमी लंबा बनेगा यूटिलिटी डक्ट

नीट पेपर लीक मामले को लेकर एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। नीट पेपर लीक मामले को लेकर एनएसयूआई ने शहर में धरना-प्रदर्शन किया। रैली कॉलेज परिसर से शुरू होकर उपायुक्त कार्यालय तक पहुंची, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। एनएसयूआई प्रदेश संगठन महामंत्री अंशुल रावत ने कहा कि नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक की घटनाओं से लाखों छात्रों के भविष्य पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन का उद्देश्य छात्रों की आवाज को उठाना और उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करना है। उन्होंने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अंशुल रावत ने कहा कि छात्रों को न्याय मिलने और जवाबदेही तय होने तक एनएसयूआई का आंदोलन जारी रहेगा।

3.20 लाख ऑनलाइन साइबर ठगी के मामले में बिहार से एक और आरोपी काबू

भारतेन्दु संवाददाता, नूरपुर। पुलिस जिला नूरपुर द्वारा ऑनलाइन साइबर अपराधों के विरुद्ध जारी कार्रवाई के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है। वर्ष 2024 में थाना नूरपुर में दर्ज ऑनलाइन ठगी के मामले में त्वरित व कड़ा संज्ञान लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

18 जनवरी, 2024 को शिकायतकर्ता शिमला देवी निवासी तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि अज्ञात साइबर अपराधियों ने फोन कॉल के माध्यम से उन्हें झांसे में लेकर 3 लाख 20 हजार की ऑनलाइन ठगी की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक पुलिस जिला नूरपुर साईबर सैल को शामिल कर एक विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम द्वारा तकनीकी विश्लेषण, डिजिटल ट्रैकिंग, बैंक खातों, सीडीआर, वित्तीय लेन-देन एवं अन्य डिजिटल साक्ष्यों का गहन विश्लेषण करते हुए विभिन्न राज्यों में लगातार दबिश दी। तकनीकी जांच के आधार पर इस अंतरराज्यीय नेटवर्क का

पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी महाबीर कुमार को पुलिस टीम द्वारा पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले की जांच के दौरान नूर आलम निवासी दक्षिण तेलुआ थाना नौतन पश्चिम चंपारण जिला बेतिया, बिहार की संलिप्तता भी सामने आई। इसके उपरांत तकनीकी जांच व डिजिटल साक्ष्यों को आगे बढ़ाते हुए मामले में संलिप्त आरोपी नूर आलम के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में अन्य संभावित पहलुओं की जांच नियमानुसार जारी है। उधर एसपी नूरपुर ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अज्ञात कॉल, ओटीपी, क्यूआर कोड, लिंक अथवा ऑनलाइन लेन-देन के प्रति सतर्क रहें।

कैडेट्स ने दिखाया अनुशासन और जज्बा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को मिला सम्मान

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। 1 एचपी नेवल यूनिट एनसीसी बिलासपुर के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का भव्य समापन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में कैडेट्स ने शानदार परेड प्रस्तुत कर अपने अनुशासन, आत्मविश्वास और प्रशिक्षण के दौरान अर्जित कौशल का प्रदर्शन किया। समारोह के मुख्यातिथि मेजर सुशील कुमार कौंडल (सेवानिवृत्त), कमांडेंट 5वीं बटालियन होमगार्ड्स रहे, जबकि अध्यक्षता कैंप कमांडेंट कमांडर सज्जन कुमार ने की।

मुख्यातिथि ने कहा कि एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और राष्ट्रभक्ति की भावना विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। कैंप कमांडेंट ने शिविर के दौरान आयोजित सैन्य प्रशिक्षण, व्यक्तित्व विकास, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विभिन्न प्रतियोगिताओं की जानकारी दी। समापन अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स और संस्थानों को सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ संस्थान का पुरस्कार एनआईटी हमीरपुर को मिला। वहीं वुड्स पार्क सैनिक स्कूल हमीरपुर को मोस्ट स्पिरिटेड इंस्टीट्यूशन और सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक प्रस्तुति का सम्मान प्राप्त हुआ। सर्वश्रेष्ठ एसडी कैडेट का पुरस्कार कैडेट कैप्टन दीक्षित धीमान (जीडीसी सुजानपुर), सर्वश्रेष्ठ एसडब्ल्यू कैडेट का पुरस्कार कैडेट दक्षिता (जीपीजीसी बिलासपुर), सर्वश्रेष्ठ जेडी कैडेट का पुरस्कार कैडेट सम्वेद त्रिपाठी और सर्वश्रेष्ठ जेडब्ल्यू कैडेट का पुरस्कार कैडेट अंजनी संजन (दोनों वुड्स पार्क सैनिक स्कूल हमीरपुर) को प्रदान किया गया। समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। शिविर से विदा हुए कैडेट्स अनुशासन, नेतृत्व, टीम भावना और राष्ट्रसेवा के संकल्प के साथ लौटे।

परेशानी मानसून हुआ सक्रिय, प्रदेश में 130 से अधिक सड़कें बंद और 370 पेयजल योजनाएं प्रभावित

प्रदेश में 27 से 29 जुलाई तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल में मानसून के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं। एक ओर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है तो दूसरी ओर ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम ने सर्दियों जैसा एहसास करा दिया है। कुल्लू जिले के हनुमान टिब्बा, देउ टिब्बा, सार पास, रोहतांग दर्रा तथा आसपास की अधिक ऊंचाई वाली चोटियों पर हल्की ताजा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद इन क्षेत्रों का तापमान गिरा है और पहाड़ों ने एक बार फिर सफेद चादर ओढ़ ली है। मौसम विभाग का कहना है कि 27 जुलाई से प्रदेश में मानसून और अधिक सक्रिय होगा तथा कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 76.2 मिलीमीटर बारिश नैना देवी (बिलासपुर) में रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा जोत (चंबा) में 75.2 मिमी, घमरूर

(कांगड़ा) में 61.6 मिमी, ओलिंडा (बिलासपुर) में 42.0 मिमी, बीबीएमबी बिलासपुर में 40.4 मिमी, सराहन (शिमला) में 30.5 मिमी और नंगल डैम (ऊना) में 29.6 मिमी बारिश हुई। प्रमुख शहरों में कांगड़ा में 24.6 मिमी, शिमला में 20.4 मिमी, धर्मशाला में 19.3 मिमी, माशोबरा में 18.5 मिमी, ऊना में 18.0 मिमी, देहरा गोपीपुर में 16.3 मिमी, कसौली में 14.0 मिमी, सैंज में 13.0 मिमी, नाहन में 12.8 मिमी, पालमपुर और मनाली में 11-11 मिमी, सोलन में 10.6 मिमी तथा बारमौर में 10 मिमी बारिश दर्ज की गई। लगातार हो रही बारिश का असर जनजीवन पर भी साफ दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों हुई व्यापक बारिश के कारण प्रदेश में अब भी 130 से अधिक सड़कें बंद हैं।

इसके अलावा 60 बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं, जबकि 370 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। प्रशासन ने संबंधित विभागों को बहाली कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। खासकर नदी-नालों, खड्डों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने तथा खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार 25 जुलाई को प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना को लेकर येलो अलर्ट रहेगा। 26 जुलाई को भी कई स्थानों पर भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद 27, 28 और 29 जुलाई को मानसून और अधिक जोर पकड़ेगा तथा कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इन दिनों अचानक बाढ़, भूस्खलन और नालों का जलस्तर बढ़ने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। 30 जुलाई को भी प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट रहेगा। प्रदेश के शहरों के न्यूनतम तापमान पर नजर डालें तो आज सबसे कम तापमान लाहौल स्पीति जिला के केलांग में 11.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद कुकुमसेरी 11.9, भरमौर 12.0, ताबो 13.7, कल्पा 14.8, कुफरी 14.7, धर्मशाला 16.2, शिमला 16.4, डलहौजी 16.5, माशोबरा 16.9, कसौली 17.5, मनाली 17.9, कोटखाई 18.3, सैंज 19.0, जुब्बड़हट्टी 19.5, पालमपुर, सोलन और सेओबाग 20.0, भुंतर 20.8, ऊना 21.0, नाहन 21.1, कांगड़ा 22.2, सुंदरनगर 22.6, नेरी 22.7, सराहन 22.9, मंडी और हमीरपुर 23.6, बरठीं 23.8, बिलासपुर और पांवटा साहिब 24.0 तथा सबसे अधिक न्यूनतम तापमान देहरा गोपीपुर में 25.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

मंडी के गुम्मा में चट्टान की चपेट में आने से महिला की मौत

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। मंडी जिले के जोगिंदरनगर उपमंडल के गुम्मा क्षेत्र में शुक्रवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। कुल्लू से मां सिमसा मंदिर के दर्शन के लिए जा रहा एक परिवार रास्ते में पानी पीने के लिए रुका था। इसी दौरान पहाड़ी से अचानक चट्टान गिर गई, जिसकी चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि सात अन्य लोग घायल हो गए। हादसे में रामेश्वरी शर्मा, पत्नी गोपालकृष्ण, निवासी सुलतानपुर (कुल्लू) की मौके पर ही मौत हो गई। घायल सातों लोगों को स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से तुरंत नागरिक अस्पताल जोगिंदरनगर पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार परिवार दो वाहनों में सवार होकर कुल्लू से मां सिमसा मंदिर के दर्शन के लिए निकला था। शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे गुम्मा के पास सभी लोग पानी पीने के लिए रुके। इसी दौरान पहाड़ी से अचानक चट्टान गिर गई और लोग उसकी चपेट में आ गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। पुलिस ने मामले दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

डांका कोविनिच का खूबसूरत अंदाज

मोंटेनेग्रो। डांका कोविनिच मोंटेनेग्रो की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्होंने कई ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं में भाग लिया है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व किया है।

दूसरा टी20 वैभव सूर्यवंशी और मयंक यादव पर रहेंगी निगाहें

जिम्बाब्वे से सीरीज जीतने उतरेगी टीम इंडिया

एजेंसी, हरारे

कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में अपनी पहली जीत से वापसी की राह पर अग्रसर भारत शनिवार को यहां होने वाले दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में अपनी जीत की लय बरकरार रखने की कोशिश करते हुए जिम्बाब्वे के खिलाफ अजेय बढ़त हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध होगा। आयरलैंड (0-2) और इंग्लैंड (0-4) से हारने के बाद तीन बार के टी20 विश्व कप विजेता भारत सीरीज के पहले मैच में हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन करते हुए जिम्बाब्वे को सात विकेट से हराकर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली।

युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की 19 गेंदों में खेली गई 50 रन की पारी और मयंक यादव (चार ओवर में 18 रन देकर दो विकेट) की तूफानी गेंदबाजी ने भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिम्बाब्वे ने हाल में अपने घरेलू मैदानों पर अच्छा प्रदर्शन किया था। भारत ने सूर्यवंशी के अर्द्धशतक, इशान किशन के 35 रन और कप्तान अय्यर की 28 रन की नाबाद पारी की बदौलत छह ओवर और सात विकेट शेष रहते हुए 126 रन के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर दिया। दो साल पहले हरारे स्पोर्ट्स क्लब में अपने टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत करते हुए अपने दूसरे ही मैच में ही शतक बनाने वाले अभिषेक शर्मा पहले मैच में नहीं चल पाए थे और वह उसकी भरपाई करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे।

सूर्यवंशी ने टी20 अंतरराष्ट्रीय में अर्द्धशतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड बनाया। इस युवा बल्लेबाज को इससे काफी राहत मिली होगी, क्योंकि इंग्लैंड दौरे पर उन्हें विशेष रूप से शॉर्ट पिच गेंदों से निशाना बनाया जा रहा था। भारतीय टीम प्रबंधन हालांकि, बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन से ज्यादा युवा तेज गेंदबाजी आक्रमण के सामूहिक प्रयास से खुश होगा। वीवीएस लक्ष्मण इस सीरीज में मुख्य कोच की भूमिका निभा रहे हैं।

भारत ने परिस्थितियों से अच्छी तरह से तालमेल बिठाया। तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने भी इस मैच में अच्छा प्रदर्शन किया और 29 रन देकर दो विकेट लिए। अशोक शर्मा ने भी अपनी गति से प्रभावित किया, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मयंक की शीर्ष स्तरीय क्रिकेट में सफल वापसी थी, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण के बाद चोटिल के कारण लगभग दो साल मैदान से बाहर रहे।

पहले मैच में मयंक की गति और नियंत्रण दोनों ही बेहतरीन थे, जिसमें जिम्बाब्वे के प्रमुख बल्लेबाज ब्रायन बेनेट को बाहर की तरफ स्विंग लेने वाली गेंद पर आउट करना महत्वपूर्ण था। जिम्बाब्वे को पावरप्ले में जरूरत से ज्यादा विकेट गंवाने का अफसोस रहेगा। उसके बल्लेबाज भारतीय तेज गेंदबाजों का सामना करने में नाकाम रहे और भारत के सामने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य नहीं रख पाए।

मैच : शाम 4.30 बजे से

संभावित टीमें

भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), इशान किशन (विकेटकीपर), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, हर्ष दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, अशोक शर्मा, प्रिंस यादव, रवि बिश्नोई, मयंक यादव, यश ठाकुर।

जिम्बाब्वे: सिकंदर रजा (कप्तान), बेन करन, इनोसेंट काला, तादिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर, डायोन मायर्स, तफदजवा त्सिगा (विकेटकीपर), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, ब्रैड इवांस, वेस्ले मधेवेरे, तनाका चिवांगा, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्लेसिंग मुजाराबानी, रिचर्ड नगारवा, न्यूमैन न्यामुरी।

कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी

मीराबाई और लवलीना बनीं भारतीय दल की ध्वजवाहक

एजेंसी, ग्लासगो

ग्लासगो ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का शानदार स्वागत किया। ओवीओ हाइड्रो में एक भव्य ओपनिंग सेरेमनी के साथ 2026 एडिशन की आधिकारिक शुरुआत हुई। इस सेरेमनी में स्कॉटलैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और खेल की उत्कृष्टता का मेल देखने को मिला और 11 दिनों तक चलने वाले बेहतरीन मुकाबलों के लिए मंच तैयार हुआ।

ओलंपिक मेडलिस्ट मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ने ध्वजवाहक के तौर पर 'परेड ऑफ नेशंस' में भारतीय दल का गर्व से नेतृत्व किया। जब तिरंगा एरिना में पहुंचा, तो भीड़ ने जोरदार तालियों और उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। वेटलिफ्टिंग में टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई देश की ध्वज-वाहक बनीं। वहीं, टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली बॉक्सर लवलीना ने कॉमनवेल्थ बैटन (छड़ी) संभाली, जो एक और सफल अभियान के लिए भारत की उम्मीदों का प्रतीक है।

कॉमनवेल्थ परंपरा के अनुसार, किंग चार्ल्स तृतीय ने औपचारिक रूप से खेलों की शुरुआत की। 2014 के बाद ये खेल पहली बार ग्लासगो लौटे हैं। यह सेरेमनी स्कॉटिश पहचान का जश्न थी, जिसमें संगीत, नृत्य और कहानी कहने की कला का शानदार मिश्रण देखने को मिला। मशहूर कलाकारों केटी टुनस्टॉल, नाथन इवांस और सेंट फीनिक्स ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दीं।

स्पोर्ट्स विंडो

सेमवाल, रविकुमार और रतिका सिंगापुर स्क्वाश के क्वार्टर फाइनल में

एजेंसी, सिंगापुर। ओम सेमवाल, संदेश रविकुमार और रतिका सीलान शुक्रवार को यहां कड़े मुकाबलों में जीत दर्ज करके पीएसए सिंगापुर चैलेंजर स्क्वाश टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। रविकुमार ने पुरुषों के दूसरे दौर में जापान के सातवीं वरीयता प्राप्त शोता यासुनश्री को 12-10, 11-5, 3-11, 11-7 से हराया, जबकि चौथी वरीयता प्राप्त सेमवाल ने स्थानीय खिलाड़ी आरोन लियांग को 11-9, 4-11, 4-11, 12-10, 11-8 से पराजित किया। तीसरी वरीयता प्राप्त रतिका ने महिला वर्ग के दूसरे दौर में स्थानीय प्रतिद्वंद्वी वाई लिन औ योंग को 8-11, 11-9, 11-2, 7-11, 12-10 से हराया।

आनंद विश्व शतरंज की सर्वोच्च संस्था फिडे के अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त

एजेंसी, नई दिल्ली। पांच बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने विश्व शतरंज महासंघ (फिडे) के अंतरिम अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। फिडे अध्यक्ष अर्कादी ड्वोरकोविच के यूरोपीय संघ की प्रतिबंधित सूची में शामिल होने के बाद उन्होंने प्रतिबंध हटने तक पद से अलग होने का फैसला किया है। यूरोपीय संघ ने रूस-यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में ड्वोरकोविच पर प्रतिबंध लगाया है। इसके तहत उनके बैंक खाते फ्रीज किए जा सकते हैं और उन पर यात्रा संबंधी पाबंदियां भी लग सकती हैं। ड्वोरकोविच ने इस फैसले को अदालत में चुनौती देने की घोषणा की है। फिडे ने बयान जारी कर कहा कि परिषद ने ड्वोरकोविच के अपने अधिकार, कर्तव्य और विशेषाधिकारों से अस्थायी रूप से अलग होने के फैसले को स्वीकार कर लिया है। फिडे चार्टर के अनुच्छेद 19.2 के तहत, प्रतिबंध लागू रहने तक उपाध्यक्ष विश्वनाथन आनंद अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे। आनंद 2022 से फिडे के उपाध्यक्ष हैं। ड्वोरकोविच ने यूरोपीय संघ के फैसले को गैर-कानूनी और अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा कि वह इसे चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध से फिडे के कामकाज पर असर पड़ सकता है, इसलिए संगठन के सुचारु संचालन के लिए उन्होंने अस्थायी रूप से पद छोड़ने का निर्णय लिया है।

भारत में एशेज टेस्ट कराने की सोच रहा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया

एजेंसी, मेलबर्न। इस साल के आखिर में चेन्नई में बिग बैश लीग कराने के बाद क्रिकेट आस्ट्रेलिया भविष्य में भारत में एशेज टेस्ट भी कराने की सोच रहा है । क्रिकेट आस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी टॉड ग्रीनबर्ग ने फिलहाल किसी योजना से इनकार किया । आस्ट्रेलिया दिसंबर में चेन्नई में बिग बैश लीग के पहले मैच की मेजबानी करेगा। ग्रीनबर्ग ने बीबीसी स्टम्प्ड पॉडकास्ट में कहा,''इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई से हमारे रिश्ते मजबूत हैं । साफ तौर पर भारत में कुछ और क्षेत्रों में और कंटेंट लाने की जरूरत है ।'' उन्होंने कहा,''फिलहाल तो कोई योजना नहीं है लेकिन इस पर विचार किया जा सकता है । भारत, आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट अभी भी काफी मजबूत है। हम इसे और मजबूत बनाने की कोशिश करते रहेंगे।'' ग्रीनबर्ग ने यह भी कहा कि क्रिकेट का व्यस्त कार्यक्रम इस प्रस्ताव के रास्ते में आ सकता है, जिसके लिए तीनों संस्थाओं के बीच बड़े पैमाने पर आयोजन संबंधी तालमेल की जरूरत होगी।

मोटरस्पोर्ट संस्था एफएमएससीआई को मिला राष्ट्रीय खेल महासंघ का दर्जा

एजेंसी, नई दिल्ली। खेल मंत्रालय ने फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब्स ऑफ इंडिया (एफएमएससीआई) को राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) के रूप में अस्थायी मान्यता दे दी है। इसे 2028 तक भारत में फॉर्मूला वन (एफ-1) रेस की वापसी की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। एफएमएससीआई ने 11 जून को मान्यता के लिए आवेदन किया था। मंत्रालय ने 23 जुलाई को जारी आदेश में संस्था को तत्काल प्रभाव से अस्थायी एनएसएफ का दर्जा दिया। साथ ही राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 के अनुरूप तय समय सीमा के भीतर संविधान में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश भी दिए हैं। 1971 में स्थापित एफएमएससीआई भारत में एफ-1 की वापसी की रणनीति पर मंत्रालय के साथ लगातार काम कर रही है। सरकार ने मान्यता प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राज्य इकाइयों की न्यूनतम संबद्धता से जुड़े कुछ मानदंडों में भी छूट दी है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यदि संस्था वित्तीय पारदर्शिता, डोपिंग रोधी नियमों, सुशासन या अन्य निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन नहीं करती है, तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है। पिछले महीने खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत में प्रमुख मोटरस्पोर्ट प्रतियोगिताओं की मेजबानी की संभावनाओं का आकलन करने के लिए एक कार्यबल गठित करने की घोषणा की थी। यह कार्यबल आर्थिक, पर्यटन और निवेश संबंधी लाभों के साथ बुनियादी ढांचे और संचालन संबंधी जरूरतों का भी अध्ययन करेगा।

अनाहत सिंह जूनियर स्क्वाश विश्व चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में

एजेंसी, ओंटारियो

भारत की उभरती खिलाड़ी और यहां शीर्ष वरीयता प्राप्त अनाहत सिंह ने अपने धैर्य और कौशल का शानदार नमूना पेश करते हुए चार गेम तक चले मैच में जीत दर्ज करके विश्व जूनियर स्क्वाश व्यक्तिगत चैंपियनशिप के महिला एकल के सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

महिला रैंकिंग में विश्व की 20वें नंबर की खिलाड़ी अनाहत ने क्वार्टरफाइनल में मिस्र की हबीबा रिज्क को 11-7, 11-5, 6-11, 11-9 से हराया। इस प्रतियोगिता में पिछले साल कांस्य पदक जीतने वाली अनाहत इस तरह से विश्व जूनियर चैंपियनशिप में लगातार दो बार सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। दिल्ली की रहने वाली यह खिलाड़ी खिताब जीतने की प्रबल दावेदार बनी हुई है। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला मिस्र की बार्ब समेह से होगा।

यह दमन की भावना के खिलाफ है विद्रोह: संजय मांजरेकर

एजेंसी, नई दिल्ली। पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के खिलाफ चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हुए इसे 'लोकतंत्र में दमन की भावना के खिलाफ विद्रोह' करार दिया है। उन्होंने कड़े शब्दों का उपयोग करते हुए एक्स पर लिखा कि आंदोलन को रोकने के लिए बल प्रयोग करने से किसी तरह का हल नहीं निकलेगा। मांजरेकर ने कहा, ''यह केवल नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने का मामला नहीं है। यह लोकतंत्र में दमन की भावना और मुख्यधारा के मीडिया के दुष्प्रचार के खिलाफ विद्रोह है।'' उन्होंने कहा, ''मैं दो बच्चों का पिता हूं और यह अच्छी तरह से जानता हूं कि आज के युवाओं को दबाना और उनका 'ब्रेनवॉश' करना कभी कारगर साबित नहीं होगा।'' इससे पहले दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता पूर्व निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने छात्रों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान की मांग की थी।

राष्ट्रमंडल खेलों के पदकों पर अंकित है ब्रेल लिपि

एजेंसी, ग्लासगो

राष्ट्रमंडल खेलों के लिए इस बार जो पदक तैयार किए गए हैं, उन पर ब्रेल लिपि अंकित है, जिससे दृष्टिबाधित खिलाड़ी भी इसमें निहित संदेश को समझ सकते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में ऐसा पहली बार किया गया है। यह ग्लास्गो में चल रहे खेलों में सभी को समान भाव से देखने की योजना से जुड़ा है। राष्ट्रमंडल खेलों में 10 प्रमुख खेल और छह पैरा खेल में कुल 215 स्वर्ण पदक दांव पर लगे होंगे। इनमें पैरा खेलों में रिकॉर्ड 47 स्वर्ण पदक भी शामिल हैं।

प्रत्येक मेजबान शहर पदकों पर अपनी छाप छोड़ता है, लेकिन ग्लास्गो खेलों के पदकों का डिज़ाइन आम तौर पर चलन में रहने वाले गोलाकार आकार से अलग है। पदकों को शहर के प्रतीक चिन्ह से प्रेरित होकर त्रिकोण रूप दिया गया है। पदक पर बने प्रारूप ग्लासगो के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक फिनिस्टन क्रेन से प्रेरित हैं, जो स्कॉटलैंड के जहाज निर्माण के अतीत की याद दिलाता है। इसकी बनावट टार्टन से प्रेरित है, जो स्कॉटलैंड से करीब से जुड़ा एक प्रतीक है। पदक पर बने तीन स्तर पोडियम की तीन सीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस पदकों का डिजाइन मिलित्सा मिलेंकोवा ने तैयार किया था। मिलेंकोवा का जन्म बुल्गारिया में हुआ था और अब वह ग्लास्गो स्कूल ऑफ आर्ट में आर्टिस्ट हैं। मिलेंकोवा ने कहा, ''मैं चाहती थी कि यह पदक राष्ट्रमंडल खेलों के पदकों में एक विशिष्ट स्थान हासिल करें।'' उन्होंने कहा, ''जब मैं पदकों के डिजाइन के बारे में सोच रही थी तो मैं ग्लासगो को एक आकार में समेटना चाहती थी। मैं राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह से प्रभावित थी और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इन्हें विशिष्ट आकार दिया।'' मिलेंकोवा ने कहा कि ग्लासगो और स्कॉटलैंड से उनके संबंधों के कारण फिनिस्टन क्रेन और टार्टन को शामिल करना स्वाभाविक था।

उन्होंने कहा, ''जब मैंने फिनिस्टन क्रेन और उससे बनी आकृतियों का उपयोग किया तो मैंने पाया कि यह मुझे टार्टन की याद दिलाता है। मैं इसे भी शामिल करना चाहती थी क्योंकि यह स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक है। पदकों पर पहली बार ब्रेल लिपि अंकित की गई है।''

खुद की एयरलाइंस शुरू नहीं करेगा अडाणी ग्रुप

एजेंसी, नई दिल्ली। अडानी ग्रुप ने उन खबरों का खंडन किया जिनमें कहा गया था कि वह ग्रुप एयरलाइन शुरू करने की योजना बना रहा है। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा कि एयरलाइन बिजनेस में उतरने पर विचार करने वाली खबरें पूरी तरह से बेबुनियाद और तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। कंपनी ने यह भी कहा कि वह एयरलाइन बिजनेस में प्रवेश करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

हाल में आई खबरों में दावा किया गया था कि अडानी ग्रुप एयरलाइन शुरू कर सकता है और इसके लिए उसने सरकार से नियमों में बदलाव करने का अनुरोध किया है। यह नियम दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट के ऑपरेटरों को किसी शेड्यूल्ड एयरलाइन में 10% से अधिक हिस्सेदारी रखने से रोकता है। अडानी ग्रुप देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर है। माना जा रहा था कि सरकार एयर इंडिया और इंडिगो के दबदबे को खत्म करने के लिए यह नियम बदलने पर विचार कर रही है।

नेपाल आने वाले ला सकेंगे 5,000 डॉलर तक विदेशी मुद्रा

एजेंसी, काठमांडू

भारतीयों के लिए 25 हजार रुपए की सीमा तय

नेपाल आने और नेपाल से बाहर जाने वाले व्यक्ति अब 5,000 अमेरिकी डॉलर तक की विदेशी मुद्रा नकदी के रूप में ला और ले जा सकेंगे। नेपाल में नकदी विदेशी मुद्रा लाने और बाहर ले जाने के संबंध में यह व्यवस्था 'विदेशी विनिमय अधिनियम' और 'संपत्ति शुद्धीकरण (मनी लॉन्ड्रिंग) निवारण अधिनियम' के प्रावधानों के तहत की गई है।

नकदी विदेशी मुद्रा के संदर्भ में नेपाल राष्ट्र बैंक ने 16 जुलाई, 2018 और 9 अप्रैल, 2019 को सूचना जारी कर यह सीमा तय की थी। केंद्रीय बैंक ने फिर से सूचना जारी करते हुए नेपाली और भारतीय नागरिकों के लिए भी 25 हजार भारतीय रुपए की सीमा बरकरार रखी है। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार नेपाली या विदेशी नागरिक 5,000 अमेरिकी डॉलर तक की नकदी विदेशी मुद्रा (और उन अन्य विदेशी मुद्राओं के मामले में भी जिनकी विनिमय दर राष्ट्र बैंक द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है, उसके बराबर राशि) बिना किसी सीमा शुल्क (कस्टम) घोषणा के नेपाल ला सकते हैं।

केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि इससे अधिक राशि होने पर सीमा शुल्क घोषणा पत्र भरना और उसे सत्यापित कराना अनिवार्य है। नेपाल राजपत्र में प्रकाशित सूचना के अनुसार कोई भी व्यक्ति 9 नवंबर, 2016 से पहले प्रचलन में रहे 500 और 1000 रुपए के भारतीय नोटों का लेनदेन नहीं कर सकता है। केंद्रीय बैंक ने व्यवस्था की है कि नेपाली या भारतीय नागरिक प्रचलित नियमों के अनुसार 9 नवंबर, 2016 के बाद जारी और प्रचलन में आए 200 और 500 रुपये के भारतीय नोट प्रति व्यक्ति 25 हजार की सीमा तक ला, ले जा तथा विनिमय (एक्सचेंज) करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने बताया है कि नेपाली नागरिकों को भारत के अलावा किसी अन्य देश में भारतीय रुपए ले जाने या किसी अन्य देश से नेपाल में भारतीय रुपए लाने की अनुमति नहीं है।

नेपाल ने 2.23 लाख बेटिंग वेबसाइट और ऐप किए ब्लॉक

एजेंसी, काठमांडू

एनटीए ने अवैध सट्टेबाजी और वित्तीय कारोबार पर की बड़ी कार्रवाई

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण (एनटीए) ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और अवैध वित्तीय गतिविधियों से जुड़ी 2,23,568 वेबसाइट और मोबाइल ऐप को बंद कर दिया है। यह कार्रवाई सरकार की शासकीय सुधार संबंधी 100 कार्यसूची के तहत की गई।

सरकार के निर्देश के बाद संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बेटिंग ऐप और वेबसाइटों को 24 घंटे के भीतर ब्लॉक करने का आदेश दिया था। इसके बाद एनटीए ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) के सहयोग से बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की।

एनटीए के अनुसार, कई प्रतिबंधित वेबसाइटें नए नामों से दोबारा सक्रिय हो रही थीं। इसी को देखते हुए फीफा विश्व कप के दौरान विशेष अभियान चलाकर बड़ी संख्या में नए अवैध प्लेटफॉर्म बंद किए गए।

प्राधिकरण ने बताया कि संदिग्ध वेबसाइटों की पहचान के लिए 'थ्रेट इंटेलिजेंस टूल' और विशेष निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए अलग टीम भी तैनात की गई है।

एनटीए के अधिकारी ओमप्रकाश महतो ने कहा कि अवैध वेबसाइटों को लगातार नए डोमेन के साथ दोबारा शुरू करना बड़ी चुनौती है, इसलिए निगरानी और कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। प्राधिकरण ने नागरिकों से भी अवैध बेटिंग प्लेटफॉर्म की जानकारी साझा करने की अपील की है।

चांदी 2924 रुपए व सोना 1848 रुपए हुआ सस्ता

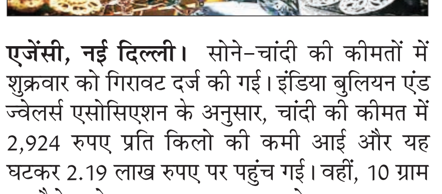

एजेंसी, नई दिल्ली। सोने-चांदी की कीमतों में शुक्रवार को गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार, चांदी की कीमत में 2,924 रुपए प्रति किलो की कमी आई और यह घटकर 2.19 लाख रुपए पर पहुंच गई। वहीं, 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,848 रुपए सस्ता होकर 1.42 लाख रुपए रह गया। एक दिन पहले चांदी 2.22 लाख रुपए और सोना 1.44 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। इस साल दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। 31 दिसंबर 2025 को सोने का भाव 1.33 लाख रुपए था, जो 29 जनवरी को बढ़कर 1.76 लाख रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। इसके बाद से सोना करीब 34 हजार रुपए तक गिर चुका है। इसी तरह चांदी 31 दिसंबर 2025 को 2.30 लाख रुपए प्रति किलो थी, जो 29 जनवरी को 3.86 लाख रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई थी। अब तक इसमें करीब 1.67 लाख रुपए की गिरावट आ चुकी है।

सरकार ने पीएलआई व पार्क योजनाओं के जरिए बढ़ाया निवेश

मेडिकल डिवाइस क्षेत्र को 476 करोड़ का बूस्ट : नड्डा

एजेंसी, नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने मेडिकल डिवाइस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) और मेडिकल डिवाइस पार्क योजना के तहत अब तक 476.44 करोड़ रुपए जारी किए हैं। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को लोकसभा में यह जानकारी दी।

नड्डा ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 तक मेडिकल डिवाइस पीएलआई योजना के तहत 266.64 करोड़ रुपए और मेडिकल डिवाइस पार्क योजना के तहत 209.80 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इनमें से पार्क योजना की 177.98 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग भी हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य आयात पर निर्भरता घटाकर मेडिकल डिवाइसों के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना है। मेडिकल डिवाइस उद्योग सुदृढ़ीकरण योजना (एसएमडीआई) के तहत 101.50 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं और 88.67 करोड़ रुपए की साझा सुविधा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 20.62 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।

3,420 करोड़ रुपए की पीएलआई योजना के तहत अब तक 27 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जिनमें 14 एमएसएमई शामिल हैं। कंपनियां 1,153.07 करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी हैं और देश में एमआरआई, सीटी स्कैनर, लिनियर एक्सेलेरेटर, अल्ट्रासाउंड, हार्ट वाल्व और स्टेंट जैसे अत्याधुनिक उपकरणों का उत्पादन शुरू हो गया है।

300 करोड़ रुपए की मेडिकल डिवाइस पार्क योजना के तहत नोएडा, उज्जैन और कांचीपुरम में पार्क विकसित किए जा रहे हैं। इन पार्कों में परीक्षण, स्टरलाइजेशन, वेयरहाउस और प्रोटोटाइपिंग जैसी साझा सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।

सेंसेक्स 331 अंक टूटा निफ्टी 23,767 पर बंद

एजेंसी, मुंबई। भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 331 अंक टूटकर 76,059 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी में 102 अंकों की गिरावट रही और यह 23,767 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में ऑटो, मेटल और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। निवेशकों में वैश्विक बाजारों के संकेतों और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव को लेकर सतर्कता बनी हुई है।

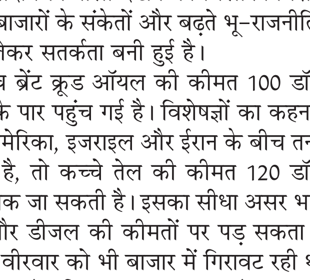

इस बीच ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव और बढ़ता है, तो कच्चे तेल की कीमत 120 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकती है। इसका सीधा असर भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है। इससे पहले वीरवार को भी बाजार में गिरावट रही थी। सेंसेक्स 364 अंक गिरकर 76,391 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 127 अंक फिसलकर 23,870 के स्तर पर रहा था।